PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: https://t.me/patrioticIAS

14_04_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography

1. **Mahad Satyagraha (1927)**
   महाड़ सत्याग्रह (1927)
2. **Kerala Temple Opens Sacred Space to All Sections**
   केरल के मंदिर ने सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल के द्वार खोले
3. **During Caste Census in Karnataka, Some Desisted from Giving Details, Some Did Not Know Their Caste**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

कर्नाटक में जातिगत जनगणना के दौरान कुछ लोगों ने जानकारी देने से इनकार किया, कुछ अपनी जाति नहीं जानते थे

4. Chaityabhoomi, Deekshabhoomi Ready for Ambedkar Jayanti

अंबेडकर जयंती के लिए चैत्यभूमि, दीक्षाभूमि तैयार

Mahad Satyagraha (1927)

महाड़ सत्याग्रह (1927)

- The **Mahad Satyagraha**, also known as **Chavdar Tale Satyagraha**, was a **pivotal movement** led by **Dr. B.R. Ambedkar** to challenge **caste-based discrimination** in India.
  महाड़ सत्याग्रह, जिसे **छावदार ताल सत्याग्रह** भी कहा जाता है, **डॉ. भीमराव अंबेडकर** द्वारा भारत में **जातिगत भेदभाव** को चुनौती देने के लिए शुरू किया गया एक **महत्वपूर्ण आंदोलन** था।
- It focused on securing the **right of Dalits** to access the **Chavdar Tank** in **Mahad, Maharashtra**, which was **traditionally denied** to them.
  यह आंदोलन **महाराष्ट्र के महाड़** में **छावदार तालाब** तक **दलितों को पहुंच दिलाने** पर केंद्रित था, जिसे उन्हें **परंपरागत रूप से वर्जित** किया गया था।
- On **20 March 1927**, **Ambedkar** and his followers drank water from the tank, asserting their **right to access public water sources**.
  20 मार्च 1927 को **अंबेडकर** और उनके अनुयायियों ने तालाब से पानी पिया, और **सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच का अधिकार** जताया।
- This act became a **symbolic protest** against **untouchability** and was a **significant milestone** in the fight for **Dalit rights**.
  यह कार्य **अछूतपन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध** बन गया और **दलित अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर** साबित हुआ।
- The day, **20 March**, is observed as **Social Empowerment Day** in India.
  यह दिन, **20 मार्च**, भारत में **सामाजिक सशक्तिकरण दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Savitribai Phule
सावित्रीबाई फुले

- Savitribai Phule was born on 3 January 1831 in Naigaon, Satara district, Maharashtra.
  सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सातारा ज़िला, महाराष्ट्र में हुआ था।

Initial Education
प्रारंभिक शिक्षा

• At the time of her marriage, Savitribai was illiterate.
शादी के समय सावित्रीबाई निरक्षर थीं।

• Her husband, Jyotirao Phule, educated her at home, along with his cousin sister, Sagunabai Shirsagar.
उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर ही अपनी चचेरी बहन सगुनाबाई शिरसागर के साथ पढ़ाया।

• She later pursued formal education under the guidance of Sakharam Yeshwant Paranjpe and Keshav Shivram Bhavalkar.
बाद में उन्होंने सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर के मार्गदर्शन में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की।

Educational Pursuits and Teaching Career
शैक्षिक प्रयास और शिक्षण करियर

• Savitribai enrolled in two teacher-training programs:
सावित्रीबाई ने दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया:

- One at an institution run by American missionary Cynthia Farrar in Ahmednagar.
  एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फैरार द्वारा संचालित संस्था में।
- Another at a Normal School in Pune.
  दूसरा पुणे में एक नॉर्मल स्कूल में।

• Given her training, Savitribai is recognized as India's first female teacher and headmistress.
इस प्रशिक्षण के आधार पर सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका के रूप में माना जाता है।

• She began teaching girls at Maharwada in Pune after completing her training.
उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया।

Establishment of the First Girls' School
पहले बालिका विद्यालय की स्थापना

PATRIOTIC IAS

• In 1848, Savitribai and Jyotirao Phule, along with Sagunabai, established the first school for girls at Bhidewada, the residence of Tatya Saheb Bhide, in Pune.
1848 में सावित्रीबाई, ज्योतिराव फुले और सगुनाबाई ने मिलकर पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास भिडेवाड़ा में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया।

• The school's curriculum included traditional subjects like mathematics, science, and social studies.
विद्यालय का पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन जैसे पारंपरिक विषयों को शामिल करता था।

• By 1851, the Phules were running three schools for girls in Pune, with a combined enrollment of approximately 150 students.
1851 तक फुले दंपति पुणे में तीन बालिका विद्यालय चला रहे थे, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 150 छात्राएं पढ़ रही थीं।

Challenges and Societal Resistance
चुनौतियाँ और सामाजिक विरोध

• Savitribai Phule encountered significant hostility, including verbal abuse and physical attacks, for her efforts to educate girls.
लड़कियों को शिक्षित करने के उनके प्रयासों के कारण सावित्रीबाई को जबरदस्त विरोध, शारीरिक हमले और शाब्दिक अपमान का सामना करना पड़ा।

• She often carried an extra sari to school in anticipation of being assaulted with stones or dung.
वह अक्सर स्कूल एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थीं क्योंकि उन पर पत्थर या गोबर फेंका जाता था।

• In 1849, due to societal pressure, Jyotirao's father expelled the couple from his home.
1849 में सामाजिक दबाव के कारण ज्योतिराव के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया।

• They found refuge with Mian Usman Sheikh, where they continued their educational work.
उन्होंने मियां उस्मान शेख के यहां आश्रय लिया, जहां उन्होंने अपना शैक्षिक कार्य जारी रखा।

Collaboration with Fatima Sheikh
फातिमा शेख के साथ सहयोग

• Pioneering Muslim Woman Educator: Fatima Sheikh, regarded as India's first Muslim woman teacher, collaborated closely with the Phules. She co-founded the initial girls' school and played a pivotal role in its operations.
• भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका मानी जाने वाली फातिमा शेख ने फुले दंपत्ति के साथ मिलकर कार्य किया। उन्होंने प्रारंभिक बालिका विद्यालय की सह-स्थापना की और इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• Teacher Training and Leadership: Both Savitribai and Fatima received teacher training under American missionary Cynthia Farrar. Fatima later assumed leadership roles, managing schools and advocating for girls' education.
• सावित्रीबाई और फातिमा दोनों ने अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फैरार के मार्गदर्शन में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में फातिमा ने नेतृत्व की भूमिका निभाई, स्कूलों का संचालन किया और बालिका शिक्षा का समर्थन किया।

PATRIOTIC IAS

Establishment of Educational Trusts
शैक्षिक न्यासों की स्थापना

• Formation of Trusts: In the 1850s, the Phules established two educational trusts – the Native Male School, Pune, and the Society for Promoting the Education of Mahar, Mangs, etc. These aimed to institutionalize education for marginalized communities.
• 1850 के दशक में फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक न्यासों की स्थापना की – नेटिव मेल स्कूल, पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मांग्स आदि। इनका उद्देश्य वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को संस्थागत बनाना था।

• Legacy and Continuation: These trusts expanded the reach of schools and ensured sustainability of educational initiatives for the underprivileged.
• इन न्यासों ने विद्यालयों के विस्तार को संभव बनाया और वंचित वर्गों के लिए शैक्षिक पहलों की निरंतरता सुनिश्चित की।

Balhatya Pratibandhak Griha (1863)
बालहत्या प्रतिबंधक गृह (1863)

• Infanticide Prevention Center: In 1863, the Phules, along with Sadashiv Ballal Govande, established the Balhatya Pratibandhak Griha in Pune. This center provided shelter and support for pregnant widows, aiming to prevent infanticide.
• 1863 में फुले दंपत्ति ने सदाशिव बल्लाल गोवांडे के साथ मिलकर पुणे में बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। यह केंद्र गर्भवती विधवाओं को आश्रय और सहायता प्रदान करता था और शिशु हत्या को रोकने का प्रयास करता था।

• Services Offered: The center offered confidential childbirth services and care for abandoned infants, addressing a critical social issue of the time.
• इस केंद्र में गोपनीय प्रसव सेवाएं और परित्यक्त शिशुओं की देखभाल प्रदान की जाती थी, जो उस समय की एक गंभीर सामाजिक समस्या थी।

Rettamalai Srinivasan
रेट्टामलाई श्रीनिवासन

• Rettamalai Srinivasan was born on 7 July 1859 in Kozhiyalam village, Maduranthagam Taluk, Kancheepuram District, in the Madras Presidency (now Tamil Nadu).
• रेट्टामलाई श्रीनिवासन का जन्म 7 जुलाई 1859 को कोझियालम गांव, मदुरानथगम तालुक, कांचीपुरम जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी (अब तमिलनाडु) में हुआ था।

• He hailed from the Paraiyar community, a Scheduled Caste.
• वह परैयार समुदाय से थे, जो कि एक अनुसूचित जाति है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

• Despite socio-economic challenges, he became the first graduate among the Scheduled Castes, earning a Bachelor of Law from Coimbatore Government Arts College.

• सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, वह अनुसूचित जातियों में पहले स्नातक बने और उन्होंने कोयंबटूर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से कानून में स्नातक (Bachelor of Law) की डिग्री प्राप्त की।

Professional and Activist Endeavors

व्यावसायिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में योगदान

• Srinivasan worked as an accountant in Ooty, where he became involved in Dalit political activism.

• श्रीनिवासन ने ऊटी में एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया, जहां वह दलित राजनीतिक सक्रियता से जुड़ गए।

• While working as a translator in a South African court, he met Mahatma Gandhi, who was practicing law there.

• उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत में अनुवादक के रूप में काम करते हुए महात्मा गांधी से मुलाकात की, जो वहां वकालत कर रहे थे।

• Srinivasan is credited with influencing Gandhi to sign his name in Tamil as "Mo.Ka. Gandhi".

• गांधी को तमिल में "मो.का. गांधी" के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करने का श्रेय श्रीनिवासन को दिया जाता है।

Founding of Organizations and Publications

संस्थाओं और प्रकाशनों की स्थापना

• In 1891, he established the Paraiyar Mahajana Sabha, which was later renamed the Adi Dravida Mahajana Sabha in 1893.

• उन्होंने 1891 में परैयार महाजन सभा की स्थापना की, जिसे 1893 में आदि द्रविड़ महाजन सभा नाम दिया गया।

• In October 1893, he founded the Tamil newspaper 'Paraiyan', aimed at highlighting the issues faced by the Depressed Classes.

• उन्होंने अक्टूबर 1893 में तमिल अखबार 'परैयन' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों की समस्याओं को उजागर करना था।

• The newspaper faced challenges, including a legal case in 1896, where Srinivasan was fined ₹100 for his writings.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

• इस अखबार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें एक 1896 का कानूनी मामला भी शामिल था, जिसमें श्रीनिवासन पर उनके लेखों के लिए ₹100 का जुर्माना लगाया गया था।

Participation in the Round Table Conferences (1930 & 1931)
राउंड टेबल सम्मेलनों (1930 और 1931) में भागीदारी

• Srinivasan represented the Paraiyars in the First (1930) and Second (1931) Round Table Conferences held in London, alongside Dr. B. R. Ambedkar.

• श्रीनिवासन ने परैयार समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले (1930) और दूसरे (1931) राउंड टेबल सम्मेलन में लंदन में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के साथ किया।

• At these conferences, he advocated for separate electorates and political representation for the Depressed Classes, emphasizing their distinct identity and rights within the Indian polity.

• इन सम्मेलनों में उन्होंने वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की, और भारतीय राजनीति में उनकी अलग पहचान और अधिकारों को रेखांकित किया।

• In 1932, Rettamalai Srinivasan, along with Dr. B. R. Ambedkar and M. C. Rajah, briefly joined the board of the Servants of Untouchables Society, established by Mahatma Gandhi to work for the upliftment of the Depressed Classes.

1932 में, रेट्टामलाई श्रीनिवासन ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर और एम. सी. राजा के साथ मिलकर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अछूतों के सेवक समाज के बोर्ड में संक्षिप्त रूप से शामिल हुए, जिसका उद्देश्य दबे-कुचले वर्गों का उत्थान करना था।

• Despite this collaboration, Srinivasan had ideological differences with Gandhi, particularly on the issue of separate electorates for the Depressed Classes.

इस सहयोग के बावजूद, श्रीनिवासन और गांधी के बीच विशेष रूप से दबे-कुचले वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों के मुद्दे पर वैचारिक मतभेद थे।

Political Involvement and Contributions
राजनीतिक भागीदारी और योगदान

· Srinivasan served as a member of the Madras Legislative Council from 1923 to 1929, influencing policies to safeguard the interests of the Depressed Classes.

श्रीनिवासन ने 1923 से 1929 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य के रूप में सेवा की, जहां उन्होंने दबे-कुचले वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नीतियों को प्रभावित किया।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Formation of the Madras Province Scheduled Castes' Party (1936)
मद्रास प्रांत अनुसूचित जाति पार्टी का गठन (1936)

- In 1936, Srinivasan established the Madras Province Scheduled Castes' Party to politically mobilize the Depressed Classes in the region.
1936 में, श्रीनिवासन ने क्षेत्र में दबे-कुचले वर्गों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए मद्रास प्रांत अनुसूचित जाति पार्टी की स्थापना की।

- In recognition of his services to the Depressed Classes, the British Government conferred upon Srinivasan the titles of Rao Sahib in 1926, Rao Bahadur in 1930, and Diwan Bahadur in 1936.
दबे-कुचले वर्गों के प्रति उनकी सेवाओं की मान्यता में, ब्रिटिश सरकार ने श्रीनिवासन को 1926 में राव साहिब, 1930 में राव बहादुर, और 1936 में दीवान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान कीं।

- In 1940, he was honored as 'Dravida Mani' in a ceremony presided over by C. Rajagopalachari.
1940 में, उन्हें सी. राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में 'द्रविड़ मणि' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

Ideological Stance on Religion and Identity
धर्म और पहचान पर वैचारिक दृष्टिकोण

- While Ambedkar declared his intent to renounce Hinduism in 1935, stating, "I was born as a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu, Srinivasan maintained that the Depressed Classes were not part of the Hindu fold, asserting, Depressed Classes are not in the Hindu fold.
1935 में, अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की अपनी मंशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, मैं आपको गंभीरता से आश्वस्त करता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा," जबकि श्रीनिवासन ने यह मानते हुए कहा कि दबे-कुचले वर्ग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हैं।

- They are full-blooded Dravidian in race.
वे पूर्ण रक्त वाले द्रविड़ जाति के हैं।

Ayyankali
अय्यंकाली

- Ayyankali was born on 28 August 1863 in Venganoor, a village in the princely state of Travancore (present-day Thiruvananthapuram, Kerala).

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

अय्यंकाली का जन्म 28 अगस्त 1863 को त्रावणकोर की एक रियासत (वर्तमान तिरुवनंतपुरम, केरल) के वेंगनूर गांव में हुआ था।

- He was the eldest of eight children in a family belonging to the Pulayar community, which was considered 'untouchable' and faced severe social discrimination.
  वह पुलायर समुदाय से थे और आठ बच्चों में सबसे बड़े थे। यह समुदाय अस्पृश्य माना जाता था और गंभीर सामाजिक भेदभाव का सामना करता था।

Socio-economic Status
सामाजिक-आर्थिक स्थिति

- Despite the caste-based restrictions, Ayyankali's family owned 5 acres of land, a rare privilege for Pulayars, granted by the landlord whom his father served as an 'Adiyalan' (bonded laborer).
  जातिगत प्रतिबंधों के बावजूद, अय्यंकाली के परिवार के पास 5 एकड़ भूमि थी, जो पुलायरों के लिए एक दुर्लभ विशेषाधिकार था। यह भूमि उन्हें उस जमींदार द्वारा दी गई थी, जिसकी सेवा में उनके पिता 'अडियालन' (बंधुआ मज़दूर) के रूप में थे।

Social Conditions in Travancore
त्रावणकोर में सामाजिक स्थिति

- During Ayyankali's time, the Pulayar community was subjected to systemic oppression:
  अय्यंकाली के समय, पुलायर समुदाय को संस्थागत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा:
- Denied access to public roads, temples, and educational institutions.
  उन्हें सार्वजनिक सड़कों, मंदिरों, और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
- Required to maintain a significant distance from upper-caste individuals.
  उन्हें उच्च जातियों के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया।
- Prohibited from wearing certain types of clothing or ornaments.
  वे विशेष प्रकार के वस्त्रों या आभूषणों को पहनने से वंचित थे।
- Compelled to work as bonded laborers without rights to land ownership.
  वे बंधुआ मज़दूरों के रूप में कार्य करने के लिए विवश थे और उन्हें भूमि स्वामित्व का अधिकार नहीं था।

Path to Social Reform
सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयास

- Cultural Resistance: Ayyankali began his activism by organizing folk music and dance gatherings that subtly protested against caste oppression. These gatherings fostered a sense of unity and resistance among the Pulayars.
  सांस्कृतिक प्रतिरोध: अय्यंकाली ने लोक संगीत और नृत्य सभाओं के माध्यम से जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रियाएं शुरू कीं। इन आयोजनों से पुलायर समुदाय में एकता और प्रतिरोध की भावना विकसित हुई।
- Formation of Advocacy Groups: He led groups that directly challenged upper-caste dominance, sometimes resulting in confrontations. His leadership earned him titles like 'Urpillai' and 'Moothapullai',

PATRIOTIC IAS

meaning 'Leader of the Land' or 'Elder Leader'.
अधिकार समूहों का गठन: उन्होंने ऐसे समूहों का नेतृत्व किया जिन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी, जिससे कभी-कभी टकराव की स्थिति बनी। उनके नेतृत्व के लिए उन्हें 'उरपिल्लै' और 'मूथपिल्लै' जैसे उपाधियाँ मिलीं, जिनका अर्थ होता है 'भूमि का नेता' या 'वरिष्ठ नेता'।

Freedom of Movement and Social Defiance
आंदोलन की स्वतंत्रता और सामाजिक विरोध

- In 1893, Ayyankali boldly challenged caste restrictions by riding a bullock cart (locally known as Villuvandi) through public roads in Travancore, Kerala.
  1893 में, अय्यनकली ने त्रावणकोर, केरल में सार्वजनिक सड़कों पर बैलगाड़ी (स्थानीय रूप से 'विल्लुवंडी' के रूप में जानी जाती है) चलाकर जातिगत प्रतिबंधों को साहसपूर्वक चुनौती दी।
- At that time, such roads were reserved for upper castes, and lower castes like the Pulayars were prohibited from using them.
  उस समय, ऐसी सड़कों को उच्च जातियों के लिए आरक्षित किया गया था, और पुलायर जैसी निम्न जातियों को उनका उपयोग करने से मना किया गया था।
- This act was a significant protest against caste-based discrimination and asserted the right of the oppressed to access public spaces.
  यह कार्य जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था और उत्पीड़ितों के सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के अधिकार को स्थापित करता था।

Education Reforms and the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS)
शिक्षा सुधार और साधु जन परिपालना संघ (एसजेपीएस)

- Recognizing the importance of education for social upliftment, Ayyankali founded the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS) in 1907.
  सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए, अय्यनकली ने 1907 में साधु जन परिपालना संघ (एसजेपीएस) की स्थापना की।
- The organization aimed to promote education among the Dalits and worked towards establishing schools for them.
  इस संगठन का उद्देश्य दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना था और उनके लिए स्कूल स्थापित करने की दिशा में काम करना था।
- Despite government orders in 1907 to admit children from "untouchable" castes into schools, local officials often resisted.
  1907 में "अस्पृश्य" जातियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने के सरकारी आदेशों के बावजूद, स्थानीय अधिकारियों ने अक्सर इसका विरोध किया।
- In response, Ayyankali organized a strike of agricultural laborers, marking one of the first labor strikes in Kerala, to demand educational rights for the oppressed.
  इसके जवाब में, अय्यनकली ने केरल में उत्पीड़ितों के लिए शैक्षिक अधिकारों की मांग करते हुए कृषि श्रमिकों की हड़ताल का आयोजन किया, जो राज्य की पहली श्रमिक हड़तालों में से एक थी।

Representation in the Sree Moolam Popular Assembly
श्री मूलम लोकप्रिय सभा में प्रतिनिधित्व

PATRIOTIC IAS

- In 1910, Ayyankali became a member of the Sree Moolam Popular Assembly (SMPA), the legislative assembly of Travancore.
  1910 में, अय्यनकली त्रावणकोर की विधान सभा, श्री मूलम लोकप्रिय सभा (एसएमपीए) के सदस्य बने।
- His inclusion in the assembly marked a significant step towards political representation for the Dalits and provided a platform to advocate for their rights at a legislative level.
  सभा में उनका शामिल होना दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उन्हें विधायी स्तर पर अपने अधिकारों की वकालत करने का मंच प्रदान किया।

Palm Sunday
पाम संडे

- **Palm Sunday commemorates** Jesus Christ's **triumphant entry into Jerusalem**, an event mentioned in **all four Gospels** (*Matthew, Mark, Luke, and John*).
  पाम संडे यीशु मसीह के **विजयपूर्वक यरूशलेम में प्रवेश** को स्मरण करता है, जिसे **चारों सुसमाचारों** (*मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना*) में वर्णित किया गया है।
- It occurs on the **Sunday before Easter**.
  यह **ईस्टर से पहले का रविवार** होता है।

According to the **New Testament**, when Jesus entered Jerusalem **riding a donkey**, crowds greeted Him by:
नए नियम के अनुसार, जब यीशु **गधे पर सवार होकर** यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो भीड़ उनका इस प्रकार स्वागत करती है:

- **Laying down** *palm branches* and *cloaks* on the road,
  सड़क पर **ताड़ के पत्ते** और **वस्त्र** बिछाना
- **Shouting**: "**Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord!**"
  यह कहते हुए: "**होशाना! धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है!**"
- This act symbolized **victory**, **peace**, and recognition of Jesus as the **Messiah**.
  यह कार्य **विजय**, **शांति**, और यीशु को **मसीहा के रूप में पहचानने** का प्रतीक था।

Why Palms?
ताड़ के पत्ते क्यों?

PATRIOTIC IAS

- In **ancient Jewish tradition**, **palm branches** were a symbol of **victory** and **triumph**.
  प्राचीन यहूदी परंपरा में, **ताड़ के पत्ते विजय** और **सफलता** का प्रतीक थे।

The use of palms in welcoming Jesus reflected:
यीशु के स्वागत में **ताड़ के पत्तों** के उपयोग से यह झलकता है:

• **Joy**
• **आनंद**

• **Hope for deliverance**
• **उद्धार की आशा**

• **Celebration of the prophesied King**
• **भविष्यवाणी किए गए राजा का स्वागत**

Significance in Christianity
ईसाई धर्म में महत्व

Palm Sunday initiates Holy Week, which includes:
पाम संडे से पवित्र सप्ताह (Holy Week) की शुरुआत होती है, जिसमें शामिल हैं:

• **Maundy Thursday** (*Last Supper*)
• **मौंडी थर्सडे** (*अंतिम भोज*)

• **Good Friday** (*Crucifixion*)
• **गुड फ्राइडे** (*क्रूस पर चढ़ाया जाना*)

• **Easter Sunday** (*Resurrection*)
• **ईस्टर संडे** (*पुनरुत्थान*)

It reminds Christians of:
यह ईसाइयों को यह स्मरण कराता है:

• The **humility** of Christ
• मसीह की **विनम्रता**

• His **sacrifice**
• उनका **बलिदान**

PATRIOTIC IAS

- The **fulfillment of prophecy** *(Zechariah 9:9)*
- **भविष्यवाणी की पूर्ति** *(जकर्याह 9:9)*

Kerala temple opens sacred space to all sections

Previously restricted to specific communities, the inner quarter of the centuries-old Pilicode Rayaramangalam temple in Kasaragod district has been opened to all sections of society for the first time following a reformist campaign

GS Paper I: A&C

The Hindu Bureau
KASARAGOD

In a landmark move, devotees from all communities entered the *nalambalam* – the sacred inner quarter – of the centuries-old Pilicode Rayaramangalam temple in Kasaragod district of Kerala for the first time, ending restrictions based on caste.

Previously restricted to specific communities, the sacred space in the temple managed by the Malabar Devaswom Board was opened to all communities following a campaign led by a reformist organisation.

Evolving norms: Devotees come out of the centuries-old Pilicode Rayaramangalam temple in Kasaragod. SPECIAL ARRANGEMENT

Around 8 a.m. on Sunday, a day before the Vishu festival, a group of 16 devotees stepped into the inner quarter of the temple. Others who had gathered to witness the moment followed, marking a significant shift in the temple's practices.

K.V. Rajesh, a member of the group, said that only people from the Brahmin, Marar, and Warrier communities were allowed to enter the space earlier. Maniyani, Nair, Vaniya and a few other communities were allowed entry during the festival period.

He said the initiative spearheaded by the reformist body Pilicode Ninav Purush Swayaamsahaya Sangham, a men's self-help group, gained momentum with its resolution advocating for universal entry rights. This was followed by the formation of the Janakiya Samithi, a people's committee comprising socio-cultural and political organisations, which petitioned the *Tantri* (head priest), State Devaswom Minister V.N. Vasavan, and the temple administrative committee. While the *Tantri* had responded that worshippers could pray near the inner quarter without affecting rituals, access into it came after the festival ceremonies concluded, he added.

The Janakiya Samithi confirmed that the inner quarter will remain open to all devotees in the coming days, reinforcing that the change was not symbolic, but permanent.

Sunday's event is being hailed as a moral and cultural victory, a sign that age-old rituals must evolve with time to reflect equality and inclusion.

Kerala Temple Opens Sacred Space to All Sections

केरल के मंदिर ने सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल के द्वार खोले

Basic Explanation with Questions and Answers

मूल जानकारी के साथ प्रश्न और उत्तर

- **What happened at the Pilicode Rayaramangalam temple?**
  पिलिकोड रायारमंगलम मंदिर में क्या हुआ?
  The **inner quarter (nalambalam)** of the **centuries-old** Pilicode Rayaramangalam temple in **Kasaragod, Kerala**, was opened to **all communities** for the **first time**, ending **caste-based restrictions**.
  केरल के कासरगोड जिले में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने पिलिकोड रायारमंगलम मंदिर के अंदरूनी हिस्से (नालंबलम) को पहली बार **सभी समुदायों** के लिए खोला गया, जिससे **जातिगत प्रतिबंध** समाप्त हो गए।

Who managed this temple?

इस मंदिर का प्रबंधन कौन करता है?

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

The temple is managed by the **Malabar Devaswom Board**.
इस मंदिर का प्रबंधन **मलाबार देवास्वम बोर्ड** करता है।

Who was allowed to enter earlier?
पहले किन लोगों को प्रवेश की अनुमति थी?

Earlier, only people from the **Brahmin**, **Marar**, and **Warrier** communities were allowed inside. During festivals, some from **Maniyani**, **Nair**, and **Vaniya** communities were also allowed.
पहले केवल **ब्राह्मण**, **मरार**, और **वारियर** समुदाय के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। त्योहारों के दौरान कुछ **मानियानी**, **नायर**, और **वणियार** समुदायों को भी अनुमति दी जाती थी।

What triggered this change?
इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई?

The change began with a **reformist campaign** led by a **self-help group** called **Pilicode Ninav Purush Swayaamsahaya Sangham**.
यह परिवर्तन **पिलिकोड निनव पुरुष स्वयं सहायता संघ** नामक एक **सुधारवादी संगठन** के नेतृत्व में शुरू हुए **अभियान** से हुआ।

What was the role of Janakiya Samithi?
जानकीया समिति की भूमिका क्या थी?

The **Janakiya Samithi**, a **people's committee** formed with **socio-cultural and political organisations**, petitioned the **Tantri (chief priest)**, the **State Devaswom Minister V.N. Vasavan**, and the **temple committee** for universal access.
जानकीया समिति, जो कि **सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों** की एक **जन समिति** है, ने **तंत्री (मुख्य पुजारी)**, **राज्य देवास्वम मंत्री वी.एन. वसावन**, और **मंदिर प्रशासनिक समिति** को **सर्वसामान्य प्रवेश** की मांग को लेकर याचिका दी।

When did the change happen?
यह बदलाव कब हुआ?

Around **8 a.m. on Sunday**, a group of **16 devotees** entered the sacred space — a day before the **Vishu festival**.
रविवार सुबह करीब 8 बजे, **विषु त्योहार से एक दिन पहले**, **16 भक्तों** का एक समूह मंदिर के **पवित्र स्थल** में प्रवेश किया।

Was this a one-time change?
क्या यह एक बार की अनुमति थी?

No, the **Janakiya Samithi confirmed** that the inner quarter will remain **open permanently** to **all devotees**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

नहीं, **जानकीया समिति ने पुष्टि की** कि मंदिर का अंदरूनी भाग अब **सभी श्रद्धालुओं के लिए स्थायी रूप से खुला रहेगा**

Why is this event considered important?

यह घटना क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

It is seen as a **moral and cultural victory**, showing that **age-old rituals** must change over time to reflect **equality** and **inclusion**.

इसे एक **नैतिक और सांस्कृतिक जीत** माना जा रहा है, जो दर्शाता है कि **पुरानी परंपराओं** को समय के साथ बदलना चाहिए ताकि वे **समानता** और **समावेशिता** को दर्शा सकें।

During caste census in Karnataka, some desisted from giving details, some did not know their caste

GS Paper I: Society

Sharath S. Srivatsa
BENGALURU

While the caste-wise population identified in the Socio-Economic and Educational Survey (caste census) conducted by the Karnataka State Commission for Backward Classes had led to a furore, a small percentage of the population had either refused to provide caste details during the census or did not know their caste to provide the details.

A total of 73,399 families, including 53,241 in urban areas, which accounted for about 2.53 lakh (including 1.12 lakh women), or about 0.425%, of the State population, refused to identify their caste during the enumeration, show data available in the survey report accepted by the Cabinet on Friday.

The full report is yet to be released by the government, and it will be discussed at a special Cabinet meeting on April 17.

As many as 35,845 families, including 27,535 living in urban areas, have stated that they do not belong to any caste or are 'caste-free'.

Their population is pegged at 1.34 lakh or about 0.225% of the State's enumerated population.

These data have emerged at a time when caste groups are lobbying to state that their numbers have reduced or the names of the castes have gone wrong.

As many as 5.98 crore people of about a projected population of 6.35 crore in Karnataka from about 1.35 crore households were covered under the survey conducted in 2015. The survey is being seen as an important document containing data set that would realign the political calculations as well as allow the government to recalibrate its focus on the populations that have continued to not receive the reservation benefits.

About 52,272 families, including 44,912 families in urban areas, have marked themselves under the "if at all does not know the caste" category, Their population is pegged at 1.94 lakh or about 0.324% of the total population. Castes and communities could not be identified for 3,755 persons belonging to 967 households in the State.

Commission sources said that those who did not reveal or did not have castes are not part of the final number calculated for enumeration.

"Some people did not know castes because of migration or due to nomadic nature. Some castes were not in the detailed list that we had drafted. Moreover, we cannot compel anyone to provide details," they said.

Fact sheet

Total projected population in 2015	6.35 crore
Total population covered	5.98 crore
People who refused to identify their castes	2.53 lakh
People who said they are 'caste-free'	1.34 lakh
People not knowing their caste	1.94 lakh
Castes and communities that could not be identified	3,755

During Caste Census in Karnataka, Some Desisted from Giving Details, Some Did Not Know Their Caste

कर्नाटक में जातिगत जनगणना के दौरान कुछ लोगों ने जानकारी देने से इनकार किया, कुछ अपनी जाति नहीं जानते थे

Caste details not shared or unknown by a small percentage
थोड़े प्रतिशत लोगों ने जाति की जानकारी नहीं दी या उन्हें जाति का ज्ञान नहीं था

- While the **caste-wise population** identified in the **Socio-Economic and Educational Survey** (caste census) created a **furore**, a **small percentage** of people either **refused to share caste details** or **did not know their caste**.
  सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) में **जाति-वार जनसंख्या** की पहचान से **विवाद** उत्पन्न हुआ, लेकिन **थोड़े प्रतिशत** लोगों ने या तो **जाति की जानकारी देने से इनकार किया** या **अपनी जाति के बारे में नहीं जानते थे**।
- **Total 73,399 families refused caste identification**
  कुल 73,399 परिवारों ने जाति पहचान से किया इनकार
- About **73,399 families**, including **53,241 from urban areas**, refused to provide their **caste** during enumeration. This accounts for about **2.53 lakh people** (including **1.12 lakh women**), which is **approximately 0.425%** of the State population.
  लगभग **73,399 परिवारों** ने, जिनमें **53,241 शहरी क्षेत्र** से थे, **गणना के दौरान जाति की जानकारी देने से इनकार** किया। यह लगभग **2.53 लाख लोगों** (जिसमें **1.12 लाख महिलाएं** शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करता है, जो **राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 0.425%** है।
- **Full report yet to be released**
  पूरी रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है
- The **full report** of the caste census is yet to be released by the **government**, and it will be discussed in a **special Cabinet meeting on April 17**.
  सरकार द्वारा जाति जनगणना की पूरी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है, और इसे **17 अप्रैल को विशेष कैबिनेट बैठक** में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
- **35,845 families identified themselves as caste-free**
  35,845 परिवारों ने खुद को जातिविहीन बताया
- About **35,845 families**, including **27,535 from urban areas**, stated that they either **do not belong to any caste** or are **caste-free**. Their population is estimated at **1.34 lakh**, around **0.225%** of the State's enumerated population.
  लगभग **35,845 परिवारों** ने, जिनमें से **27,535 शहरी क्षेत्र** से हैं, बताया कि वे या तो **किसी जाति से नहीं जुड़े हैं** या **जातिविहीन** हैं। इनकी जनसंख्या लगभग **1.34 लाख** आंकी गई है, जो **राज्य की कुल गिनी गई आबादी का लगभग 0.225%** है।
- **Data emerges amid caste group lobbying**
  जातीय समूहों के दबाव के बीच यह आंकड़े सामने आए
- This data comes at a time when **caste groups** are lobbying, claiming their **numbers have reduced** or that their **caste names were recorded incorrectly**.
  यह आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब **जातीय समूह** यह दावा कर रहे हैं कि **उनकी संख्या कम दिखाई गई है** या **उनकी जातियों के नाम गलत दर्ज हुए हैं**।
- **Survey covered 5.98 crore people from 1.35 crore households**
  सर्वेक्षण में 1.35 करोड़ घरों से 5.98 करोड़ लोगों को शामिल किया गया

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- The survey, conducted in **2015**, covered **5.98 crore people** out of a projected population of **6.35 crore**, from about **1.35 crore households**.

  2015 में कराए गए इस सर्वेक्षण में अनुमानित **6.35 करोड़ की जनसंख्या** में से **5.98 करोड़ लोग**, जो लगभग **1.35 करोड़ परिवारों** से हैं, शामिल किए गए।
- **Survey considered key for policy realignment**

  नीति पुनःसंरेखन के लिए सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है
- The caste survey is seen as an important document that can **realign political strategies** and allow the government to **refocus welfare efforts** on those **not receiving reservation benefits**.

  जाति सर्वेक्षण को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है, जो **राजनीतिक रणनीतियों को पुनः व्यवस्थित** कर सकता है और सरकार को उन वर्गों पर **कल्याणकारी योजनाएं केंद्रित करने** की सुविधा देगा जिन्हें **आरक्षण लाभ नहीं मिल रहे हैं**।
- **52,272 families didn't know their caste**

  52,272 परिवारों को अपनी जाति का ज्ञान नहीं था
- About **52,272 families**, including **44,912 from urban areas**, marked themselves under the **"don't know caste"** category. Their population is estimated at **1.94 lakh**, or about **0.324%** of the total population.

  लगभग **52,272 परिवारों**, जिनमें से **44,912 शहरी क्षेत्रों** से हैं, ने खुद को **"जाति नहीं जानते"** श्रेणी में चिह्नित किया। इनकी जनसंख्या लगभग **1.94 लाख** है, जो **कुल जनसंख्या का लगभग 0.324%** है।
- **Caste not identified for 3,755 persons**

  3,755 व्यक्तियों की जाति की पहचान नहीं हो सकी
- Caste details could not be identified for **3,755 persons** belonging to **967 households** in the State.

  राज्य के **967 परिवारों** के **3,755 व्यक्तियों** की जाति की पहचान नहीं हो सकी।
- **Reasons for missing caste details explained by Commission**

  आयोग द्वारा जाति जानकारी न देने के कारण बताए गए
- Commission sources explained that people did not reveal caste details due to **migration**, **nomadic lifestyle**, or because their **castes were not on the list**. They added, "We cannot compel anyone to give their caste."

  आयोग के सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों ने **प्रवास**, **घुमंतू जीवनशैली**, या उनके **जातियों का सूची में न**

होना जैसे कारणों से जाति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, "हम किसी को जाति बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।"

Chaityabhoomi in Dadar is closely connected to Dr. Ambedkar's life and legacy, and witness massive footfall. EMMANUAL YOGINI

Chaityabhoomi, Deekshabhoomi ready for Ambedkar Jayanti

GS Paper I: Prominent Personalities

Preparations are in full swing at Mumbai's Chaityabhoomi and Nagpur's Deekshabhoomi, ahead of Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary on Monday, with lakhs of followers expected to gather and pay homage to the architect of the Indian Constitution.

Authorities in both cities have ramped up security and civic arrangements, anticipating large crowds. Chaityabhoomi in Dadar and Deekshabhoomi in Nagpur are closely connected to Dr. Ambedkar's life and legacy and witness massive footfall every year on April 14.

Cultural programmes and public addresses are scheduled . Local administrations have appealed to visitors to cooperate with authorities to ensure a peaceful and respectful observance of the occasion.

Chaityabhoomi, Deekshabhoomi Ready for Ambedkar Jayanti

अंबेडकर जयंती के लिए चैत्यभूमि, दीक्षाभूमि तैयार

Preparations are in full swing at Mumbai's Chaityabhoomi and Nagpur's Deekshabhoomi ahead of Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary on Monday.

सोमवार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती से पहले मुंबई की चैत्यभूमि और नागपुर की दीक्षाभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं।

- **Lakhs of followers** are expected to gather to **pay homage** to the **architect of the Indian Constitution**.

  भारतीय संविधान के शिल्पकार को **श्रद्धांजलि** देने के लिए **लाखों अनुयायियों** के एकत्र होने की **संभावना** है।

- Authorities in both cities have increased **security and civic arrangements**, anticipating **large crowds**.

  दोनों शहरों के प्रशासन ने **भीड़ को ध्यान में रखते हुए** सुरक्षा और **नागरिक सुविधाओं** को बढ़ा दिया है।

- **Chaityabhoomi in Dadar** and **Deekshabhoomi in Nagpur** are closely linked to **Dr. Ambedkar's life and legacy**.

  दादर की चैत्यभूमि और **नागपुर की दीक्षाभूमि**, **डॉ. अंबेडकर के जीवन और विरासत** से गहराई से जुड़ी

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

हुई हैं।

- These places witness **massive footfall** every year on **April 14**.
  14 अप्रैल को हर साल इन स्थलों पर **भारी भीड़** देखी जाती है।

- **Cultural programmes** and **public addresses** are scheduled to mark the occasion.
  इस अवसर पर **सांस्कृतिक कार्यक्रम** और **जनसभाएं** आयोजित की गई हैं।

Local administrations have appealed to visitors to **cooperate** with authorities for a **peaceful and respectful** observance.
स्थानीय प्रशासन ने आगंतुकों से **शांतिपूर्ण और सम्मानजनक** आयोजन के लिए **प्रशासन के साथ सहयोग** करने की अपील की है।**र** समुदायों को भी अनुमति दी जाती थी।

What triggered this change?
इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई?

The change began with a **reformist campaign** led by a **self-help group** called **Pilicode Ninav Purush Swayaamsahaya Sangham**.
यह परिवर्तन **पिलिकोड निनव पुरुष स्वयं सहायता संघ** नामक एक **सुधारवादी संगठन** के नेतृत्व में शुरू हुए **अभियान** से हुआ।

What was the role of Janakiya Samithi?
जानकीया समिति की भूमिका क्या थी?

The **Janakiya Samithi**, a **people's committee** formed with **socio-cultural and political organisations**, petitioned the **Tantri (chief priest)**, the **State Devaswom Minister V.N. Vasavan**, and the **temple committee** for universal access.
जानकीया समिति, जो कि **सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों** की एक **जन समिति** है, ने **तंत्री (मुख्य पुजारी)**, **राज्य देवास्वम मंत्री वी.एन. वसावन**, और **मंदिर प्रशासनिक समिति** को **सर्वसामान्य प्रवेश** की मांग को लेकर याचिका दी।

When did the change happen?
यह बदलाव कब हुआ?

Around **8 a.m. on Sunday**, a group of **16 devotees** entered the sacred space — a day before the **Vishu festival**.
रविवार सुबह करीब 8 बजे, **विषु त्योहार से एक दिन पहले**, **16 भक्तों** का एक समूह मंदिर के **पवित्र स्थल** में प्रवेश किया।

PATRIOTIC IAS

Was this a one-time change?

क्या यह एक बार की अनुमति थी?

No, the **Janakiya Samithi confirmed** that the inner quarter will remain **open permanently** to **all devotees**.

नहीं, **जानकीया समिति ने पुष्टि की** कि मंदिर का अंदरूनी भाग अब **सभी श्रद्धालुओं के लिए स्थायी रूप से खुला रहेगा**

Why is this event considered important?

यह घटना क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

It is seen as a **moral and cultural victory**, showing that **age-old rituals** must change over time to reflect **equality** and **inclusion**.

इसे एक **नैतिक और सांस्कृतिक जीत** माना जा रहा है, जो दर्शाता है कि **पुरानी परंपराओं** को समय के साथ बदलना चाहिए ताकि वे **समानता** और **समावेशिता** को दर्शा सकें।

During caste census in Karnataka, some desisted from giving details, some did not know their caste

GS Paper I: Society

Sharath S. Srivatsa
BENGALURU

While the caste-wise population identified in the Socio-Economic and Educational Survey (caste census) conducted by the Karnataka State Commission for Backward Classes had led to a furore, a small percentage of the population had either refused to provide caste details during the census or did not know their caste to provide the details.

A total of 73,399 families, including 53,241 in urban areas, which accounted for about 2.53 lakh (including 1.12 lakh women), or about 0.425%, of the State population, refused to identify their caste during the enumeration, show data available in the survey report accepted by the Cabinet on Friday.

The full report is yet to be released by the government, and it will be discussed at a special Cabinet meeting on April 17.

As many as 35,845 families, including 27,535 living in urban areas, have stated that they do not belong to any caste or are 'caste-free'.

Their population is pegged at 1.34 lakh or about 0.225% of the State's enumerated population.

These data have emerged at a time when caste groups are lobbying to state that their numbers have reduced or the names of the castes have gone wrong.

As many as 5.98 crore people of about a projected population of 6.35 crore in Karnataka from about 1.35 crore households were covered under the survey conducted in 2015. The survey is being seen as an important document containing data set that would realign the political calculations as well as allow the government to recalibrate its focus on the populations that have continued to not receive the reservation benefits.

About 52,272 families, including 44,912 families in urban areas, have marked themselves under the "if at all does not know the caste" category, Their population is pegged at 1.94 lakh or about 0.324% of the total population. Castes and communities could not be identified for 3,755 persons belonging to 967 households in the State.

Commission sources said that those who did not reveal or did not have castes are not part of the final number calculated for enumeration.

"Some people did not know castes because of migration or due to nomadic nature. Some castes were not in the detailed list that we had drafted. Moreover, we cannot compel anyone to provide details," they said.

Fact sheet

Total projected population in 2015	6.35 crore
Total population covered	5.98 crore
People who refused to identify their castes	2.53 lakh
People who said they are 'caste-free'	1.34 lakh
People not knowing their caste	1.94 lakh
Castes and communities that could not be identified	3,755

During Caste Census in Karnataka, Some Desisted from Giving Details, Some Did Not Know Their Caste

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

कर्नाटक में जातिगत जनगणना के दौरान कुछ लोगों ने जानकारी देने से इनकार किया, कुछ अपनी जाति नहीं जानते थे

Caste details not shared or unknown by a small percentage
थोड़े प्रतिशत लोगों ने जाति की जानकारी नहीं दी या उन्हें जाति का ज्ञान नहीं था

- While the **caste-wise population** identified in the **Socio-Economic and Educational Survey** (caste census) created a **furore**, a **small percentage** of people either **refused to share caste details** or **did not know their caste**.
  सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) में **जाति-वार जनसंख्या** की पहचान से **विवाद** उत्पन्न हुआ, लेकिन **थोड़े प्रतिशत** लोगों ने या तो **जाति की जानकारी देने से इनकार किया** या **अपनी जाति के बारे में नहीं जानते थे**।
- **Total 73,399 families refused caste identification**
  कुल 73,399 परिवारों ने जाति पहचान से किया इनकार
- About **73,399 families**, including **53,241 from urban areas**, refused to provide their **caste** during enumeration. This accounts for about **2.53 lakh people** (including **1.12 lakh women**), which is **approximately 0.425%** of the State population.
  लगभग **73,399 परिवारों** ने, जिनमें **53,241 शहरी क्षेत्र** से थे, **गणना के दौरान जाति की जानकारी देने से इनकार** किया। यह लगभग **2.53 लाख लोगों** (जिसमें **1.12 लाख महिलाएं** शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करता है, जो **राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 0.425%** है।
- **Full report yet to be released**
  पूरी रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है
- The **full report** of the caste census is yet to be released by the **government**, and it will be discussed in a **special Cabinet meeting on April 17**.
  सरकार द्वारा जाति जनगणना की पूरी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है, और इसे **17 अप्रैल को विशेष कैबिनेट बैठक** में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
- **35,845 families identified themselves as caste-free**
  35,845 परिवारों ने खुद को जातिविहीन बताया
- About **35,845 families**, including **27,535 from urban areas**, stated that they either **do not belong to any caste** or are **caste-free**. Their population is estimated at **1.34 lakh**, around **0.225%** of the State's enumerated population.
  लगभग **35,845 परिवारों** ने, जिनमें से **27,535 शहरी क्षेत्र** से हैं, बताया कि वे या तो **किसी जाति से नहीं जुड़े हैं** या **जातिविहीन** हैं। इनकी जनसंख्या लगभग **1.34 लाख** आंकी गई है, जो **राज्य की कुल गिनी गई आबादी का लगभग 0.225%** है।
- **Data emerges amid caste group lobbying**
  जातीय समूहों के दबाव के बीच यह आंकड़े सामने आए
- This data comes at a time when **caste groups** are lobbying, claiming their **numbers have reduced** or that their **caste names were recorded incorrectly**.

PATRIOTIC IAS

यह आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब **जातीय समूह** यह दावा कर रहे हैं कि **उनकी संख्या कम दिखाई गई है** या **उनकी जातियों के नाम गलत दर्ज हुए हैं**।

- **Survey covered 5.98 crore people from 1.35 crore households**
  सर्वेक्षण में 1.35 करोड़ घरों से 5.98 करोड़ लोगों को शामिल किया गया
- The survey, conducted in **2015**, covered **5.98 crore people** out of a projected population of **6.35 crore**, from about **1.35 crore households**.
  2015 में कराए गए इस सर्वेक्षण में अनुमानित **6.35 करोड़ की जनसंख्या** में से **5.98 करोड़ लोग**, जो लगभग **1.35 करोड़ परिवारों** से हैं, शामिल किए गए।
- **Survey considered key for policy realignment**
  नीति पुनःसंरेखन के लिए सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है
- The caste survey is seen as an important document that can **realign political strategies** and allow the government to **refocus welfare efforts** on those **not receiving reservation benefits**.
  जाति सर्वेक्षण को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है, जो **राजनीतिक रणनीतियों को पुनः व्यवस्थित** कर सकता है और सरकार को उन वर्गों पर **कल्याणकारी योजनाएं केंद्रित करने** की सुविधा देगा जिन्हें **आरक्षण लाभ नहीं मिल रहे हैं**।
- **52,272 families didn't know their caste**
  52,272 परिवारों को अपनी जाति का ज्ञान नहीं था
- About **52,272 families**, including **44,912 from urban areas**, marked themselves under the **"don't know caste"** category. Their population is estimated at **1.94 lakh**, or about **0.324%** of the total population.
  लगभग **52,272 परिवारों**, जिनमें से **44,912 शहरी क्षेत्रों** से हैं, ने खुद को **"जाति नहीं जानते"** श्रेणी में चिह्नित किया। इनकी जनसंख्या लगभग **1.94 लाख** है, जो **कुल जनसंख्या का लगभग 0.324%** है।
- **Caste not identified for 3,755 persons**
  3,755 व्यक्तियों की जाति की पहचान नहीं हो सकी
- Caste details could not be identified for **3,755 persons** belonging to **967 households** in the State.
  राज्य के **967 परिवारों** के **3,755 व्यक्तियों** की जाति की पहचान नहीं हो सकी।
- **Reasons for missing caste details explained by Commission**
  आयोग द्वारा जाति जानकारी न देने के कारण बताए गए
- Commission sources explained that people did not reveal caste details due to **migration**, **nomadic lifestyle**, or because their **castes were not on the list**. They added, "We cannot compel anyone to give their caste."
  आयोग के सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों ने **प्रवास**, **घुमंतू जीवनशैली**, या उनके **जातियों का सूची में न होना** जैसे कारणों से जाति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, "हम किसी को जाति बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।"

PATRIOTIC IAS

TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

1. **Kerala will seek to have pending Bills deemed as passed**
   केरल लंबित विधेयकों को पारित मानने की मांग करेगा
2. **Pause, Review, and Repeal Amendment to the RTI Act: Ramesh urges Vaishnaw**
   सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन को रोकें, पुनः समीक्षा करें और निरस्त करें: रमेश ने वैष्णव से आग्रह किया
3. **SC Sub-Categorisation into 3 Groups Takes Effect in Telangana from Today**
   तेलंगाना में आज से अनुसूचित जातियों का तीन समूहों में उपवर्गीकरण प्रभावी
4. **CAG Must Probe How Government Policies Aided Oil Companies: Congress**
   सीएजी को यह जांच करनी चाहिए कि सरकार की नीतियों ने तेल कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचाया: कांग्रेस
5. **Cooperative Movement Was 'Almost Dead' Before Modi Govt., Says Shah**
   कांग्रेस सरकार से पहले सहकारी आंदोलन 'लगभग मर चुका था', शाह का बयान
6. **Undertake Survey to Assess MGNREGS Effectiveness: Panel**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करने की सिफारिश: पैनल

7. India, Africa Maritime Engagement Exercise Begins off Tanzania Coast

भारत-अफ्रीका समुद्री अभ्यास तंजानिया तट पर शुरू हुआ

8. A Governor's Conduct and a Judgment of Significance

राज्यपाल का आचरण और एक महत्वपूर्ण निर्णय

9. Adding a French Touch to India's Olympic Dream

भारत के ओलंपिक सपने में फ्रांसीसी स्पर्श

Kerala will seek to have pending Bills deemed as passed

GS Paper II: Polity

K.S. Sudhi
KOCHI

The State is set to contend in the top court that the action of former Governor on some Bills was 'erroneous in law'

Armed with the Supreme Court's landmark judgment on Bills kept pending by the Governors and the President, Kerala is set to contend in the top court that all the Bills pending with the President be deemed as passed.

The Supreme Court last week deemed Bills kept pending by Tamil Nadu Governor R.N. Ravi to have received assent. Kerala will approach the Supreme Court next month seeking similar relief.

The Supreme Court had ruled that the prolonged refusal of Mr. Ravi to give assent to the Bills was "illegal" and "erroneous in law".

Kerala had earlier approached the top court against similar acts of former Governor Arif Muhammad Khan. It had also moved the court against President Droupadi Murmu's act of withholding assent to a few Bills.

Kerala will contend that the Bills pending with Ms. Murmu, including those for which she had withheld assent, be deemed as passed since the very act of the Governor sitting on them and later referring them to the President was "erroneous in law". The State will also highlight the fact that the President had assigned no reasons for withholding consent for the Bills.

The SC, legal experts pointed out, had made it clear that the President would be required to assign clear and detailed reasons while withholding assent to a Bill.

Kerala will seek to have pending Bills deemed as passed

केरल लंबित विधेयकों को पारित मानने की मांग करेगा

Armed with the Supreme Court's landmark judgment on Bills kept pending by the Governors and the President, Kerala is set to argue in the top court that all the Bills pending with the President be deemed as passed.

राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा लंबित रखे गए विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर, केरल शीर्ष अदालत में यह तर्क देगा कि राष्ट्रपति के पास लंबित सभी विधेयकों को पारित माना जाए।

- The **Supreme Court last week** deemed **Bills kept pending by Tamil Nadu Governor R.N. Ravi** to have received assent.

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा लंबित रखे गए विधेयकों को **मंजूरी प्राप्त माना।**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Kerala will approach the **Supreme Court next month** seeking similar relief.
  केरल अगले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और **ऐसी ही राहत** मांगेगा।
- The Supreme Court had ruled that the **prolonged refusal** of Mr. Ravi to give assent to the Bills was "**illegal**" and "**erroneous in law**".
  सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि श्री रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने से **लगातार इनकार करना "अवैध" और "कानून में त्रुटिपूर्ण"** है।
- Kerala had earlier approached the **top court** against similar acts of **former Governor Arif Muhammad Khan**.
  केरल पहले भी पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के ऐसे ही कृत्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुका है।
- It had also moved the court against **President Droupadi Murmu's act of withholding assent** to a few Bills.
  केरल ने कुछ विधेयकों पर **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी रोकने के कार्य** के खिलाफ भी अदालत में याचिका दायर की थी।
- Kerala will contend that the **Bills pending with Ms. Murmu**, including those for which she had **withheld assent**, be **deemed as passed**.
  केरल यह तर्क देगा कि राष्ट्रपति मुर्मू के पास लंबित सभी विधेयक, जिन पर उन्होंने **मंजूरी नहीं दी**, **पारित माने जाएं।**
- The State will argue that the act of the **Governor sitting on the Bills and later referring them to the President** was **"erroneous in law"**.
  राज्य यह भी तर्क देगा कि **राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकना और बाद में उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना "कानून में त्रुटिपूर्ण"** था।
- The State will also highlight that the **President had assigned no reasons** for **withholding assent** to the Bills.
  राज्य यह भी उजागर करेगा कि **राष्ट्रपति ने विधेयकों को मंजूरी न देने का कोई कारण नहीं बताया।**
- Legal experts pointed out that the **Supreme Court** has made it clear that the **President must give clear and detailed reasons** while **withholding assent**.
  कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि **सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को मंजूरी न देने की स्थिति में स्पष्ट और विस्तृत कारण बताने होंगे।**

PATRIOTIC IAS

Pause, review, and repeal amendment to the RTI Act: Ramesh urges Vaishnaw

GS Paper II: RTI Act

The Hindu Bureau

NEW DELHI

In a letter to Union Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw on Sunday, Congress Rajya Sabha member Jairam Ramesh warned that the proposed amendment to the Right to Information Act, 2005, would have a "devastating" effect on the transparency law. He urged Mr. Vaishnaw to "pause, review, and repeal" the change.

The letter was in response to Mr. Vaishnaw's assurance to an earlier letter by Mr. Ramesh, in which the Congress leader had expressed concern over Section 44 (3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, which would place a blanket ban on sharing any "personal information" with RTI applicants.

Mr. Vaishnaw had responded to Mr. Ramesh, saying that the amendment was aimed at preventing "misuse" of the law, and the information that is specifically required to be disclosed (such as salaries of public officials) would remain accessible.

Four points

Making four points by way of a counter-response to the Minister, Mr. Ramesh said: "I would therefore strongly again urge you to pause, review, and repeal the amendment made to the RTI Act, 2005. As you would have seen, this issue has also exercised a broad spectrum of people from civil society, academics, and political parties."

Along with Mr. Ramesh, 130 Opposition MPs have signed another letter demanding a reversal of the amendment.

Civil society groups voiced concerns regarding the amendment, which would strike out all but the first six words in Section 8(1)(j), which exempts "information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless" officials are convinced that the "larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person".

Thanking the Union Minister for his response, Mr. Ramesh said, "I now wish to make four points."

"First, Section 3 of the DPDP Act, 2023, cited in your letter as protecting disclosures under the RTI Act 2005, is wholly irrelevant since Section 8(1) of the RTI Act, 2005 itself has been amended drastically," he said. "Section 3 of the DPDP Act will now only protect disclosures as per the amended RTI Act, which exempts all personal information from being accessible."

Second, the operation of the RTI Act, 2005 – informed by several judgments by the Supreme Court and various High Courts – has demonstrated that the law is able to withhold the disclosure of personal information which has no relationship to any public activity or public interest, Mr. Ramesh said.

Third, the deletion of the proviso in Section 8(1) of the RTI Act which recognises the citizens' right to information as being at par with that of legislators is "completely unwarranted", the Congress general secretary said in the letter to Mr. Vaishnaw. "In fact, that proviso is applicable not just to the personal information exemption, but all exemptions in Section 8(1) of the RTI Act, 2005."

"Fourth, you mention the *Puttaswamy* judgment of the Supreme Court. Please do remember that nowhere in this judgment is it mentioned that the RTI Act, 2005 itself needs to be amended."

Pause, Review, and Repeal Amendment to the RTI Act: Ramesh urges Vaishnaw

सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन को रोकें, पुनः समीक्षा करें और निरस्त करें: रमेश ने वैष्णव से आग्रह किया

In a letter to Union IT Minister Ashwini Vaishnaw on Sunday, Congress Rajya Sabha MP Jairam Ramesh warned that the proposed amendment to the Right to Information (RTI) Act, 2005 would have a "devastating" impact on the law.

रविवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित संशोधन का कानून पर "विनाशकारी" प्रभाव पड़ेगा।

- **He urged Mr. Vaishnaw to "pause, review, and repeal" the amendment.**

उन्होंने श्री वैष्णव से इसे "रोकने, समीक्षा करने और निरस्त करने" का आग्रह किया।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- The letter was in response to Mr. Vaishnaw's earlier assurance to Ramesh's previous letter expressing concern over Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023.
  यह पत्र श्री वैष्णव के उस आश्वासन के जवाब में था, जो श्री रमेश के पिछले पत्र पर दिया गया था जिसमें उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) को लेकर चिंता व्यक्त की थी।
- Section 44(3) would place a blanket ban on sharing any "personal information" with RTI applicants.
  धारा 44(3) सूचना के अधिकार आवेदकों को किसी भी प्रकार की "व्यक्तिगत जानकारी" साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगी।
- Mr. Vaishnaw had said the amendment was to prevent "misuse" of the law, and certain data like public officials' salaries would still be available.
  श्री वैष्णव ने कहा था कि यह संशोधन कानून के "दुरुपयोग" को रोकने के लिए है, और लोक अधिकारियों के वेतन जैसी जानकारियां अभी भी उपलब्ध रहेंगी।
- Four Points by Jairam Ramesh
  जयराम रमेश के चार तर्क
- Mr. Ramesh responded with four counter-points, urging again to pause, review, and repeal the amendment.
  श्री रमेश ने चार मुख्य बिंदुओं के साथ जवाब दिया और एक बार फिर से संशोधन को रोकने, समीक्षा करने और निरस्त करने का आग्रह किया।
- He said this issue has affected a broad spectrum of civil society, academics, and political parties.
  उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नागरिक समाज, शिक्षाविदों और राजनीतिक दलों के व्यापक वर्ग को प्रभावित कर रहा है।
- Along with Mr. Ramesh, 130 Opposition MPs have signed another letter demanding reversal of the amendment.
  श्री रमेश के साथ 130 विपक्षी सांसदों ने एक अन्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें संशोधन को वापस लेने की मांग की गई है।
- Civil Society's Concern
  नागरिक समाज की चिंता
- Civil society groups raised concern that the amendment would strike out all but the first six words in Section 8(1)(j) of the RTI Act.
  नागरिक समाज समूहों ने चिंता जताई कि यह संशोधन आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) की प्रारंभिक छह शब्दों को छोड़कर शेष पूरी बात हटा देगा।
- This section currently exempts personal information from disclosure unless public interest justifies it, and ensures such info cannot be denied to the public if it cannot be denied to Parliament or a State Legislature.
  यह धारा व्यक्तिगत जानकारी को छूट देती है जब तक कि जनहित में उसका खुलासा जरूरी न हो, और

PATRIOTIC IAS

यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई जानकारी संसद या राज्य विधानसभा से नहीं छुपाई जा सकती, तो उसे किसी व्यक्ति से भी नहीं छुपाया जा सकता।

- Point One: On Section 3 of DPDP Act
  पहला बिंदु: डीपीडीपी अधिनियम की धारा 3 पर
- Mr. Ramesh said Section 3 of DPDP Act, 2023, cited by the Minister, is irrelevant now because Section 8(1) of the RTI Act itself has been drastically amended.
  श्री रमेश ने कहा कि मंत्री द्वारा उल्लिखित डीपीडीपी अधिनियम की धारा 3 अब अप्रासंगिक है क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) को गंभीर रूप से संशोधित किया गया है।
- He added that Section 3 will only protect disclosures under the amended RTI, which now exempts all personal information.
  उन्होंने जोड़ा कि अब धारा 3 केवल संशोधित आरटीआई के तहत खुलासों की रक्षा करेगी, जो अब सभी व्यक्तिगत जानकारी को छूट देती है।
- Point Two: RTI Act has withstood Judicial Scrutiny
  दूसरा बिंदु: आरटीआई अधिनियम न्यायिक समीक्षा में खरा उतरा है
- Mr. Ramesh said Supreme Court and High Court judgments have already shown that the RTI Act can withhold personal information that has no link to public activity or interest.
  श्री रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णयों से स्पष्ट है कि आरटीआई अधिनियम पहले से ही उस व्यक्तिगत जानकारी को रोकने में सक्षम है जिसका सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं है।
- Point Three: Deletion of Proviso is Unwarranted
  तीसरा बिंदु: उपवाक्य का हटाना अनुचित है
- He said the deletion of the proviso in Section 8(1), which gives citizens the same right to information as legislators, is completely unwarranted.
  उन्होंने कहा कि धारा 8(1) में उपवाक्य को हटाना, जो नागरिकों को विधायकों के समान सूचना का अधिकार देता है, पूरी तरह से अनुचित है।
- This proviso applies not just to personal information, but to all exemptions under Section 8(1).
  यह उपवाक्य केवल व्यक्तिगत जानकारी पर ही नहीं, बल्कि धारा 8(1) की सभी छूटों पर लागू होता है।
- Point Four: Misinterpretation of Puttaswamy Judgment
  चौथा बिंदु: पुट्टास्वामी निर्णय की गलत व्याख्या
- He pointed out that the Puttaswamy judgment does not recommend amending the RTI Act.
  उन्होंने बताया कि पुट्टास्वामी निर्णय में कहीं भी आरटीआई अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश नहीं की गई है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Central Information Commission (CIC)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

The Central Information Commission (CIC) is a statutory body established under the Right to Information (RTI) Act, 2005, effective from October 12, 2005.
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक **वैधानिक निकाय** है जिसे **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** के तहत स्थापित किया गया, जो **12 अक्टूबर 2005** से प्रभावी हुआ।

Its primary role is to act upon complaints from individuals who have been unable to submit information requests to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, either due to the absence of such officers or their refusal to accept the application.
इसका **मुख्य कार्य** उन व्यक्तियों की **शिकायतों पर कार्रवाई करना** है जो किसी **केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी** को सूचना का अनुरोध **नहीं दे पाए**, चाहे वह अधिकारियों की **अनुपलब्धता** के कारण हो या उनके **आवेदन स्वीकार करने से इनकार** करने के कारण।

The jurisdiction of the Commission extends over all Central Public Authorities.
आयोग का **अधिकार क्षेत्र** सभी **केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों** तक फैला हुआ है।

Composition of the Commission
आयोग की संरचना

- **One Chief Information Commissioner (CIC).**
  एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)।
- **Not more than ten Information Commissioners (ICs).**
  अधिकतम **दस सूचना आयुक्त (ICs)।**

Appointment Process: The President of India appoints the CIC and ICs based on the recommendations of a committee consisting of:
नियुक्ति प्रक्रिया: भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक **समिति की सिफारिश** पर CIC और ICs की नियुक्ति की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

- **The Prime Minister as the Chairperson.**
  प्रधानमंत्री समिति के **अध्यक्ष** के रूप में।
- **The Leader of Opposition in the Lok Sabha.**
  लोकसभा में विपक्ष के नेता।
- **A Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.**
  प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Eligibility Criteria:
योग्यता मानदंड:

Appointees should be individuals of eminence in public life with extensive knowledge and experience in fields such as law, science and technology, social service, management, journalism, mass media, or administration and governance.
नियुक्त व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हों और उन्हें **कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन** जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।

They should not be Members of Parliament or Members of the Legislature of any State or Union Territory, hold any other office of profit, be connected with any political party, or carry on any business or pursue any profession.
वे **सांसद, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य, लाभ के किसी अन्य पद पर, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध, या किसी व्यवसाय या पेशे में संलग्न** नहीं होने चाहिए।

Tenure and Service Conditions
कार्यकाल और सेवा शर्तें

Term Duration: Initially, under the RTI Act of 2005, the CIC and ICs held office for a term of five years or until they attained the age of 65 years, whichever was earlier.

However, the Right to Information (Amendment) Act, 2019 revised this provision, and the term is now determined by the Central Government.
कार्यकाल की अवधि: प्रारंभ में, **RTI अधिनियम 2005** के तहत, CIC और ICs का कार्यकाल **पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक** (जो भी पहले हो) तय था।

लेकिन **RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019** के तहत इसे संशोधित किया गया और अब कार्यकाल **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** किया जाता है।

If the CIC or ICs are receiving any pension from previous government service, their pay is reduced by the amount of that pension.
यदि **CIC या ICs को पहले की सरकारी सेवा से कोई पेंशन मिल रही हो**, तो उनका वेतन उस **पेंशन की राशि** से **कम कर दिया जाता है।**

Retirement from Parent Service: Upon appointment, if the CIC or ICs were serving in the Central or State Government, they are deemed to have retired from that service with effect from the date of their appointment.
मूल सेवा से सेवानिवृत्ति: नियुक्ति के समय यदि **CIC या ICs केंद्र या राज्य सरकार में सेवा कर रहे हों**, तो उन्हें **नियुक्ति की तिथि से उस सेवा से सेवानिवृत्त** माना जाता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Removal Procedures
हटाने की प्रक्रियाएँ

The President can remove the **Chief Information Commissioner (CIC)** or any **Information Commissioner (IC)** under the following circumstances:
राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में **मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)** या किसी भी **सूचना आयुक्त (IC)** को हटा सकते हैं:

• **Proven Misbehavior or Incapacity**: After an inquiry conducted by the **Supreme Court**, if the Court reports that the CIC or IC should be removed on such grounds.
• **सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता**: यदि **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा की गई जांच के बाद यह रिपोर्ट दी जाती है कि CIC या IC को इस आधार पर हटाया जाना चाहिए।

• **Specific Grounds for Removal**:
• **हटाने के विशिष्ट आधार**:

o If **adjudged insolvent**.
o यदि किसी को **दिवालिया घोषित** किया गया हो।

o **Conviction** of an offense involving **moral turpitude**.
o यदि **नैतिक पतन** से संबंधित किसी अपराध में **दोषी ठहराया** गया हो।

o Engaging in any **paid employment** outside the duties of the office during the term.
o कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के अलावा किसी **वेतनयुक्त कार्य** में संलग्न होना।

o If deemed **unfit to continue** in office due to **infirmity of mind or body**.
o यदि **शारीरिक या मानसिक दुर्बलता** के कारण **पद पर बने रहने के अयोग्य** माने जाएँ।

o Acquiring **financial or other interests** that are likely to **affect prejudicially** official functions.
o यदि किसी **आर्थिक या अन्य स्वार्थ** को प्राप्त किया जाए जो **आधिकारिक कार्यों को हानि पहुँचाने** की संभावना रखता हो।

In cases of proven misbehavior or incapacity, the **President may suspend** the CIC or IC **during the inquiry**.
सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामलों में, **जांच के दौरान राष्ट्रपति CIC या IC को निलंबित** कर सकते हैं।

Powers and Functions
शक्तियाँ और कार्य

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

The CIC has several **key responsibilities**:
CIC की कई **महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ** होती हैं:

• **Adjudication in Second Appeals**: It addresses **second appeals** for information requests.
• **द्वितीय अपीलों पर निर्णय**: यह सूचना अनुरोधों की **द्वितीय अपीलों** को सुलझाता है।

• **Complaint Handling**: It **entertains complaints** regarding the inability to file RTI requests, directs **record-keeping**, and ensures **suo motu disclosures**.
• **शिकायत निवारण**: यह **RTI आवेदन दायर करने में असमर्थता** से संबंधित **शिकायतों को सुनता है**, **रिकॉर्ड रखने** का निर्देश देता है और **स्वत: प्रकटीकरण** सुनिश्चित करता है।

• **Imposition of Penalties**: The Commission can **impose penalties** on Public Information Officers who **fail to provide information** without reasonable cause.
• **दंड लगाना**: आयोग उन जन सूचना अधिकारियों पर **दंड लगा सकता है** जो **उचित कारण के बिना जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं**।

• **Monitoring and Reporting**: It **monitors** the implementation of the **RTI Act** and prepares **annual reports** on its functioning.
• **निगरानी और रिपोर्टिंग**: यह **RTI अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी** करता है और इसके कार्यों पर **वार्षिक रिपोर्ट** तैयार करता है।

Recent Developments
हालिया विकास

• **Amendments to the RTI Act**: The **Right to Information (Amendment) Act, 2019** brought **significant changes**, including:
• **RTI अधिनियम में संशोधन**: **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** ने **महत्वपूर्ण परिवर्तन** किए, जिनमें शामिल हैं:

o The **tenure** of the CIC and ICs is now **determined by the Central Government**, replacing the earlier **fixed five-year term**.
o CIC और ICs का **कार्यकाल अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** किया जाता है, जबकि पहले यह **पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल** का था।

o The **salaries, allowances**, and other **service conditions** are also **determined by the Central Government**, removing the earlier equivalence to the **Chief Election Commissioner** and **Election Commissioners**.
o उनकी **वेतन, भत्ते**, और अन्य **सेवा शर्तें** अब **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** की जाती हैं, जिससे उन्हें पहले की तरह **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** और **निर्वाचन आयुक्तों** के समकक्ष नहीं माना जाता।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

These amendments have been a topic of **debate among activists and stakeholders**, with concerns about the **potential impact** on the **independence and autonomy** of the Commission.

इन संशोधनों को लेकर **कार्यकर्ताओं और संबंधित पक्षों में बहस** हुई है, क्योंकि इससे आयोग की **स्वतंत्रता और स्वायत्तता** पर **प्रभाव पड़ने की आशंका** जताई गई है।

- As of **now**, **Heeralal Samariya** is the **Chief Information Commissioner of India**.
  - **नवंबर 2025** तक, **हीरालाल सामरिया** भारत के **मुख्य सूचना आयुक्त** हैं।

SC sub-categorisation into 3 groups takes effect in Telangana from today

GS Paper II: Reservation

T
HYDERABAD

Categorisation of the Scheduled Caste communities into three groups will come into effect in Telangana from Monday, coinciding with the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar.

A Cabinet sub-committee, headed by Irrigation and Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy and co-chaired by Health Minister C. Damodar Rajanarsimha, convened a meeting with senior officials on Sunday for giving final touches to the Government Order.

Formal release today

The order will be formally released on Monday and the first copy presented to Chief Minister A. Revanth Reddy.

Mr. Uttam Kumar Reddy said the government finalised the order keeping in view the recommendations made by the one-man commission headed by the retired judge Justice Shameem Akhter.

The categorisation of 59 sub-castes among the SCs into three groups was taken up on the basis of the backwardness of the SC groups.

The first group comprised 15 sub-castes that were the most backward and made up 3.288% of the SC population. It was accordingly decided to provide 1% reservation to these sub-castes.

The second group comprising 18 sub-castes constituting 62.74% of the population and in receipt of marginal benefits, had been given 9% reservation.

The third group, with 26 sub-castes and constituting 33.96% of the population and found to be relatively forward compared with other groups, was given 5% reservation.

Mr. Uttam Kumar Reddy recalled that the State government had constituted the one-man commission immediately after the Supreme Court's historic verdict on categorisation, and the commission conducted an in-depth study on the status of these sub-castes, receiving over 8,600 representations in the process.

Finishing touches: Cabinet sub-committee during the meeting on Sunday. SPECIAL ARRANGEMENT

SC Sub-Categorisation into 3 Groups Takes Effect in Telangana from Today

तेलंगाना में आज से अनुसूचित जातियों का तीन समूहों में उपवर्गीकरण प्रभावी

Categorisation begins on Ambedkar Jayanti

अंबेडकर जयंती पर उपवर्गीकरण की शुरुआत

- The **categorisation of Scheduled Caste (SC) communities into three groups** comes into **effect in Telangana** from **Monday**, coinciding with the **birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar**.

  तेलंगाना में सोमवार से अनुसूचित जातियों के तीन समूहों में वर्गीकरण लागू हो गया है, जो **डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती** के दिन हुआ।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Cabinet Sub-Committee Finalised the Order
मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने आदेश को अंतिम रूप दिया

- A **Cabinet sub-committee**, headed by **Irrigation and Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy** and co-chaired by **Health Minister C. Damodar Rajanarsimha**, met with **senior officials** on **Sunday** to give final touches to the **Government Order**.
  सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता और **स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा** की सह-अध्यक्षता में एक **कैबिनेट उप-समिति** ने **रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों** के साथ बैठक की और **सरकारी आदेश** को अंतिम रूप दिया।

Formal Release of Government Order
सरकारी आदेश का औपचारिक रूप से जारी होना

- The order will be **formally released on Monday**, and the **first copy** will be presented to **Chief Minister A. Revanth Reddy**.
  यह आदेश **सोमवार को औपचारिक रूप से जारी** किया जाएगा और इसकी **प्रथम प्रति मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी** को सौंपी जाएगी।

Based on One-Man Commission Report
एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर

- The order is based on the **recommendations** of a **one-man commission** headed by **retired judge Justice Shameem Akhter**.
  यह आदेश **सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस शमीम अख्तर** की अध्यक्षता वाले **एकल सदस्यीय आयोग** की **सिफारिशों** पर आधारित है।

Total 59 SC Sub-Castes Categorised
कुल 59 अनुसूचित जाति उप-जातियों का वर्गीकरण

- The **59 sub-castes** of the SCs have been categorised into **three groups**, based on the **level of backwardness** among the communities.
  अनुसूचित जातियों की 59 उप-जातियों को उनके **पिछड़ेपन के स्तर** के आधार पर **तीन समूहों** में विभाजित किया गया है।

Group I: Most Backward (3.288%)
समूह I: सबसे पिछड़ा (3.288%)

- This group includes **15 sub-castes**, which are considered the **most backward** and constitute **3.288%** of the SC population. They will receive **1% reservation**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

इस समूह में **15 उप-जातियाँ** शामिल हैं जो **सबसे पिछड़ी** मानी गई हैं और जो **एससी आबादी का 3.288%** हैं। इन्हें **1% आरक्षण** दिया जाएगा।

Group II: Marginally Benefitted (62.74%)
समूह II: आंशिक लाभ प्राप्त (62.74%)

- This group includes **18 sub-castes**, making up **62.74%** of the SC population. These sub-castes, who have received **marginal benefits**, are allotted **9% reservation**.
  इस समूह में **18 उप-जातियाँ** शामिल हैं, जो **एससी आबादी का 62.74%** हैं। इन्हें **9% आरक्षण** दिया गया है क्योंकि इन्हें **सीमित लाभ** प्राप्त हुए हैं।

Group III: Relatively Forward (33.96%)
समूह III: तुलनात्मक रूप से आगे (33.96%)

- This group includes **26 sub-castes**, which are relatively more forward and form **33.96%** of the SC population. They are assigned **5% reservation**.
  इस समूह में **26 उप-जातियाँ** हैं, जो अन्य समूहों की तुलना में **तुलनात्मक रूप से आगे** मानी गई हैं और **एससी आबादी का 33.96%** हैं। इन्हें **5% आरक्षण** दिया गया है।

One-Man Commission and Study Process
एकल सदस्यीय आयोग और अध्ययन प्रक्रिया

- Mr. Uttam Kumar Reddy said that the **State Government** constituted the **commission** immediately after the **Supreme Court's historic verdict on categorisation**, and it conducted an **in-depth study**.
  श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि **राज्य सरकार** ने **उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले** के बाद तुरंत **आयोग का गठन** किया और आयोग ने **गहन अध्ययन** किया।

Public Participation in the Process
प्रक्रिया में जन भागीदारी

- The commission received over **8,600 representations** during the study process.
  अध्ययन प्रक्रिया के दौरान आयोग को **8,600 से अधिक अभ्यावेदन** प्राप्त हुए।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

CAG must probe how govt. policies aided oil companies: Cong.

GS Paper II: CAG, CVC, and CBI

NEW DELHI

Accusing the government of "looting" people by increasing excise duty on petrol and diesel, the Congress on Sunday called for fixing accountability, and demanded that the Comptroller and Auditor-General (CAG) audit how government policies benefited private companies.

The party also demanded that the Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation investigate whether there was deliberate negligence or collusion in this matter.

Congress general secretary (communications) Jairam Ramesh said on X, "The people of India are being looted – on one hand, the Modi government is increasing the tax burden and picking people's pockets, while on the other hand, private and government oil companies are making profits! This is open economic exploitation!"

"The truth is: In May 2014, the excise duty on petrol was ₹9.20 and on diesel ₹3.46. Under the Modi government, this has risen to ₹19.90 on petrol and ₹15.80 on diesel – an increase of 54% and 357%, respectively!" he said.

Jairam Ramesh

He said the government had earned ₹39.54 lakh crore from the petroleum sector over the past 11 years, but failed to give any relief to people. "In May 2014, crude oil was $108/barrel, today it is only $65.31 – i.e. 40% cheaper, yet the prices of petrol and diesel are higher than the UPA era," Mr. Ramesh said.

"In 2014, petrol in Delhi was ₹71.41 and diesel ₹55.49 per litre. Today, the same petrol is ₹94.77 and diesel ₹87.67 per litre – the public is being openly looted," he asked.

He said along with government companies, the private oil companies are also earning huge profits from refining and marketing, while the common man is burdened with expensive petrol and diesel.

CAG Must Probe How Government Policies Aided Oil Companies: Congress

सीएजी को यह जांच करनी चाहिए कि सरकार की नीतियों ने तेल कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचाया: कांग्रेस

The Congress accused the government of "looting" people by increasing excise duty on petrol and diesel, and called for fixing accountability.

कांग्रेस ने सरकार पर "लोगों को लूटने" का आरोप लगाया है, क्योंकि उसने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है और जवाबदेही तय करने की मांग की है।

- The party demanded that the **Comptroller and Auditor-General (CAG)** audit how **government policies** benefited **private companies**.

पार्टी ने मांग की कि **कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी)** यह ऑडिट करे कि **सरकार की नीतियों** ने **निजी कंपनियों** को कैसे लाभ पहुँचाया।

- The Congress also called for an investigation by the **Central Vigilance Commission** and **Central Bureau of Investigation (CBI)** to determine if there was **deliberate negligence** or **collusion**.

कांग्रेस ने **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)** से यह जांच करने की भी मांग की कि क्या

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

इसमें **जानबूझकर लापरवाही** या **साठगांठ** थी।

- Congress General Secretary (Communications) **Jairam Ramesh** said on X, "The people of India are being **looted** — on one hand, the **Modi government** is increasing the **tax burden** and picking people's pockets, while on the other hand, private and government **oil companies** are making **profits**! This is open **economic exploitation**!"
  कांग्रेस के महासचिव (संचार) **जयराम रमेश** ने एक्स पर कहा, "भारत के लोग **लूटे जा रहे हैं** — एक ओर, **मोदी सरकार कर का बोझ** बढ़ा रही है और लोगों की जेबें काट रही है, वहीं दूसरी ओर, निजी और सरकारी **तेल कंपनियां** मुनाफा कमा रही हैं! यह खुला **आर्थिक शोषण** है!"

- He highlighted that in **May 2014**, the **excise duty** on **petrol** was **₹9.20** and on **diesel** it was **₹3.46**. Under the **Modi government**, this has increased to **₹19.90** on **petrol** and **₹15.80** on **diesel**, an increase of **54%** and **357%** respectively.
  उन्होंने बताया कि **मई 2014** में **पेट्रोल** पर **उत्पाद शुल्क ₹9.20** था और **डीजल** पर यह **₹3.46** था। **मोदी सरकार** के तहत, यह **पेट्रोल** पर **₹19.90** और **डीजल** पर **₹15.80** हो गया है, जो क्रमशः **54%** और **357%** की वृद्धि है।

- Mr. Ramesh further pointed out that the **government** earned **₹39.54 lakh crore** from the **petroleum sector** over the past **11 years**, but failed to provide any relief to the public.
  श्री रमेश ने आगे यह भी बताया कि **सरकार** ने **पेट्रोलियम क्षेत्र** से पिछले **11 वर्षों** में **₹39.54 लाख करोड़** की आय अर्जित की, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं दी।

- He said that while **crude oil** was **$108/barrel** in **May 2014**, today it is only **$65.31** — **40% cheaper**, yet the prices of **petrol** and **diesel** are higher than during the **UPA era**.
  उन्होंने कहा कि जबकि **मई 2014** में **कच्चा तेल $108/ बैरल** था, आज यह सिर्फ **$65.31** है — **40% सस्ता**, फिर भी **पेट्रोल** और **डीजल** की कीमतें **यूपीए सरकार** के समय से ज्यादा हैं।

- Mr. Ramesh also pointed out that in **2014**, the price of **petrol** in **Delhi** was **₹71.41** and **diesel** was **₹55.49** per litre. Today, the same **petrol** costs **₹94.77** and **diesel** costs **₹87.67** per litre.
  श्री रमेश ने यह भी बताया कि **2014** में **दिल्ली** में **पेट्रोल** की कीमत **₹71.41** और **डीजल** की कीमत **₹55.49** प्रति लीटर थी। आज वही **पेट्रोल ₹94.77** और **डीजल ₹87.67** प्रति लीटर है।

- He stated that both **government** and **private oil companies** are earning huge profits from refining and marketing, while the common man is burdened with **expensive petrol and diesel**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

उन्होंने कहा कि **सरकारी** और **निजी तेल कंपनियां** रिफाइनिंग और विपणन से भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि आम आदमी महंगे **पेट्रोल** और **डीजल** के बोझ तले दबा हुआ है।

Cooperative movement was 'almost dead' before Modi govt., says Shah

GS Paper II: FR

Press Trust of India
BHOPAL

In a veiled swipe at previous Congress-led governments, Union Home Minister Amit Shah said on Sunday that the cooperative movement had remained in a shambles as laws had not been tweaked for years and "almost died" before the Narendra Modi government took decisive actions.

Addressing a State-level cooperative conference in Bhopal, Mr. Shah said the erstwhile governments never considered bolstering the cooperative sector.

On the occasion, an agreement was signed between the National Dairy Development Board (NDDB) and the Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation to enhance milk production in the State.

"For years, the cooperative movement was moving slowly and turned almost dead. Looking at the cooperative movement nationwide, it was uneven (in the past)," he said.

Union Home Minister Amit Shah distributes a Kisan Card to a beneficiary during a conference in Bhopal on Sunday. ANI

He said the movement gained traction only after 75 years of Independence, when Prime Minister Modi formed the Ministry of Cooperatives to strengthen the sector.

"In some States, the movement gained momentum, while in some places, it has been destroyed. The main reason was that the laws, which should have been changed with time, were not tweaked," Mr. Shah said while crediting Mr. Modi for bringing a "positive change" in the cooperative movement.

Madhya Pradesh has a lot of possibilities in the agriculture, animal husbandry and cooperative fields, Mr. Shah said, acknowledging the need to undertake more efforts to exploit these possibilities to the fullest.

"Madhya Pradesh is seeing good governance now. The cooperatives were almost dead during the Congress regime. This is a golden opportunity for their revival, and Madhya Pradesh should take this opportunity," he said.

As cooperation is a State subject under the Constitutional arrangement, initiatives were not taken to frame cooperative laws adapting to rapidly changing conditions across the country.

"This (scenario) was not considered from a holistic perspective at the national level, because there was no separate Ministry for cooperatives," he said.

Stating that the Centre works within the Constitutional framework, Mr. Shah said the Union government has enacted model bylaws for cooperatives, which are accepted by all States.

"By accepting these model bylaws that empower primary societies, States have given a new lease of life to the cooperative sector in India," he said while thanking the States.

Mr. Shah said the Modi government was "standing like a rock" in supporting the cooperative sector's expansion.

Cooperative Movement Was 'Almost Dead' Before Modi Govt., Says Shah

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

कांग्रेस सरकार से पहले सहकारी आंदोलन 'लगभग मर चुका था', शाह का बयान

Union Home Minister Amit Shah criticized the previous Congress-led governments, stating that the cooperative movement had been in a state of shambles and had "almost died" because laws had not been updated for years.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन वर्षों तक खस्ताहाल रहा था और "लगभग मर चुका था" क्योंकि कानूनों में वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था।

- Addressing a state-level cooperative conference in **Bhopal**, Shah stated that the previous governments never considered strengthening the **cooperative sector**.
  भोपाल में एक राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी **सहकारी क्षेत्र** को मजबूत करने पर विचार नहीं किया।

- An agreement was signed between the **National Dairy Development Board (NDDB)** and the **Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation** to enhance **milk production** in the state.
  राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) और **मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेरी संघ** के बीच राज्य में **दूध उत्पादन** बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ।

- Shah pointed out that for years, the cooperative movement was slow and had almost died. He described the movement as being **uneven** in the past.
  शाह ने कहा कि वर्षों तक सहकारी आंदोलन धीमा था और लगभग मर चुका था। उन्होंने इसे पहले **असमान** बताया।

- He credited **Prime Minister Modi** for bringing positive change in the movement by forming the **Ministry of Cooperatives** to strengthen the sector.
  उन्होंने **प्रधानमंत्री मोदी** को सहकारी आंदोलन में सकारात्मक बदलाव लाने का श्रेय दिया, जब उन्होंने **सहकारी मंत्रालय** स्थापित किया ताकि क्षेत्र को मजबूत किया जा सके।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Shah stated that the cooperative movement gained momentum only after **75 years of Independence**.
  शाह ने कहा कि **75 वर्षों** बाद ही सहकारी आंदोलन ने गति पकड़ी।

- He emphasized that in some states the cooperative movement gained momentum, while in others it was destroyed, due to the failure to adapt laws to the changing times.
  उन्होंने जोर दिया कि कुछ राज्यों में सहकारी आंदोलन ने गति पकड़ी, जबकि अन्य में यह नष्ट हो गया, क्योंकि समय के साथ कानूनों में बदलाव नहीं किया गया।

- Shah acknowledged that **Madhya Pradesh** has great potential in **agriculture**, **animal husbandry**, and **cooperative fields**, and more efforts are needed to fully exploit these possibilities.
  शाह ने स्वीकार किया कि **मध्य प्रदेश** में **कृषि**, **पशुपालन**, और **सहकारी क्षेत्रों** में बहुत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

- He stated that under the **Congress regime**, cooperatives were almost dead, and now is a **golden opportunity** for their revival.
  उन्होंने कहा कि **कांग्रेस सरकार** के तहत सहकारी लगभग मर चुके थे, और अब उनके पुनरुद्धार के लिए एक **सुनहरा अवसर** है।

- Shah pointed out that **cooperation** is a **State subject** under the Constitutional arrangement, and no initiatives were taken to adapt cooperative laws to rapidly changing conditions.
  शाह ने बताया कि **सहकारिता** संविधान के तहत **राज्य विषय** है, और सहकारी कानूनों को तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी।

- He mentioned that there was no separate Ministry for cooperatives, which resulted in the **lack of a national level perspective**.
  उन्होंने बताया कि सहकारिता के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था, जिसके कारण **राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण की कमी** थी।

- Shah added that the **Union government** has enacted **model bylaws** for cooperatives, which are now accepted by all states, giving a new lease of life to the cooperative sector.
  शाह ने कहा कि **केंद्र सरकार** ने सहकारिता के लिए **मॉडल उपनियम** बनाए हैं, जिन्हें अब सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, और इससे सहकारी क्षेत्र को नया जीवन मिला है।

PATRIOTIC IAS

- He also thanked the states for accepting the model bylaws and stated that the Modi government is "standing like a rock" in supporting the cooperative sector's expansion.
उन्होंने राज्यों को मॉडल उपनियमों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मोदी सरकार सहकारी क्षेत्र के विस्तार में "चट्टान की तरह खड़ी है।"

Undertake survey to assess MGNREGS effectiveness: panel

GS Paper II: Government Schemes

The Parliamentary Standing Committee on Rural Development has recommended an independent survey to assess the effectiveness of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and its shortcomings.

This survey, the panel said, should focus on worker satisfaction, wage delays, participation trends, and financial irregularities within the scheme.

The panel's report was tabled on April 4, the concluding day of the Budget Session of Parliament. The panel, headed by Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka, has argued that such a survey should focus on the necessary policy reforms, and should be introduced based on the insights from the survey.

Equal opportunities

The panel also said that despite the stated objective of the scheme to uplift marginalised communities, the participation of women workers and those from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes remained "inconsistent across districts".

"A district-wise study must be conducted to ensure that these communities receive equal work opportunities and benefits under the scheme, thereby fulfilling its intended goal of social and economic inclusion," the report said.

The panel pointed out that the scheme has been plagued by delays in wage payments.

The panel also stressed the need to revamp the scheme, keeping in view the "changing times and emerging challenges". "This committee urges the Ministry to explore the options that could increase the number of guaranteed working days under MGNREGA to at least 150 days from the current 100 days," the report said.

The parliamentary panel also pointed out that the scheme has been plagued by chronic delays in wage payments, leading to uncertainty for the workers. It has recommended that the current compensation rate for delayed wages should be increased. The Committee strongly recommended that timely disbursement of these payments was essential to maintain trust in the scheme and ensure uninterrupted execution of work.

Undertake Survey to Assess MGNREGS Effectiveness: Panel

मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करने की सिफारिश: पैनल

The Parliamentary Standing Committee on Rural Development has recommended an independent survey to assess the effectiveness of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and its shortcomings.

लोकसभा स्थायी समिति (ग्रामीण विकास) ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की प्रभावशीलता और उसकी कमियों का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है।

- This survey should focus on key areas like **worker satisfaction**, **wage delays**, **participation trends**, and **financial irregularities** within the scheme.
यह सर्वेक्षण **कार्यकर्ता संतोष**, **वेतन में देरी**, **भागीदारी के रुझान** और योजना के भीतर **आर्थिक अनियमितताओं** पर केंद्रित होना चाहिए।

- The panel's report was tabled on **April 4**, the concluding day of the **Budget Session** of Parliament.
पैनल की रिपोर्ट **4 अप्रैल** को संसद के **बजट सत्र** के समापन दिन प्रस्तुत की गई।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- The panel, headed by **Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka**, argued that such a survey should focus on **necessary policy reforms**, which should be introduced based on the insights from the survey.
  पैनल, जिसकी अध्यक्षता **कांग्रेस सांसद साप्तागिरी शंकर उलाका** द्वारा की गई, ने कहा कि ऐसे सर्वेक्षण को **नीति सुधारों** पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

- **Despite** the stated objective of the scheme to uplift **marginalized communities**, the participation of **women workers** and those from the **Scheduled Castes** and **Scheduled Tribes** remained "**inconsistent across districts**."
  योजना का उद्देश्य **आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों** को ऊंचा उठाना था, लेकिन **महिला श्रमिकों** और **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** का भागीदारी विभिन्न जिलों में "**असंगत**" बनी रही।

- A **district-wise study** must be conducted to ensure that these communities receive **equal work opportunities** and **benefits** under the scheme, thereby fulfilling its intended goal of **social** and **economic inclusion**.
  एक **जिला-वार अध्ययन** किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समुदायों को योजना के तहत **समान कार्य अवसर** और **लाभ** मिलें, जिससे इसका उद्देश्य **सामाजिक** और **आर्थिक समावेशन** पूरा हो सके।

- The panel also stressed the need to **revamp** the scheme, keeping in view the "**changing times** and **emerging challenges**."
  पैनल ने योजना के **नवीनीकरण** की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे "**बदलते समय** और **उभरती चुनौतियों**" का ध्यान रखा जा सके।

- The committee urged the **Ministry of Rural Development** to explore options that could increase the **guaranteed working days** under **MGNREGA** from the current **100 days** to at least **150 days**.
  समिति ने **ग्रामीण विकास मंत्रालय** से उन विकल्पों की तलाश करने का आग्रह किया, जो **मनरेगा** के तहत **100 दिनों** से बढ़ाकर कम से कम **150 दिन** तक **गारंटीकृत कार्य दिवसों** को बढ़ा सकें।

- The **parliamentary panel** also pointed out that the scheme has been plagued by **chronic delays** in **wage payments**, leading to **uncertainty** for the workers.
  संसदीय पैनल ने यह भी指出 किया कि योजना में **वेतन भुगतान में लगातार देरी** रही है, जिससे

PATRIOTIC IAS

कार्यकर्ताओं के लिए **अनिश्चितता** पैदा हो गई है।

- The committee strongly recommended increasing the current **compensation rate** for delayed wages.
  समिति ने विलंबित वेतन के लिए वर्तमान **मुआवजा दर** बढ़ाने की **मजबूत सिफारिश** की है।

- Timely disbursement of wages is essential to maintain **trust** in the scheme and ensure uninterrupted execution of work.
  वेतन का समय पर वितरण योजना में **विश्वास** बनाए रखने और काम के बिना रुकावट के **निष्पादन** को सुनिश्चित करने के लिए **अत्यंत महत्वपूर्ण** है।

India, Africa maritime engagement exercise begins off Tanzania coast

GS Paper II: India-Africa

NEW DELHI

The inaugural edition of the large-scale multilateral exercise Africa India Key Maritime Engagement (AIKEYME) began on Sunday off Dar-es-Salaam, Tanzania.

Coinciding with the naval exercise, offshore patrol vessel *INS Sunayna*, designated as Indian Ocean Ship (IOS) SAGAR and sailing with 44 naval personnel from nine friendly nations, reached the port on Saturday.

"AIKEYME aims to develop collaborative solutions to common regional maritime challenges. This maiden initiative by the Indian Navy seeks to enhance interoperability and synergise combined operations among the maritime forces of partner nations," the Navy said in a statement.

"It also highlights the strong and friendly relations between India and the African nations." The six-day AIKEYME exercise from April 13 to 18 includes participation from Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles and South Africa, alongside the co-hosts India and Tanzania. "This initiative aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi, promoting Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions (MAHASAGAR)," the Navy said.

INS Chennai arrives in Dar-es-Salaam for the inaugural edition of the large-scale multilateral exercise AIKEYME. PTI

The *Indian Naval Ship Chennai* (destroyer) and *INS Kesari* (Landing Ship Tank - Large) arrived in Dar-es-Salaam ahead of the exercise, and the inauguration ceremony of AIKEYME was co-hosted onboard, along with the Tanzanian Peoples' Defence Force (TPDF).

A Ceremonial Guard was also paraded onboard *INS Chennai* with TPDF and Indian Navy band playing in unison the national anthems of respective countries.

India, Africa Maritime Engagement Exercise Begins off Tanzania Coast

भारत-अफ्रीका समुद्री अभ्यास तंजानिया तट पर शुरू हुआ

The inaugural edition of the Africa India Key Maritime Engagement (AIKEYME), a large-scale multilateral naval exercise, began on Sunday off the coast of Dar-es-Salaam, Tanzania.

अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता (AIKEYME) का पहला संस्करण, एक बड़े पैमाने का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, रविवार को तंजानिया के दार-एस-सलाम तट पर

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

शुरू हुआ।

- Coinciding with the naval exercise, **offshore patrol vessel INS Sunayna**, designated as **Indian Ocean Ship (IOS) SAGAR**, arrived at the port on **Saturday** with **44 naval personnel** from **nine friendly nations**.
  नौसैनिक अभ्यास के साथ-साथ **ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुयना**, जिसे **इंडियन ओशियन शिप (आईओएस) सागर** नाम दिया गया है, **शनिवार** को **9 मित्र देशों के 44 नौसैनिक कर्मियों** के साथ बंदरगाह पहुंचा।

- The Navy stated that **AIKEYME** aims to develop **collaborative solutions** to **common regional maritime challenges**.
  नौसेना ने कहा कि **AIKEYME** का उद्देश्य **आम क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों** के लिए **सहयोगात्मक समाधान** विकसित करना है।

- This **maiden initiative** by the **Indian Navy** seeks to enhance **interoperability** and **synergise combined operations** among the **maritime forces** of partner nations.
  यह **भारतीय नौसेना** की एक **पहली पहल** है जिसका उद्देश्य भागीदार देशों की **समुद्री सेनाओं** के बीच **परस्पर संचालन क्षमता** और **संयुक्त अभियानों की तालमेल** को बढ़ाना है।

- The Navy also highlighted the **strong and friendly relations** between **India** and the **African nations**.
  नौसेना ने **भारत** और **अफ्रीकी देशों** के बीच **मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों** को भी रेखांकित किया।

- The **six-day AIKEYME exercise**, from **April 13 to 18**, includes participation from **Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, and South Africa**, along with co-hosts **India** and **Tanzania**.
  13 से 18 अप्रैल तक चलने वाले **छह दिवसीय AIKEYME अभ्यास** में **कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मैडागास्कर, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका** सहित सह-मेजबान **भारत** और **तंजानिया** की भागीदारी है।

- This initiative aligns with **Prime Minister Narendra Modi's** vision of **Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions (MAHASAGAR)**.
  यह पहल **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** के **क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति (MAHASAGAR)** के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

PATRIOTIC IAS

- **INS Chennai (destroyer)** and **INS Kesari (Landing Ship Tank - Large)** arrived in **Dar-es-Salaam** ahead of the exercise.
  अभ्यास से पहले **आईएनएस चेन्नई (विध्वंसक)** और **आईएनएस केसरी (लैंडिंग शिप टैंक - लार्ज) दार-एस-सलाम** पहुंच गए।

- The **inauguration ceremony** of **AIKEYME** was co-hosted onboard by the **Indian Navy** and **Tanzanian Peoples' Defence Force (TPDF)**.
  AIKEYME का **उद्घाटन समारोह भारतीय नौसेना** और **तंजानियाई जन रक्षा बल (TPDF)** द्वारा जहाज पर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

- A **Ceremonial Guard** was paraded onboard **INS Chennai**, with **TPDF** and **Indian Navy band** playing the **national anthems** of respective countries in unison.
  आईएनएस चेन्नई पर एक **औपचारिक गार्ड** परेड किया गया, जिसमें **TPDF** और **भारतीय नौसेना बैंड** ने एक साथ संबंधित देशों के **राष्ट्रीय गान** बजाए।

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

A Governor's conduct and a judgment of significance

GS Paper II: Article 200

Suhrith Parthasarathy

is an advocate practising in the Madras High Court

The top court has reiterated a constitutional truth — that the Governor of a State is constrained by legal norms and democratic principle

Last week, in a judgment of wide-ranging significance, in *The State of Tamil Nadu vs The Governor of Tamil Nadu and Anr.*, a two-judge Bench of the Supreme Court of India, comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan, reaffirmed the limits that bind gubernatorial authority. In doing so, the Court reminded us of a constitutional truth that ought to be self-evident: the Governor of a State is neither an appendage of the Union nor an independent power centre, but is constrained by legal norms and democratic principle.

A need to respect democratic obligations

At the heart of the case was a seemingly simple but institutionally weighty question: what happens when a Governor fails to act on a Bill duly passed by the State's legislature? The answers from the Court not only helped validate a clutch of Bills passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly – each of which had languished without assent – but also contained in them a broader message. The office of the Governor, while significant, is not exempt from the obligations of representative democracy. To withhold assent indefinitely, without reason, subverts the constitutional order.

Initially numbering 12, the contested Bills trace their origins to as far as 2020, with two enacted under the previous regime in the State. Among them were Bills that sought to supplant the Governor's power to appoint Vice-Chancellors to public universities – proposals that emanated out of a long-standing skirmish between the Raj Bhavan and the elected government over institutional control.

For years, the Governor took no discernible action. When the State government moved the Supreme Court in November 2023, he promptly referred two of the Bills to the President for her consideration. The Legislative Assembly, in turn, convened a special session to reenact the remaining 10 Bills. But when these were sent to the Governor, he swiftly passed them on to the President. Since then, the President assented to only one, rejected seven outright, and left two pending.

It was this sequence of events which formed the basis for the State government's case in the Court. The Governor, through his conduct, the State claimed, had undermined the people's will. His prolonged inaction, and ultimately delayed referral, therefore, demanded judicial scrutiny.

India's federal design rests on a delicate balance. The Constitution carefully demarcates legislative authority between the Union and the States. Article 245 prescribes the territorial jurisdiction of each, allowing Parliament to legislate for the entire country or any part thereof, while State legislatures are confined to their respective territories.

The scope of legislative powers is categorised into three distinct lists outlined in the Constitution's Seventh Schedule. The Union enjoys exclusive authority over items in List I, while subjects in List III allow for legislation by both the Union and State governments. Matters in List II, on the other hand, remain under the sole legislative domain of the States. However, in the event of conflict with a parliamentary law, primacy is given to the Union legislation.

In this scheme, the Governor, though appointed by the President, functions as the constitutional head of the State. Barring specific instances where the Constitution expressly permits discretion, he is bound to act on the advice of the State's Council of Ministers.

A reading of Article 200

It is in this context that Article 200 of the Constitution, which deals with how a Governor ought to assent to a Bill, assumed significance before the Court. Much of the dispute turned on its interpretation. On a plain reading of Article 200, the Governor may: grant assent; withhold assent (and return the Bill to the Assembly for reconsideration), or reserve the Bill for the President's consideration.

The Union of India, in their response to Tamil Nadu's petition, contended that the first proviso to Article 200 provided the Governor an independent, fourth course of action: he could simply withhold his assent to a Bill, without referring it back to the Assembly. In other words, he could perform a pocket-veto.

But this argument had expressly been rejected by the Court in *State of Punjab vs Principal Secretary to the Governor of Punjab* (2023). There, it found that the proviso to Article 200 contains no independent power. Once an ordinary Bill is passed by the Assembly, the Governor has only one of three options available: to either assent to it, or reserve it for the President's consideration, or withhold the assent, in which case, the Governor must also refer it back to the Assembly for reconsideration.

It was also the Union's case that in deciding whether to reserve a Bill for the President's assent, the Governor could exercise an autonomous discretion. That is, he had the independent ability to decide what course of action to follow. In answering this argument, the Court harked to the debates in the Constituent Assembly. It noted that the draft version of Article 200 (then Article 175) had explicitly stated that the Governor "may, in his discretion" reserve a Bill for the consideration of the President. This phrase was consciously omitted in the adopted version. Its removal, the Court held, was deliberate, aimed at ensuring that the Governor's role was constrained by the advice of the elected executive.

Indeed, the Court identified only three narrow circumstances in which the Governor could act without ministerial counsel: first, where the second proviso to Article 200 applied, that is where a Bill derogated from a High Court's powers; second, where a Bill fell within a class for which presidential assent was explicitly mandated, such as under Article 31C where a law was sought to be protected from judicial review; and third, where a Bill so fundamentally undermined constitutional values.

This conclusion came with an important caveat. Even where a Governor exercises discretion, the action is still amenable to judicial review. Relying on its earlier judgment in *Rameshwar Prasad vs Union of India* (2006), the Court found that while Article 361 grants personal immunity to Governors, it does not insulate their actions from legal scrutiny. Consider the alternative: a Governor may simply paralyse the legislative process by sitting over Bills for years on end, all the while hiding behind the cloak of gubernatorial immunity, choking, in the process, the entire governance of a State.

In any event, in this case, the Court found that there was no discretion available to the Governor. Having chosen to withhold assent, he could not plausibly have then referred the Bills to the President, on their being re-presented to him. There was no trace of executive advice backing his decisions nor were his acts grounded in any identifiable, let alone defensible, constitutional rationale. Having found the Governor's actions unconstitutional, the Court could no doubt have considered issuing what the law describes as a writ of mandamus, compelling him to grant his assent to the Bills. But given the substantial time that had lapsed and given that previous Court decisions had been overlooked, the Court chose the ostensibly extreme option. With a view to achieving complete justice – a power available to it under Article 142 – it declared that these 10 Bills would be deemed to have been assented to on the date when they were re-presented to the Governor.

Some might see this as judicial overreach, but issuing a mandamus might well have been rather more unworkable. Should the Court's orders be breached, it cannot plausibly hold the Governor in contempt. Therefore, the ultimate direction must be seen as a logical *sequitur* to the Court's findings: on the Bills being passed anew by the State Assembly, and on the Council of Ministers recommending their assent, the Governor was left with no discretion in the matter.

The larger message

The significance of the judgment for the specific Bills, which were at stake, is plain to see. But the verdict also carries with it a larger message. It upholds a fact intrinsic to our Republic: that the Governor, though appointed by the Union government, functions on the aid and advice of the State executive; the office is meant to serve not as a source of political disputes, but as a constitutional sentinel, upholding the values of representative democracy.

A Governor's Conduct and a Judgment of Significance

राज्यपाल का आचरण और एक महत्वपूर्ण निर्णय

Last week, the Supreme Court of India gave a significant judgment in the case *The State of Tamil Nadu vs The Governor of Tamil Nadu and Anr.*

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

पिछले सप्ताह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनर.* मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।

- The judgment was delivered by a **two-judge Bench** comprising **Justice J.B. Pardiwala** and **Justice R. Mahadevan**.
  यह निर्णय **न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला** और **न्यायमूर्ति आर. महादेवन** की **दो-न्यायाधीशों की पीठ** द्वारा दिया गया।
- The Court reaffirmed that a **Governor** is not an **independent power centre** or an **appendage of the Union**, but is **bound by law** and **democratic principles**.
  न्यायालय ने दोहराया कि **राज्यपाल** कोई **स्वतंत्र शक्ति केंद्र** या **संघ का अंग** नहीं हैं, बल्कि वे **कानूनी नियमों** और **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** से बंधे होते हैं।

A Need to Respect Democratic Obligations
लोकतांत्रिक दायित्वों का सम्मान करने की आवश्यकता

- The central issue in the case was: what happens if a **Governor fails to act** on a **Bill passed by the State legislature**?
  इस मामले का मुख्य मुद्दा यह था: यदि **राज्यपाल** किसी **राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक** पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो क्या होता है?
- The Court validated several **Bills passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly** that had been **pending without assent**.
  न्यायालय ने **तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों** को वैध ठहराया जो **अनुमोदन के बिना लंबित** थे।
- It emphasized that the **Governor's office**, while important, is **not exempt** from the **principles of representative democracy**.
  न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि **राज्यपाल का पद** महत्वपूर्ण होते हुए भी **प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों से मुक्त नहीं** है।
- Indefinite **withholding of assent without reason** undermines the **constitutional framework**.
  बिना कारण **अनिश्चितकालीन अनुमोदन रोकना संवैधानिक ढांचे** को कमजोर करता है।

Details of the Bills and Timeline
विधेयकों का विवरण और समयरेखा

- Initially, there were **12 Bills**, some dating back to **2020**, including two from the **previous State regime**.
  प्रारंभ में **12 विधेयक** थे, जिनमें से कुछ **2020** के थे और दो **पिछली राज्य सरकार** के समय के थे।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Some of the Bills aimed to **curb the Governor's power** in appointing **Vice-Chancellors of public universities**.
  इनमें कुछ विधेयकों का उद्देश्य **राज्यपाल की शक्ति को सीमित करना** था, विशेष रूप से **राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति** के संबंध में।
- This arose from a **long-standing conflict** between the **Raj Bhavan** and the **elected State government**.
  यह मुद्दा **राजभवन** और **निर्वाचित राज्य सरकार** के बीच **लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष** का परिणाम था।

The Governor's Delayed Response
राज्यपाल की विलंबित प्रतिक्रिया

- For years, the **Governor took no action** on these Bills.
  कई वर्षों तक, इन विधेयकों पर **राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की**।
- When the State approached the Supreme Court in **November 2023**, he **referred two Bills** to the **President**.
  जब राज्य सरकार ने **नवंबर 2023** में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तब उन्होंने **दो विधेयकों को राष्ट्रपति** के पास भेजा।
- The **Legislative Assembly** then held a **special session** to **reenact the remaining 10 Bills**.
  इसके बाद **विधानसभा** ने एक **विशेष सत्र** आयोजित करके **शेष 10 विधेयकों को पुनः पारित** किया।
- The Governor again **forwarded them to the President** without action.
  राज्यपाल ने उन विधेयकों को भी **राष्ट्रपति के पास भेज दिया**, बिना किसी कार्रवाई के।
- Eventually, the **President approved only one**, **rejected seven**, and kept **two pending**.
  अंततः **राष्ट्रपति ने केवल एक विधेयक को मंजूरी दी**, **सात को अस्वीकार कर दिया**, और **दो को लंबित रखा**।

Arguments Presented by the State Government
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क

- The State argued that the Governor's **inaction and delays** had **undermined the will of the people**.
  राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्यपाल की **निष्क्रियता और देरी** ने **जनता की इच्छाशक्ति को कमजोर** किया।
- These actions necessitated **judicial scrutiny**.
  इन कार्रवाइयों के कारण **न्यायिक जांच आवश्यक** हो गई।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

The Constitutional Framework and Federal Structure
संवैधानिक ढांचा और संघीय संरचना

- India's federal system depends on a **delicate balance** of power between the **Union and the States**.
  भारत की संघीय व्यवस्था **संघ और राज्यों के बीच संतुलन** पर आधारित है।
- **Article 245** defines the **territorial jurisdiction** of legislative powers.
  अनुच्छेद 245 विधान शक्ति की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करता है।
- The **Seventh Schedule** divides subjects into **three lists**:
  सातवीं अनुसूची विषयों को **तीन सूचियों** में विभाजित करती है:
  - **List I (Union List)** — exclusive to Parliament.
    सूची I (संघ सूची) — केवल संसद के लिए आरक्षित।
  - **List II (State List)** — exclusive to State legislatures.
    सूची II (राज्य सूची) — केवल राज्य विधानमंडलों के लिए।
  - **List III (Concurrent List)** — allows both Union and States to legislate.
    सूची III (समवर्ती सूची) — इसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- In case of a **conflict**, the **Union law prevails** over the State law.
  किसी **संघर्ष** की स्थिति में **संघ का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी** होता है।

Role and Powers of the Governor
राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ

- The **Governor**, though appointed by the **President**, functions as the **constitutional head** of the State.
  राज्यपाल, भले ही **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** हों, लेकिन वे राज्य के **संवैधानिक प्रमुख** के रूप में कार्य करते हैं।
- Except in certain circumstances, the Governor is **bound to act** on the **advice of the State's Council of Ministers**.
  कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, राज्यपाल को **राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है**।

A Reading of Article 200
अनुच्छेद 200 का विश्लेषण

- **Article 200** of the Constitution became important in a case concerning the Governor's role in giving assent to a Bill.
  संविधान का **अनुच्छेद 200** किसी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति को लेकर एक मामले में महत्वपूर्ण बन गया।

PATRIOTIC IAS

- As per **Article 200**, the Governor can **grant assent**, **withhold assent and return the Bill for reconsideration**, or **reserve the Bill for the President's consideration**.
  अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल **स्वीकृति दे सकते हैं**, **स्वीकृति रोककर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं**, या **राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं**।
- The **Union of India** argued that the Governor had a **fourth option** — to withhold assent **without returning the Bill**, similar to a **pocket veto**.
  भारत सरकार ने तर्क दिया कि राज्यपाल के पास एक **चौथा विकल्प** है — वह विधेयक को **वापस किए बिना स्वीकृति रोक सकते हैं**, जिसे **पॉकेट वीटो** कहा जा सकता है।
- This idea was rejected in the **2023 judgment** in **State of Punjab vs Principal Secretary to the Governor of Punjab**.
  यह तर्क **2023 के निर्णय** में, **पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव** में खारिज कर दिया गया था।
- The Court held that the Governor has only **three options — assent**, **return for reconsideration**, or **reserve for the President**.
  न्यायालय ने माना कि राज्यपाल के पास केवल **तीन विकल्प** हैं — **स्वीकृति देना**, **पुनर्विचार हेतु लौटाना**, या **राष्ट्रपति को भेजना**।
- The Union also said the Governor can use **independent discretion** to reserve Bills for the President.
  केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यपाल **स्वतंत्र विवेकाधिकार** से विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
- The Court referred to **Constituent Assembly Debates**, where the original draft had the phrase "**in his discretion**", which was **deliberately removed**.
  न्यायालय ने **संविधान सभा की बहसों** का हवाला दिया, जहाँ प्रारूप में "**अपने विवेक से**" शब्द था, जिसे **जानबूझकर हटा दिया गया** था।
- The removal of this phrase showed the intention to **limit the Governor's powers** and bind him to **ministerial advice**.
  इस शब्द को हटाने से यह स्पष्ट हुआ कि राज्यपाल की शक्तियों को **सीमित करने** और उन्हें **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर कार्य करने के लिए बाध्य करने की मंशा थी।
- The Court identified **three exceptions** where the Governor can act **without ministerial advice**:
  न्यायालय ने **तीन अपवाद** पहचाने जहाँ राज्यपाल **बिना मंत्रिपरिषद की सलाह** के कार्य कर सकते हैं:
  - If a Bill **derogates High Court powers** (under the **second proviso to Article 200**).
    यदि कोई विधेयक **उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है** (**अनुच्छेद 200 की दूसरी व्याख्या** के अंतर्गत)।
  - If a Bill needs **mandatory presidential assent** (like under **Article 31C**).
    यदि किसी विधेयक के लिए **अनिवार्य राष्ट्रपति की स्वीकृति** जरूरी हो (**अनुच्छेद 31C** के तहत)।

PATRIOTIC IAS

- If a Bill **undermines constitutional values**.
  यदि कोई विधेयक **संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता हो**।

- Even if the Governor uses discretion, the action is subject to **judicial review**.
  भले ही राज्यपाल विवेक का प्रयोग करें, उनका कार्य **न्यायिक समीक्षा** के अंतर्गत आता है।
- The Court cited **Rameshwar Prasad vs Union of India (2006)** to say that while **Article 361** gives **personal immunity** to the Governor, it doesn't protect his **actions**.
  न्यायालय ने **रमेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार (2006)** का हवाला दिया कि **अनुच्छेद 361** राज्यपाल को **व्यक्तिगत प्रतिरक्षा** देता है, लेकिन उनके **कृत्यों** को नहीं।
- Otherwise, a Governor could **stall the legislative process** for **years**, hiding behind **immunity**.
  अन्यथा राज्यपाल **प्रतिरक्षा** का बहाना बनाकर **वर्षों तक विधायी प्रक्रिया को रोक सकते हैं**।
- In this case, the Court found the Governor had **no discretion** once the Bills were re-presented.
  इस मामले में न्यायालय ने पाया कि विधेयकों के पुनः प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्यपाल के पास **कोई विवेकाधिकार नहीं था**।
- The Governor had **no executive advice** and provided **no valid constitutional basis** for his actions.
  राज्यपाल के पास **कोई कार्यपालिका की सलाह नहीं थी** और उनके कार्यों का **कोई वैध संवैधानिक आधार नहीं था**।
- The Court could have issued a **writ of mandamus**, but due to **long delays**, it invoked **Article 142** instead.
  न्यायालय एक **मैंडेमस रिट** जारी कर सकता था, लेकिन **लंबी देरी** के कारण उसने **अनुच्छेद 142** का प्रयोग किया।
- It declared that the **10 Bills** would be **deemed to have been assented to** on the date they were re-submitted.
  न्यायालय ने घोषित किया कि **10 विधेयक** उस दिन से **स्वीकृत माने जाएंगे**, जिस दिन उन्हें दोबारा प्रस्तुत किया गया था।
- While some may see this as **judicial overreach**, mandamus would have been **ineffective**, as **Governors cannot be held in contempt**.
  कुछ लोग इसे **न्यायिक अतिक्रमण** मान सकते हैं, लेकिन मैंडेमस **अप्रभावी** होता क्योंकि **राज्यपाल को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता**।
- The Court's order was a **logical result** of its findings — once the Assembly passed the Bills and ministers advised assent, the **Governor had no option**.
  न्यायालय का आदेश उसके निष्कर्षों का **तार्किक परिणाम** था — जब विधानसभा ने विधेयक पारित किए और मंत्रियों ने स्वीकृति की सिफारिश की, तो **राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं था**।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

The Larger Message
विस्तृत संदेश

- The verdict is important not only for the **10 Bills**, but also for the **principle of democratic governance**.
  यह निर्णय केवल **10 विधेयकों** के लिए ही नहीं, बल्कि **लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत** के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- It reaffirms that although the **Governor is appointed by the Union**, he functions on the **aid and advice of the State executive**.
  यह पुष्टि करता है कि भले ही **राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है**, वह **राज्य कार्यपालिका की सलाह और सहायता** से कार्य करता है।
- The Governor's role is not to **interfere politically**, but to act as a **constitutional guardian** of **representative democracy**.
  राज्यपाल की भूमिका **राजनीतिक हस्तक्षेप** की नहीं, बल्कि **प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र** के **संवैधानिक रक्षक** के रूप में होती है।

Adding a French touch to India's Olympic dream

GS Paper II: India-France

The Paralympic Games were extraordinary organisational, popular and sporting successes, and hailed as such worldwide. The stunning venues and ceremonies in the heart of the city of love and across France, the memorable prowess of the athletes, and the unbridled enthusiasm throughout the country thrilled spectators and television viewers around the world. The Games built bridges and brought people together – which is all the more important in the current geopolitical context.

France is grateful that India fully participated in the festivities and contributed to the success of the Games. The Indian Paralympic delegation made a record-breaking performance in Paris, reaching the 18th position in the medals tally. Further, under an international cooperation framework, India sent K9 teams (canine) abroad for the first time to patrol various Olympic venues, reinforcing France's meticulously-planned security arrangements. The first Indian hospitality centre in the Games' history, India House, was set up during the 2024 Olympics and opened to visitors strolling through the iconic "Nations Park".

Expertise that will be shared

Paris 2024 was also the most sustainable and inclusive Games. It reduced the carbon footprint of the Games by 54.6% when compared with the average for the London 2012 and Rio 2016 Games, setting new standards for international sporting events and their impact on the people. It made history by achieving gender parity with the equal participation of male and female athletes, and invested massively to make the Games accessible for spectators with disabilities. These achievements were made possible by bold and innovative approaches and the great collective effort of France's central and regional governments, the Olympic Organising Committee, various sports movements and sponsoring companies. France has developed very special and comprehensive expertise that it now aims to share with its partners under its sports diplomacy. This is one of the main objectives of my visit to India.

Samuel Ducroquet
is France's Ambassador-at-Large for Sport

Paris is working to boost India-France sports cooperation and share its expertise in organising major sporting events

India's Olympic bid

France has also noted how sports have been playing an increasingly important role in Indian society and economy, with Prime Minister Narendra Modi recently upholding sports as an "essential aspect in the development of the country". Besides India's 2036 Games bid and, more broadly, the organisation of international sporting events, the Indian authorities and sports movements are proactively developing sporting practices and focusing on improving performance, as recently demonstrated by the decision to establish 10 Olympic training centres across the nation.

Sports are hence another area of cooperation with promising prospects. Mutual interest in deepening exchanges have been expressed at the highest levels: President Emmanuel Macron and Mr. Modi highlighted this during the French President's visit to India in January 2024 and more recently, Mr. Modi's visit to France in February 2025.

In July 2023, a joint declaration of intent on sports was concluded between our respective sports ministries to increase exchanges between sports delegations and federations, economic actors of the sports industry, and experts of international sporting events. In January 2024, the India-France Joint Statement welcomed the strengthening of sports cooperation and reaffirmed that France would share its experience of hosting the Paris 2024 Games with India as it bids to host the 2036 Games.

Against this backdrop, my mission in Delhi and Chennai as Ambassador-at-Large for Sport aims to enhance France's understanding of India's sports ecosystem and meet its various institutional and economical players to deepen already identified areas of cooperation and explore new ones.

The sharing of expertise in organising major international sporting events, as well as their long-term social and environmental legacy, has already begun. Institutional exchanges have been taking place, with several delegations from India's Ministry of Youth Affairs and Sports having visited France in September 2024 during the Paralympic Games. As India's 2036 project takes shape, my visit will help identify India's needs more precisely, so that our dialogue can advance in line with India's targeted priorities.

A vibrant industry that has much to offer

The medium-term idea is also to bring new players to the table, particularly economic ones. The French sports industry is particularly dynamic: in 2023, it generated a turnover of €75 billion (₹6.7 lakh crore approximately at that time), which is much higher, for example, than that of the aerospace industry (€65 billion). With around 1,28,000 companies of all sizes, its offering is diverse, ranging from construction, major equipment, data analysis, to ticketing and consumer experience. While some of these companies, such as Decathlon, are already household names in the Indian market, many are looking to expand here soon. We are also seeing promising new partnerships, including the recent one between Tata Consultancy Services and Amaury Sport Organisation for the Paris Marathon.

Lastly, enhancing exchanges between our two countries' sports movements and professionals – such as athletes or coaches – is a constant priority for France's sports diplomacy, the main goal being to boost youth exchanges with India. In this regard, one of the most recent success stories is that of the Indian and French surfing federations, which signed a cooperation agreement last November, under which four Indians under 21 years of age were invited to participate in an international competition in Reunion Island, a French overseas territory in the Indian Ocean.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Adding a French Touch to India's Olympic Dream
भारत के ओलंपिक सपने में फ्रांसीसी स्पर्श

The 2024 Paris Olympic and Paralympic Games
2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेल

- The **2024 Paris Olympic and Paralympic Games** were extraordinary in terms of organisation, public engagement, and athletic performance, and were praised globally.
  2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन, जनभागीदारी और खेल प्रदर्शन के लिहाज से असाधारण थे, और इन्हें वैश्विक स्तर पर सराहा गया।

- The **stunning venues**, **ceremonies** in the heart of Paris and across France, and the **memorable performances** by athletes thrilled spectators and viewers worldwide.
  पेरिस और पूरे फ्रांस में स्थित **शानदार स्थल**, **समारोह**, और खिलाड़ियों का **यादगार प्रदर्शन** दर्शकों और दुनियाभर के टीवी दर्शकों को रोमांचित कर गया।

- The Games built **bridges between people** and fostered unity, which is especially important in the current **geopolitical context**.
  इन खेलों ने **लोगों के बीच पुल बनाए** और एकता को बढ़ावा दिया, जो वर्तमान **भू-राजनीतिक माहौल** में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

India's Participation and Contribution
भारत की भागीदारी और योगदान

- **France** appreciated India's **full participation**, which contributed to the overall success of the Games.
  फ्रांस ने भारत की **पूर्ण भागीदारी** की सराहना की, जिसने खेलों की समग्र सफलता में योगदान दिया।

- The **Indian Paralympic delegation** delivered a **record-breaking performance**, securing the **18th position** in the medals tally.
  भारतीय पैरालंपिक दल ने **रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन** किया और **18वां स्थान** हासिल किया।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Under an **international cooperation framework**, India sent **K9 (canine) teams** abroad for the **first time** to patrol Olympic venues and support **France's security plans**.
  अंतरराष्ट्रीय सहयोग ढांचे के तहत, भारत ने पहली बार **K9 (कैनाइन) टीमें** विदेश भेजीं ताकि ओलंपिक स्थलों की सुरक्षा में **फ्रांस की योजनाओं को समर्थन** मिल सके।

- For the first time in Olympic history, **India House**, an **Indian hospitality centre**, was set up and welcomed visitors in the iconic **"Nations Park"**.
  ओलंपिक इतिहास में पहली बार, **इंडिया हाउस** नामक एक **भारतीय आतिथ्य केंद्र** स्थापित किया गया, जो प्रतिष्ठित **"नेशंस पार्क"** में आगंतुकों के लिए खुला रहा।

Expertise That Will Be Shared
साझा की जाने वाली विशेषज्ञता

- **Paris 2024** was the most **sustainable** and **inclusive Games** ever organised.
  पेरिस 2024 अब तक के सबसे **सतत** और **समावेशी खेल** रहे।

- The Games reduced the **carbon footprint** by **54.6%** compared to the **London 2012** and **Rio 2016** Games.
  इन खेलों ने **लंदन 2012** और **रियो 2016** की तुलना में **54.6% कार्बन उत्सर्जन में कमी** की।

- They set **new global standards** for **international sporting events** and their **impact on people**.
  उन्होंने **अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों** और उनके **जनता पर प्रभाव** के लिए **नए वैश्विक मानक** स्थापित किए।

- The Games made history by achieving **gender parity**, with **equal participation** of **male and female athletes**.
  इन खेलों ने **लैंगिक समानता** हासिल कर इतिहास रच दिया, जिसमें **पुरुष और महिला खिलाड़ियों की बराबर भागीदारी** थी।

- Huge investments were made to ensure **accessibility** for **spectators with disabilities**.
  विकलांग दर्शकों की **सुलभता** सुनिश्चित करने के लिए भारी निवेश किया गया।

PATRIOTIC IAS

- These successes were made possible by **innovative methods** and **cooperation** between **France's central and regional governments**, the **Olympic Organising Committee**, **sports organisations**, and **sponsoring companies**.
  ये सफलताएं **नवोन्मेषी तरीकों** और **फ्रांस की केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों**, **ओलंपिक आयोजन समिति**, **खेल संगठनों**, और **प्रायोजक कंपनियों** के **सहयोग** से संभव हुईं।

- France has developed **unique and comprehensive expertise**, which it now wishes to share with **international partners** through **sports diplomacy**.
  फ्रांस ने **विशेष और व्यापक विशेषज्ञता** विकसित की है, जिसे वह अब **खेल कूटनीति** के माध्यम से **अंतरराष्ट्रीय भागीदारों** के साथ साझा करना चाहता है।

- Sharing this expertise is one of the **main goals** of the **French envoy's visit** to India.
  इस विशेषज्ञता को साझा करना **फ्रांसीसी प्रतिनिधि की भारत यात्रा** का एक **मुख्य उद्देश्य** है।

India's Olympic Bid
भारत की ओलंपिक बोली

- France has noted that **sports** are playing an increasingly **important role** in **Indian society and economy**.
  फ्रांस ने देखा है कि **खेल** भारत के **समाज और अर्थव्यवस्था** में तेजी से **महत्वपूर्ण भूमिका** निभा रहे हैं।

- **Prime Minister Narendra Modi** recently emphasised sports as an **essential aspect** in the **development of the country**.
  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खेलों को देश के **विकास का एक अनिवार्य पहलू** बताया।

- In line with India's **2036 Olympic bid** and other international events, Indian authorities are actively promoting **sporting practices** and improving **performance**.
  भारत की **2036 ओलंपिक बोली** और अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के तहत, भारतीय प्रशासन सक्रिय रूप से **खेल गतिविधियों** को बढ़ावा दे रहा है और **प्रदर्शन में सुधार** पर ध्यान दे रहा है।

- India has announced the creation of **10 Olympic training centres** across the country.
  भारत ने देशभर में **10 ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित करने की घोषणा की है।

PATRIOTIC IAS

India-France Cooperation in Sports

भारत-फ्रांस खेल सहयोग

- Sports have become another area of **promising cooperation** between India and France.
  खेल भारत और फ्रांस के बीच एक और **उम्मीदभरा सहयोग क्षेत्र** बन गया है।

- **President Emmanuel Macron** and **Prime Minister Modi** have expressed **mutual interest** in enhancing sports exchanges.
  राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और **प्रधानमंत्री मोदी** ने खेलों में **आपसी सहयोग बढ़ाने** में रुचि जताई है।

- This was highlighted during Macron's visit to India in **January 2024** and Modi's visit to France in **February 2025**.
  यह बात **जनवरी 2024** में मैक्रों की भारत यात्रा और **फरवरी 2025** में मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रेखांकित की गई थी।

- A **joint declaration of intent** on sports was signed in **July 2023** between both countries' sports ministries.
  जुलाई 2023 में दोनों देशों के खेल मंत्रालयों के बीच खेलों पर एक **संयुक्त अभिप्राय घोषणा** पर हस्ताक्षर किए गए।

- The declaration aimed to increase exchanges among **sports delegations**, **federations**, **industry players**, and **event experts**.
  इस घोषणा का उद्देश्य **खेल प्रतिनिधिमंडलों**, **संघों**, **उद्योग के साझेदारों**, और **आयोजन विशेषज्ञों** के बीच सहयोग बढ़ाना था।

- In **January 2024**, the **India-France Joint Statement** reaffirmed that **France would share its experience** of hosting **Paris 2024 Games** with India.
  जनवरी 2024 में, **भारत-फ्रांस संयुक्त बयान** में यह दोहराया गया कि **फ्रांस अपने पेरिस 2024 खेलों के अनुभव** को भारत के साथ साझा करेगा।

PATRIOTIC IAS

Ambassador's Mission in India
भारत में राजदूत का मिशन

- The **Ambassador-at-Large for Sport** visited **Delhi and Chennai** to understand India's **sports ecosystem**.
  खेलों के लिए विशेष राजदूत ने **दिल्ली और चेन्नई** का दौरा किया ताकि भारत की **खेल प्रणाली** को समझा जा सके।

- The goal is to meet **institutional** and **economic stakeholders** and identify current and new **areas of cooperation**.
  उद्देश्य यह है कि **संस्थागत** और **आर्थिक साझेदारों** से मुलाकात की जाए और वर्तमान एवं नए **सहयोग क्षेत्रों** की पहचान की जाए।

- **Institutional exchanges** have already begun, with delegations from India's **Ministry of Youth Affairs and Sports** visiting **France in September 2024**.
  संस्थागत आदान-प्रदान पहले ही शुरू हो चुका है, भारत के **युवा मामले और खेल मंत्रालय** के प्रतिनिधिमंडल ने **सितंबर 2024** में **फ्रांस का दौरा** किया।

- As India's **2036 Olympic project** takes shape, the Ambassador's visit will help **define India's priorities** and advance the dialogue.
  जैसे-जैसे भारत की **2036 ओलंपिक परियोजना** आकार ले रही है, राजदूत की यह यात्रा भारत की **प्राथमिकताओं को स्पष्ट** करने और संवाद को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

A Vibrant Industry with Much to Offer
एक जीवंत उद्योग जिसकी पेशकश बहुत कुछ है

- The plan is also to bring in more **economic players** into the partnership.
  योजना यह भी है कि अधिक **आर्थिक साझेदारों** को सहयोग में शामिल किया जाए।

- The **French sports industry** is very **dynamic**, generating a turnover of **€75 billion** (around **₹6.7 lakh crore**) in **2023**.
  फ्रांसीसी खेल उद्योग बहुत **सक्रिय** है और इसने **2023** में **€75 बिलियन (लगभग ₹6.7 लाख करोड़)** का कारोबार किया।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- This figure is even higher than the turnover of the **aerospace industry (€65 billion)**.
  यह आंकड़ा **एयरोस्पेस उद्योग (€65 बिलियन)** से भी अधिक है।

- With around **1,28,000 companies**, the sector covers areas such as **construction**, **equipment**, **data analysis**, **ticketing**, and **consumer experience**.
  लगभग **1,28,000 कंपनियों** के साथ, यह क्षेत्र **निर्माण**, **उपकरण**, **डेटा विश्लेषण**, **टिकटिंग**, और **उपभोक्ता अनुभव** जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है।

- Some companies like **Decathlon** are already popular in India, while many others plan to expand here soon.
  कुछ कंपनियां जैसे **डेकाथलॉन** पहले से ही भारत में लोकप्रिय हैं, जबकि कई अन्य जल्द ही यहां विस्तार की योजना बना रही हैं।

- Promising partnerships are emerging, like the recent one between **Tata Consultancy Services (TCS)** and **Amaury Sport Organisation** for the **Paris Marathon**.
  टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और **अमॉरी स्पोर्ट ऑर्गनाइजेशन** के बीच **पेरिस मैराथन** के लिए हालिया साझेदारी जैसे **उम्मीदभरे सहयोग** उभर रहे हैं।

Strengthening Youth Exchanges and Professional Cooperation
युवा आदान-प्रदान और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना

- France places a **high priority** on enhancing **sports exchanges**, particularly among **athletes** and **coaches**.
  फ्रांस **खिलाड़ियों** और **कोचों** के बीच **खेल आदान-प्रदान को मजबूत करने** को **उच्च प्राथमिकता** देता है।

- The **main goal** is to boost **youth exchanges** between France and India.
  इसका **मुख्य उद्देश्य** फ्रांस और भारत के बीच **युवा आदान-प्रदान** को बढ़ावा देना है।

- A recent success story is the cooperation agreement between the **Indian and French surfing federations** signed in **November**.
  हालिया एक सफलता की कहानी **भारतीय और फ्रांसीसी सर्फिंग संघों** के बीच **नवंबर** में हस्ताक्षरित **सहयोग समझौता** है।

PATRIOTIC IAS

Under this agreement, **four Indian surfers under 21** were invited to participate in an **international competition** at **Reunion Island**, a **French overseas territory**. इस समझौते के तहत **21 वर्ष से कम आयु के चार भारतीय सर्फर** को **रीयूनियन द्वीप**, जो एक **फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र** है, में आयोजित **अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता** में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. **CAPF deployed in Murshidabad; situation under control, says DGP**
   मुर्शिदाबाद में CAPF की तैनाती; स्थिति नियंत्रण में है, DGP ने कहा
2. **India's Smartphone Exports to U.S. to Get Tariff Edge Over China**
   अमेरिका को भारत के स्मार्टफोन निर्यात को चीन पर टैरिफ बढ़त मिलेगी
3. **Experts Share Insights on Spinal Health and its Impact on Human Well-being**
   रीढ़ की सेहत और मानव कल्याण पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों ने साझा की जानकारियां
4. **FPIs Withdraw ₹31,575 Crore from Equities This Month**
   एफपीआई ने इस महीने शेयर बाजार से ₹31,575 करोड़ की निकासी की
5. **DRDO Tests Laser Weapon System That Can Disable Missiles and Drones**
   डीआरडीओ ने मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय करने वाली लेज़र हथियार प्रणाली का परीक्षण किया
6. **BatEchoMon: India's First Automated Bat Monitoring and Detection System**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

BatEchoMon: भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली

7. Saving Traditional Varieties of Seeds
पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण

8. Will Trump's Tariffs Bring in a Recession?
क्या ट्रंप के टैरिफ़ मंदी लाएंगे?

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

CAPF deployed in Murshidabad; situation under control, says DGP

Congress calls for all-party meeting, BJP takes to the streets in Kolkata, Trinamool alleges spread of misinformation; over 150 arrested in connection with the violence; BJP MP urges Amit Shah to declare select districts a 'disturbed area'

GS Paper III: Internal Security

Shiv Sahay Singh
KOLKATA

Seventeen companies of the Central Armed Police Forces (CAPF) were deployed in Murshidabad district of West Bengal on Sunday following violent protests over the Waqf (Amendment) Act that claimed three lives on Saturday.

Over 150 people were arrested, and one person who sustained a bullet injury was admitted to a State-run health facility, the police said.

Director-General of Police, West Bengal, Rajeev Kumar held meetings with senior police officials in Murshidabad. He said the situation was "very much under control".

Ananda Roy, Superintendent of Police, Jangipur, appealed to people not to believe in rumours and approach the police in case they need any clarifications. The SP said 155 persons had been arrested so far in connection with the violence.

A total of 23 high-ranking officers from the State police and other agencies have been deployed in the violence-affected district.

On alert: BSF personnel near the wreckage caused during the violence in Murshidabad, on Sunday. ANI

Karni Singh Shekhawat, Inspector-General of Police, Border Security Force, was among those present in the district. Nine companies of the BSF have been moved to the strife-torn areas.

Eighteen police personnel were injured in the violence.

Isha Khan Chowdhury, Congress MP for the Malda Dakshin constituency under which the violence-affected areas of Murshidabad district fall, said that he and Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury had called for an all-party meeting on the violence.

Almost the entire leadership of the State BJP unit took to the streets in Kolkata on Sunday in protest against the violence.

BJP MP Jyotirmoy Singh Mahato wrote to Union Home Minister Amit Shah urging the Centre to declare select border districts of West Bengal "disturbed areas".

State BJP president Sukanta Majumdar alleged that the violence was a "conspiracy of radical outfits such as the Popular Front of India [PFI] and the Students Islamic Movement of India [SIMI]".

A section of BJP leaders also claimed that hundreds of Hindus from Dhulian in Murshidabad have been forced to take shelter across the river at Baishnabnagar in neighbouring Malda district.

EDITORIAL
» PAGE 8

CAPF deployed in Murshidabad; situation under control, says DGP

मुर्शिदाबाद में CAPF की तैनाती; स्थिति नियंत्रण में है, DGP ने कहा

Seventeen companies of the Central Armed Police Forces (CAPF) were deployed in Murshidabad district of West Bengal on Sunday following violent protests over the Waqf (Amendment) Act that claimed three lives on Saturday.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर हुए हिंसक विरोध के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 17 कंपनियां तैनात की गईं। यह हिंसा शनिवार को तीन लोगों की मौत का कारण बनी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Over **150 people** were arrested, and one person who sustained a **bullet injury** was admitted to a **State-run health facility**, the police said.
  पुलिस के अनुसार, **150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार** किया गया और एक व्यक्ति को **गोलियों की चोट** लगने के बाद **सरकारी अस्पताल में भर्ती** कराया गया।
- **Director-General of Police (DGP)** of West Bengal, **Rajeev Kumar**, held meetings with senior police officials in Murshidabad and said the situation was "**very much under control**."
  पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार ने मुर्शिदाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि **स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में** है।
- **Ananda Roy**, Superintendent of Police (SP), Jangipur, appealed to people not to believe in **rumours** and approach the police for any **clarifications**.
  जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक आनंद रॉय ने लोगों से **अफवाहों पर विश्वास न करने** और किसी भी **स्पष्टीकरण** के लिए पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
- The SP said that **155 persons** had been arrested so far in connection with the violence.
  SP ने बताया कि हिंसा के संबंध में अब तक **155 लोगों को गिरफ्तार** किया गया है।
- A total of **23 high-ranking officers** from the State police and other agencies have been deployed in the **violence-affected district**.
  राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के 23 उच्चाधिकारी हिंसा-प्रभावित जिले में तैनात किए गए हैं।
- **Karni Singh Shekhawat**, Inspector-General of Police, **Border Security Force (BSF)**, was present in the district. **Nine BSF companies** were deployed in **strife-torn areas**.
  सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पुलिस महानिरीक्षक कर्णी सिंह शेखावत जिले में मौजूद रहे। **BSF की 9 कंपनियां हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों** में तैनात की गईं।
- **Eighteen police personnel** were injured in the violence.
  हिंसा में **18 पुलिसकर्मी घायल** हुए।
- **Congress MP Isha Khan Chowdhury**, representing **Malda Dakshin**, said he and **Adhir Ranjan Chowdhury** have called for an **all-party meeting** on the violence.
  मालदा दक्षिण से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने कहा कि उन्होंने और **अधीर रंजन चौधरी** ने हिंसा पर **सर्वदलीय बैठक** बुलाई है।
- Almost the entire leadership of the **State BJP** took to the **streets in Kolkata** on Sunday in **protest** against the violence.
  राज्य भाजपा नेतृत्व का अधिकांश हिस्सा रविवार को **कोलकाता की सड़कों पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन** में उतरा।
- **BJP MP Jyotirmoy Singh Mahato** wrote to **Union Home Minister Amit Shah** urging the Centre to declare select **border districts of West Bengal as 'disturbed areas'.**
  भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह माहतो ने **केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह** को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के कुछ **सीमा जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित** करने की मांग की।
- **State BJP president Sukanta Majumdar** alleged the violence was a **conspiracy** of radical outfits like **Popular Front of India (PFI)** and **Students Islamic Movement of India (SIMI)**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि यह हिंसा **कट्टरपंथी संगठनों जैसे PFI और SIMI की साजिश** थी।

- Some BJP leaders claimed that **hundreds of Hindus** from **Dhulian in Murshidabad** had to take **shelter in Baishnabnagar**, across the river in **Malda district**.
  कुछ भाजपा नेताओं ने दावा किया कि **मुर्शिदाबाद के धूलियन से सैकड़ों हिंदू** को भागकर **मालदा जिले के बैष्णबनगर** में **नदी पार शरण लेनी पड़ी**।

India's smartphone exports to U.S. to get tariff edge over China

GS Paper III: External Sector

NEW DELHI

Export of iPhones, smartphones, tablets, laptops from India to the U.S. will be cheaper by 20% compared with those shipped from China following the exemptions given by the Trump administration, industry body ICEA said on Sunday.

The U.S. government on Saturday amended its tariff order to exempt smartphones, tablets, laptops, and some other electronic devices from the new taxes.

"China still has 20% of iPhones, laptops, tablets, and watches. Only reciprocal tariff has been removed for China. India has zero tariff on iPhones and all smartphones, laptops and tablets exported to the U.S. So India enjoys a 20% tariff advantage over China," ICEA chairman Pankaj Mohindroo said.

India Cellular and Electronics Association (ICEA) represents major smartphone companies and their manufacturers, including Apple, Foxconn, Dixon, etc.

Apple's iPhone ecosystem in India has become the largest job creator in India and is one of the top exported items from the country.

According to ICEA, mobile phone exports from India have crossed an all-time high of ₹2 lakh crore in 2024-25, registering a 55% growth over the ₹1.29 lakh crore recorded in 2023-24. Union Minister Ashwini Vaishnaw has said that iPhones alone accounted for ₹1.5 lakh crore worth of exports in the smartphone segment.

The reciprocal tariff regime announced by U.S. President Donald Trump had raised concerns on Apple's iPhone production plan in China and India.

However, in a relief for the sector, the Trump administration on Saturday (as per Indian Standard Time) said they will exclude electronics like smartphones and laptops from reciprocal tariffs imposed on China as well as other countries. The move can help keep prices down for popular consumer electronics goods that are not usually made in the U.S.

U.S. Customs and Border Protection said items like smartphones, laptops, hard drives, flat-panel monitors and some chips would qualify for the exemption. Machines used to make semiconductors are excluded too.

Apple's iPhone ecosystem has become one of the top exported items. REUTERS

India's Smartphone Exports to U.S. to Get Tariff Edge Over China

अमेरिका को भारत के स्मार्टफोन निर्यात को चीन पर टैरिफ बढ़त मिलेगी

Export of iPhones, smartphones, tablets, and laptops from India to the U.S. will be 20% cheaper compared to those from China, due to tariff exemptions by the Trump administration.

ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ छूट दिए जाने के कारण भारत से अमेरिका को आईफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप का निर्यात चीन की तुलना में 20% सस्ता होगा।

- The **U.S. government** has **amended** its tariff order to **exempt smartphones, tablets, laptops,** and other electronics from **new taxes**.
  अमेरिकी सरकार ने नए करों से **स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** को **छूट** देने के लिए अपने टैरिफ आदेश में **संशोधन** किया है।

- **India has zero tariff** on exported **iPhones and other smart devices**, giving it a **20% tariff advantage** over **China**, which still has 20% duties.
  भारत में निर्यात किए गए आईफोन और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर **शून्य टैरिफ** है, जिससे उसे **चीन पर 20% का लाभ** मिलता है, जहां अभी भी 20% शुल्क है।

- The **India Cellular and Electronics Association (ICEA)** represents companies like **Apple, Foxconn, Dixon**, etc.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) कंपनियों जैसे **एप्पल, फॉक्सकॉन, डिक्सन** आदि का प्रतिनिधित्व करता है।

- **Apple's iPhone ecosystem** in India has become the **largest job creator** and is one of the **top exported items** from the country.
  भारत में **एप्पल का आईफोन ईकोसिस्टम सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता** बन गया है और **शीर्ष निर्यातित उत्पादों** में शामिल है।

- **Mobile phone exports** from India touched a **record ₹2 lakh crore** in **2024-25**, growing by **55%** over **₹1.29 lakh crore** in **2023-24**, according to **ICEA**.
  ICEA के अनुसार, **2024-25 में भारत से मोबाइल फोन निर्यात ₹2 लाख करोड़** के **रिकॉर्ड स्तर** पर पहुंचा, जो कि **2023-24 के ₹1.29 लाख करोड़** की तुलना में **55% अधिक** है।

- **iPhones alone** accounted for **₹1.5 lakh crore** of the total smartphone exports, said **Union Minister Ashwini Vaishnaw**.
  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि **सिर्फ आईफोन का निर्यात** ही **₹1.5 लाख करोड़** रहा।

- The **reciprocal tariff regime** announced earlier by **President Trump** had raised concerns for **Apple's manufacturing in China and India**.
  राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पहले घोषित पारस्परिक टैरिफ नीति ने **चीन और भारत में एप्पल के निर्माण** को लेकर चिंता बढ़ा दी थी।

- In a **relief**, the **Trump administration** announced on **Saturday (IST)** that **smartphones, laptops**, and other electronics will be **exempt** from these tariffs.
  शनिवार (भारतीय समयानुसार) को **ट्रम्प प्रशासन** ने राहत देते हुए कहा कि **स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स** को इन **टैरिफ से छूट** दी जाएगी।

- The move is expected to **keep prices stable** for **consumer electronics**, which are **rarely manufactured in the U.S.**
  इस निर्णय से **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स** की **कीमतें स्थिर** रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनका निर्माण **अमेरिका में बहुत कम होता है**।

- **U.S. Customs and Border Protection** announced that **smartphones, laptops, hard drives, flat-panel monitors**, and some **semiconductor chips** will be **exempt**.

PATRIOTIC IAS

यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने घोषणा की कि **स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, फ्लैट-पैनल मॉनिटर** और कुछ **सेमीकंडक्टर चिप्स** को **छूट** दी जाएगी।

- **Machines used to make semiconductors** are **not included** in the exemption list.
  सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनों को **छूट सूची में शामिल नहीं** किया गया है।

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

Experts share insights on spinal health and its impact on human well-being

GS Paper III: S&T

The Hindu Bureau
CHENNAI

As part of the "Healthy India, Happy India" initiative, a webinar titled "Healthy Spine, Healthy Life" was organised by Naruvi Hospitals, Vellore, in collaboration with *The Hindu*. The session brought together three expert doctors who shared insights into spinal health and its vital role in overall well-being.

Boopesh P., consultant, neurosurgery, Naruvi Hospitals, focused on workplace ergonomics. "Spinal health is essential for maintaining overall quality of

life," he noted, adding that caring for the spine positively influences physical, mental, and emotional health. He identified key ergonomic risk factors such as poor posture, repetitive strain, excessive force, and compression. Dr. Boopesh also demonstrated proper desk posture and safe lifting techniques to avoid strain or injury.

Backiaraj D., spine surgeon at Naruvi Hospitals, addressed the factors affecting spine health. "A healthy spine has discs that are cushiony and flexible, enabling smooth movement," he said. He further explained that strong supporting muscles play a vital role in maintaining spinal integrity.

"Maintaining good posture involves aligning the joints, engaging the core, relaxing the shoulders, and ensuring the head and neck are in proper alignment," he noted. He also highlighted that lifestyle habits such as smoking, vaping, and stress can adversely affect spine health.

Vinitha Varghese, consultant, physical medicine and rehabilitation, Naruvi Hospitals, emphasised the importance of exercise for spinal health.

She introduced the Flamingo Test, a simple technique to assess balance by standing on one leg with eyes closed. "There's no ideal age to begin exercising," she said, urging people to first assess their joint mobility and flexibility before starting a fitness routine.

Experts Share Insights on Spinal Health and its Impact on Human Well-being

रीढ़ की सेहत और मानव कल्याण पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों ने साझा की जानकारियां

As part of the "Healthy India, Happy India" initiative, a webinar titled "Healthy Spine, Healthy Life" was organised by Naruvi Hospitals, Vellore, in collaboration with The Hindu.

"हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया" पहल के तहत नारुवी हॉस्पिटल्स, वेल्लोर ने द हिंदू के सहयोग से "हेल्दी स्पाइन, हेल्दी लाइफ" नामक वेबिनार आयोजित किया।

- The session brought together **three expert doctors** who shared insights into **spinal health** and its **vital role** in **overall well-being**.
  इस सत्र में **तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों** ने भाग लिया जिन्होंने **रीढ़ की सेहत** और **समग्र स्वास्थ्य** में इसकी **महत्वपूर्ण भूमिका** पर जानकारी साझा की।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- **Boopesh P.**, consultant in **neurosurgery**, focused on **workplace ergonomics** and said that **spinal health is essential** for maintaining **quality of life**.
  बूपेश पी., जो **न्यूरोसर्जरी सलाहकार** हैं, ने **कार्यक्षेत्र की कार्य सुविधा (एर्गोनॉमिक्स)** पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि **रीढ़ की सेहत** को बनाए रखना **जीवन की गुणवत्ता** के लिए जरूरी है।

- He noted that spinal care positively affects **physical**, **mental**, and **emotional health**.
  उन्होंने बताया कि रीढ़ की देखभाल **शारीरिक**, **मानसिक** और **भावनात्मक स्वास्थ्य** को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

- He identified **poor posture**, **repetitive strain**, **excessive force**, and **compression** as key **ergonomic risk factors**.
  उन्होंने **खराब मुद्रा**, **दोहराया गया तनाव**, **अत्यधिक बल** और **दबाव** को प्रमुख **एर्गोनॉमिक जोखिम कारक** बताया।

- Dr. Boopesh also demonstrated **proper desk posture** and **safe lifting techniques** to avoid **strain or injury**.
  डॉ. बूपेश ने **सही डेस्क मुद्रा** और **सुरक्षित उठाने की तकनीकें** भी दिखाईं जिससे **तनाव या चोट** से बचा जा सके।

- **Backiaraj D.**, spine surgeon at Naruvi Hospitals, explained that a **healthy spine** has **flexible discs** that allow **smooth movement**.
  बैकियाराज डी., जो नारुवी हॉस्पिटल्स में **स्पाइन सर्जन** हैं, ने बताया कि **स्वस्थ रीढ़** में **लचीली डिस्क्स** होती हैं जो **सहज गति** की अनुमति देती हैं।

- He said that **strong supporting muscles** are important for **spinal integrity**.
  उन्होंने कहा कि **मजबूत सहायक मांसपेशियां**, **रीढ़ की मजबूती** बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

- He advised that maintaining **good posture** involves **joint alignment**, **core engagement**, **shoulder relaxation**, and correct positioning of the **head and neck**.
  उन्होंने सुझाव दिया कि **अच्छी मुद्रा बनाए रखने** में **जोड़ों का सही संरेखण**, **कोर मांसपेशियों का उपयोग**, **कंधों का ढीलापन**, और **सिर और गर्दन की सही स्थिति** जरूरी है।

- He also highlighted that **lifestyle habits** like **smoking**, **vaping**, and **stress** negatively affect **spine health**.

PATRIOTIC IAS

उन्होंने यह भी बताया कि **धूम्रपान**, **वेपिंग**, और **तनाव** जैसी **जीवनशैली की आदतें**, **रीढ़ की सेहत** को नुकसान पहुंचाती हैं।

- **Vinitha Varghese**, consultant in **physical medicine and rehabilitation**, emphasised the role of **exercise** in **spinal health**.
  विनीथा वर्गीज, जो **शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास** की सलाहकार हैं, ने **रीढ़ की सेहत** में **व्यायाम** की भूमिका पर ज़ोर दिया।

- She introduced the **Flamingo Test**, a simple balance test by standing on **one leg with eyes closed**.
  उन्होंने **फ्लेमिंगो टेस्ट** पेश किया, जिसमें **एक पैर पर आंखें बंद करके खड़े होकर** संतुलन की जांच की जाती है।

- She stressed that there is **no ideal age** to begin **exercising**, but one should assess **joint mobility** and **flexibility** first.
  उन्होंने जोर देकर कहा कि **व्यायाम शुरू करने की कोई आदर्श आयु नहीं होती**, लेकिन पहले **जोड़ों की गतिशीलता** और **लचीलापन** जांच लेना चाहिए।

PATRIOTIC IAS

GS Paper III: FPIs

FPIs withdraw ₹31,575 crore from equities this month

Foreign investors have pulled out ₹31,575 crore from the country's equity markets so far this month, in the wake of turbulence created by sweeping tariffs imposed by the U.S. on most nations, including India. This came following a net investment of ₹30,927 crore in the six trading sessions from March 21 to 28. This infusion helped reduce the overall outflow for March to ₹3,973 crore, according to data from the depositories. Compared to previous months, this marks a notable improvement. In February, foreign portfolio investors (FPIs) took out ₹34,574 crore, while in January, the outflow was even higher at ₹78,027 crore. This shift in investor sentiment highlights the volatility and evolving dynamics in global financial markets. The total withdrawn by FPIs has reached ₹1.48 lakh crore in 2025. PTI

FPIs Withdraw ₹31,575 Crore from Equities This Month

एफपीआई ने इस महीने शेयर बाजार से ₹31,575 करोड़ की निकासी की

Foreign portfolio investors (FPIs) have withdrawn ₹31,575 crore from the country's equity markets this month due to the turbulence caused by sweeping tariffs imposed by the U.S. on most nations, including India.

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस महीने भारत के शेयर बाजारों से ₹31,575 करोड़ की निकासी की है, जिसका कारण अमेरिका द्वारा अधिकांश देशों पर लागू किए गए व्यापक शुल्क हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

- This withdrawal follows a net investment of ₹30,927 crore in six trading sessions from **March 21 to 28**.
  यह निकासी **21 मार्च से 28 मार्च** तक के छह व्यापार सत्रों में ₹30,927 करोड़ के शुद्ध निवेश के बाद हुई है।

- The infusion of funds in March helped reduce the overall outflow for the month to ₹3,973 crore, according to data from **depositories**.
  मार्च में धन के प्रवाह ने महीने के कुल निकासी को ₹3,973 करोड़ तक कम करने में मदद की है, जो **जमा करने वाले संस्थाओं** से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार है।

- Compared to previous months, this marks a significant improvement. In **February**, FPIs withdrew ₹34,574 crore, while in **January**, the outflow was even higher at ₹78,027 crore.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

पिछले महीनों की तुलना में, यह महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। **फरवरी** में एफपीआई ने ₹34,574 करोड़ की निकासी की, जबकि **जनवरी** में निकासी ₹78,027 करोड़ तक अधिक थी।

- This shift in investor sentiment highlights the **volatility** and **evolving dynamics** in global financial markets.
  निवेशक भावना में यह बदलाव **वैश्विक वित्तीय बाजारों** में **अस्थिरता** और **बदलती परिस्थितियों** को उजागर करता है।

- The total amount withdrawn by FPIs has reached ₹1.48 lakh crore in **2025**.
  2025 में एफपीआई द्वारा निकाली गई कुल राशि ₹1.48 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है।

DRDO tests laser weapon system that can disable missiles and drones

GS Paper III: Defence

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) on Sunday announced the successful trial of the Mk-II(A) Laser-Directed Energy Weapon (DEW) system "mastering the technology of disabling missiles, drones and smaller projectiles".

The success has put India in the exclusive club of nations which have the high-power Laser-DEW system, the DRDO said in a statement.

"Indigenously designed and developed Mk-II(A) DEW system was demonstrated in its entire spectrum of capability by engaging the fixed wing drones at long range, thwarting a multiple drone attack and destroying enemy surveillance sensors and antennae," the statement said.

A view of the Laser-Directed Energy Weapon system developed by the DRDO to shoot down aerial targets in Kurnool. ANI X

"The lightning speed of engagement, the precision and the lethality delivered at the target within few seconds made it the most potent counter drone system."

"Cost of firing it for few seconds is equivalent to the cost of couple of litres of petrol. Therefore, it has the potential to be a long-term and low-cost alternative to defeat the target," the DRDO said.

Detailing the functioning of the system, the statement said once detected by a radar or by its inbuilt Electro Optic (EO) system, laser-DEW can engage targets at the speed of light and use an intense laser beam to cut through the target, leading to structural failure or more impactful results if the warhead is targeted.

This type of cutting-edge weaponry has the potential to revolutionise the battlespace by reducing the reliance on expensive ammunition, while also lowering the risk of collateral damage, it stated. The trial was carried at the National Open Air Range, Kurnool in Andhra Pradesh.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

DRDO Tests Laser Weapon System That Can Disable Missiles and Drones

डीआरडीओ ने मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय करने वाली लेज़र हथियार प्रणाली का परीक्षण किया

On Sunday, the Defence Research and Development Organisation (DRDO) announced the successful trial of the Mk-II(A) Laser-Directed Energy Weapon (DEW) system, mastering the technology to disable missiles, drones, and smaller projectiles.

रविवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने Mk-II(A) लेज़र-डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) प्रणाली के सफल परीक्षण की घोषणा की, जिससे मिसाइलों, ड्रोन और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करने की तकनीक प्राप्त हुई।

- DRDO stated that this success has placed **India** among an **exclusive group of nations** possessing **high-power Laser-DEW systems**.
  डीआरडीओ ने कहा कि इस सफलता ने **भारत** को उन **चुनिंदा देशों** की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास **उच्च-शक्ति वाली लेज़र-DEW प्रणाली** है।

- The **indigenously designed and developed Mk-II(A) DEW system** was demonstrated across its full capabilities, including engaging **fixed-wing drones** at **long range**, neutralising **multiple drone attacks**, and destroying **enemy surveillance sensors and antennae**.
  स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित की गई Mk-II(A) DEW प्रणाली को उसकी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शित किया गया, जिसमें **लंबी दूरी पर फिक्स्ड विंग ड्रोन** पर हमला, **एक साथ कई ड्रोन हमलों** को विफल करना, और **दुश्मन के निगरानी सेंसर व एंटीना** को नष्ट करना शामिल था।

- The system delivered **lightning speed**, **precision**, and **lethality**, making it one of the most **potent counter-drone systems**.
  प्रणाली ने **बिजली जैसी गति**, **सटीकता**, और **घातक प्रभाव** दिखाया, जिससे यह सबसे **प्रभावी ड्रोन रोधी प्रणालियों** में से एक बन गया।

- The **cost of firing** the weapon for a few seconds is **equivalent** to the cost of just **a couple of litres of petrol**, making it a **low-cost and long-term alternative** to defeat

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

targets.
इस हथियार को कुछ सेकंड तक चलाने की **लागत**, मात्र **कुछ लीटर पेट्रोल** की कीमत के बराबर है, जिससे यह **कम लागत और दीर्घकालिक विकल्प** बन जाता है।

- The system uses **radar** or an inbuilt **Electro-Optic (EO) system** to detect targets, then engages them at the **speed of light** using an **intense laser beam**, causing **structural failure** or **impactful destruction** if a **warhead** is hit.
यह प्रणाली लक्ष्यों का पता लगाने के लिए **रडार** या अंतर्निहित **इलेक्ट्रो-ऑप्टिक (EO) प्रणाली** का उपयोग करती है, फिर **प्रकाश की गति** से एक **तीव्र लेज़र बीम** का उपयोग करके हमला करती है, जिससे **संरचनात्मक विफलता** या यदि **वारहेड** को निशाना बनाया जाए तो **विनाशकारी परिणाम** उत्पन्न होते हैं।

- Such **cutting-edge weaponry** can **revolutionise** modern battlefields by reducing dependency on **expensive ammunition** and minimizing the risk of **collateral damage**.
इस प्रकार के **उन्नत हथियार महंगे गोला-बारूद** पर निर्भरता को कम करके और **सहायक क्षति** के जोखिम को घटाकर युद्धक्षेत्रों में **क्रांतिकारी बदलाव** ला सकते हैं।

- The trial was conducted at the **National Open Air Range** in **Kurnool, Andhra Pradesh**.
यह परीक्षण **आंध्र प्रदेश के कुरनूल** स्थित **नेशनल ओपन एयर रेंज** में किया गया।

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

BatEchoMon: India's first automated bat monitoring, detection system

BatEchoMon is programmed to activate at sunset, when bats begin flying, and continuously listens and analyses audio. Its Raspberry Pi microprocessor processes data captured by an ultrasonic detector, isolating bat calls from other noises, and then uses a neural network to identify the species

GS Paper III: S&T

Nikhil Sreekandan

For her PhD research, bat biologist Kadambari Deshpande made overnight recordings of bat echolocation calls in the Western Ghats. A "good night" would generate about 30 GB of data from 11 hours of recording with a bat detector. To process the data, Deshpande would go through several one-minute recordings, scanning every millisecond for bat calls, and make notes on the species and other information on their behaviour and ecology.

"It took me 11 months to process 20 nights of data," Deshpande said. "BatEchoMon can probably give me that in a few hours."

BatEchoMon, short for 'Bat Echolocation Monitoring,' is an autonomous system capable of detecting and analysing bat calls in real-time. It is India's first automated bat monitoring system, developed by Deshpande and Vedant Barje under the guidance of Jagdish Krishnaswamy, at the Long-Term Urban Ecological Observatory in the School of Environment and Sustainability at the Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Bengaluru.

Deshpande is a postdoctoral fellow at the Observatory and the School; Barje, who leads the WildTech Project at the Wildlife Conservation Trust, is a consultant there.

BatEchoMon marks a new chapter for bat research in the country, according to Deshpande. The monitoring system allows scientists who study bats to "go beyond data processing and towards asking interesting questions about bat ecology."

"Not only will it lead to a smoother workflow, it will help people transition to recording bats in different parts of the country, allowing us to gain more insights on the natural history and ecology of different bat species," Rohit Chakravarty, a bat researcher and conservationist at the Nature Conservation Foundation, said.

"I don't know of any device internationally with an inbuilt recording plus call classifying unit. If my knowledge serves me well, BatEchoMon is a milestone in bat research globally."

The bat in the machine

Aside from a recording device, BatEchoMon includes components to record, store, process, and analyse species-wise bat activity on the fly. "In [BatEchoMon], Audiomoth, a popular low-cost ultrasonic detector, has been configured to work as an ultrasonic microphone," Barje said.

BatEchoMon is programmed to activate automatically at sunset, when bats begin flying, and continuously listens and analyses audio. The device's brain is a Raspberry Pi microprocessor, which processes the data captured by Audiomoth. "It first isolates bat calls from other ultrasounds, such as those of insects or anthropogenic and environmental noises. Then the peak frequency and structure of a bat call are analysed to match a known pre-trained model, which helps identify the bat species," Deshpande explained.

"The system uses a [convolutional neural network] based algorithm to do this," Barje added. The output from the device is a spectrogram – a visual representation of the frequencies of an audio signal as it varies with time – of all detected bat calls, along with audio recordings of the portions with just the calls. The system also generates statistical data on which species has been most active through the night, which species was active when, and so on.

"Earlier, all of this needed to be interpreted manually, after painstakingly combing through hours of data," Deshpande said.

The Raspberry Pi and its associated processing components are enclosed in a box measuring 200 mm × 80 mm × 80 mm. Other auxiliary components in the device include a solar panel plus battery and a WiFi communication unit for power supply and data transmission, respectively. In the absence of the sun, the device can last for up to eight days, according to Barje. BatEchoMon also has a modular design, and its battery, charging apparatus, and the level of automation and data relay can be customised to the space it is installed in. But the team was reluctant to reveal more about the setup process.

Kadambari Deshpande and Vedant Barje with two BatEchoMon units. VIVEK HASYAGAR

> Currently, the system can identify six to seven common Indian bat species. Going forward, we would like to include as many bat species as possible

'Suddenly, it became possible'

Bat ecology and acoustics is a nascent field in India, with just a handful of bat researchers recording bat calls and analysing them for ecological studies. Global bat-call databases such as ChiroVox and Xeno-Canto have few recordings submitted by Indians.

Deshpande has been using bat detectors since 2008 and has observed their evolution worldwide. In Europe, she said, detectors equipped with the associated software and reference libraries have saved scientists a lot of time. Since then she has wanted to develop something similar, but customised for the insectivorous bats that are more common in India.

After a chance meeting with fellow researcher Barje, the duo started iterating through numerous designs, different microprocessors, algorithms, and power solutions – before arriving at the current version of BatEchoMon.

The core system of BatEchoMon costs a third of advanced detectors and similar systems, according to Barje. He didn't wish to disclose exact numbers, however.

The main challenge

In the last few months, BatEchoMon has successfully completed pilot tests in an IIHS site in Nashik. The team plans to test it for longer durations and in diverse conditions as well as to beta test the device with select users outside the organisation.

BatEchoMon's primary obstacle is the limited availability of reference libraries for the calls of many bat species. "Currently, the system can identify six to seven common Indian bat species. Going forward, we would like to include as many bat species as possible," Deshpande said.

They also said they hope the device in its present form will be able to identify the species commonly seen in urban, peri-urban, and human-modified forested areas. The main challenge is to create robust training datasets to make good detection models for different species.

Fortunately, collaborations among Indian researchers are improving because of initiatives like the 'State of India's Bats' workshop conducted by the Nature Conservation Foundation and Bat Conservation International, according to Chakravarty.

(Nikhil Sreekandan is an independent journalist. nsreekandan@gmail.com)

THE GIST

BatEchoMon can detect and analyse bat calls in real-time. It is India's first automated bat monitoring system, developed by Kadambari Deshpande and Vedant Barje at the Long-Term Urban Ecological Observatory in Bengaluru

The developers say the system allows scientists to progress towards asking questions about bat ecology, and will help people transition to recording bats in other parts of the country

The output from the device is a spectrogram of all detected bat calls, along with audio of just the calls. The system also generates statistics on which species has been most active. Earlier, all of this needed to be interpreted manually

BatEchoMon: India's First Automated Bat Monitoring and Detection System

BatEchoMon: भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

BatEchoMon is programmed to activate at sunset, when bats begin flying, and continuously listens and analyses audio signals.

BatEchoMon को सूर्यास्त के समय सक्रिय होने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जब चमगादड़ उड़ना शुरू करते हैं, और यह लगातार ऑडियो सिग्नलों को सुनता और विश्लेषण करता है।

- The system uses a **Raspberry Pi microprocessor** to process data captured by an **ultrasonic detector**, isolates **bat calls** from other noises, and uses a **neural network** to identify species.
  यह प्रणाली एक **Raspberry Pi माइक्रोप्रोसेसर** का उपयोग करती है, जो **अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर** द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को प्रोसेस करता है, **चमगादड़ों की आवाजों** को अन्य शोर से अलग करता है, और प्रजातियों की पहचान के लिए **न्यूरल नेटवर्क** का उपयोग करता है।

Data Challenges in Manual Monitoring
मैन्युअल निगरानी में डेटा संबंधी चुनौतियाँ

- For her **PhD research**, bat biologist **Kadambari Deshpande** recorded **overnight echolocation calls** of bats in the **Western Ghats**.
  अपनी **पीएचडी रिसर्च** के लिए चमगादड़ विज्ञानी **कादंबरी देशपांडे** ने **पश्चिमी घाटों** में **चमगादड़ों की रात भर की इकोलोकेशन आवाज़ों** को रिकॉर्ड किया।

- A “good night” would generate about **30 GB** of data from **11 hours** of recording.
  एक "अच्छी रात" में **11 घंटे** की रिकॉर्डिंग से लगभग **30 जीबी** डेटा उत्पन्न होता था।

- Deshpande had to scan **each millisecond** of several one-minute recordings, taking **11 months** to process data from just **20 nights**.
  देशपांडे को कई एक-एक मिनट की रिकॉर्डिंग के **प्रत्येक मिलीसेकंड** को स्कैन करना पड़ता था, जिससे केवल **20 रातों** के डेटा को प्रोसेस करने में **11 महीने** लगते थे।

- **BatEchoMon** can perform this analysis in just **a few hours**.
  BatEchoMon यह विश्लेषण केवल **कुछ घंटों** में कर सकता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

Development and Purpose
विकास और उद्देश्य

- **BatEchoMon**, short for **Bat Echolocation Monitoring**, is an **autonomous system** for real-time detection and analysis of bat calls.
  BatEchoMon, यानी **Bat Echolocation Monitoring**, एक **स्वायत्त प्रणाली** है जो चमगादड़ों की आवाजों का **रीयल-टाइम में पता लगाने और विश्लेषण** करने में सक्षम है।

- It is **India's first automated bat monitoring system**, developed by **Kadambari Deshpande** and **Vedant Barje** under **Jagdish Krishnaswamy** at the **Indian Institute for Human Settlements (IIHS)**, Bengaluru.
  यह **भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली** है, जिसे **कादंबरी देशपांडे** और **वेदांत बार्जे** ने **जगदीश कृष्णास्वामी** के मार्गदर्शन में **बेंगलुरु स्थित भारतीय मानव बसावट संस्थान (IIHS)** में विकसित किया।

- Deshpande is a **postdoctoral fellow** at IIHS, and Barje, who leads the **WildTech Project** at the **Wildlife Conservation Trust**, is a **consultant** at the same institution.
  देशपांडे **पोस्टडॉक्टोरल फेलो** हैं और बार्जे, जो **Wildlife Conservation Trust** में **WildTech परियोजना** का नेतृत्व करते हैं, वहां के **सलाहकार** हैं।

Advantages and Research Impact
लाभ और अनुसंधान पर प्रभाव

- According to Deshpande, BatEchoMon opens new avenues for **bat research** in India.
  देशपांडे के अनुसार, BatEchoMon भारत में **चमगादड़ अनुसंधान** के लिए नए रास्ते खोलता है।

- The system allows researchers to go beyond data processing and explore **ecological behaviour** and **natural history**.
  यह प्रणाली शोधकर्ताओं को **डेटा प्रोसेसिंग** से आगे बढ़कर **पारिस्थितिकी व्यवहार** और **प्राकृतिक इतिहास** पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- **Rohit Chakravarty**, a bat researcher from the **Nature Conservation Foundation**, said the system enables smoother workflows and helps expand bat studies to **different parts of the country**.
  नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन के चमगादड़ शोधकर्ता **रोहित चक्रवर्ती** ने कहा कि यह प्रणाली कार्यप्रणाली को सहज बनाती है और **देश के विभिन्न हिस्सों** में चमगादड़ अध्ययन का विस्तार करने में मदद करती है।

- He also mentioned that there is **no international device** that combines recording and call classification like BatEchoMon, calling it a **global milestone**.
  उन्होंने यह भी कहा कि BatEchoMon जैसा **रिकॉर्डिंग और कॉल क्लासिफिकेशन** वाला **कोई अंतरराष्ट्रीय उपकरण** नहीं है, और इसे **वैश्विक स्तर पर एक उपलब्धि** बताया।

System Design and Functioning
प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली

- Besides a recording device, BatEchoMon has components to **record**, **store**, **process**, and **analyse** species-specific bat activity.
  रिकॉर्डिंग डिवाइस के अलावा, BatEchoMon में **प्रजाति-विशिष्ट चमगादड़ गतिविधियों** को **रिकॉर्ड**, **स्टोर**, **प्रोसेस** और **विश्लेषण** करने के लिए अन्य घटक भी हैं।

- The system uses **Audiomoth**, a low-cost ultrasonic detector, configured to act as an **ultrasonic microphone**.
  यह प्रणाली **Audiomoth**, एक कम लागत वाला अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर, को **अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन** की तरह काम करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है।

- The **Raspberry Pi microprocessor** processes the data captured by Audiomoth.
  Raspberry Pi माइक्रोप्रोसेसर, Audiomoth द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को प्रोसेस करता है।

- It isolates **bat calls** from other **ultrasonic** and **environmental** noises and matches the structure and peak frequency with **pre-trained models** to identify bat species.
  यह अन्य **अल्ट्रासोनिक** और **पर्यावरणीय शोरों** से **चमगादड़ों की आवाजों** को अलग करता है और **पूर्व प्रशिक्षित मॉडल** से तुलना कर प्रजातियों की पहचान करता है।

- A **convolutional neural network (CNN)** based algorithm performs the analysis.
  एक **कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN)** आधारित एल्गोरिदम यह विश्लेषण करता है।

PATRIOTIC IAS

- The output includes **spectrograms** of bat calls, **audio recordings** of call-only segments, and **statistical data** on species activity throughout the night.
  आउटपुट में **चमगादड़ कॉल्स के स्पेक्ट्रोग्राम**, केवल कॉल्स के **ऑडियो रिकॉर्डिंग**, और पूरी रात की **प्रजाति गतिविधि का सांख्यिकीय डेटा** शामिल होता है।

Hardware and Deployment
हार्डवेयर और तैनाती

- The Raspberry Pi and other components are enclosed in a box of size **200 mm × 80 mm × 80 mm**.
  Raspberry Pi और अन्य घटक **200 मिमी × 80 मिमी × 80 मिमी** के एक बॉक्स में रखे गए हैं।

- The device includes a **solar panel with battery** and **WiFi unit** for power and data transmission.
  डिवाइस में **सौर पैनल और बैटरी** तथा डेटा ट्रांसमिशन के लिए **WiFi यूनिट** शामिल हैं।

- In the absence of sunlight, the device can function for up to **eight days**.
  सूरज की रोशनी न होने पर भी यह डिवाइस **आठ दिनों** तक काम कर सकता है।

- The system is **modular**, allowing customisation of **battery**, **charging**, **automation**, and **data relay** according to the deployment space.
  यह प्रणाली **मॉड्यूलर** है, जिससे **बैटरी**, **चार्जिंग**, **स्वचालन**, और **डेटा ट्रांसमिशन** को तैनाती स्थान के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

- However, the team has not disclosed full details of the **setup process**.
  हालांकि, टीम ने **स्थापना प्रक्रिया** के पूरे विवरण साझा नहीं किए हैं।

‘Suddenly, it became possible’
‘अचानक, यह संभव हो गया’

- Bat ecology and acoustics is a **nascent field** in India, with only a few researchers recording and analysing bat calls for ecological studies.
  भारत में चमगादड़ों की पारिस्थितिकी और ध्वनिकी एक **नवोदित क्षेत्र** है, जिसमें केवल कुछ ही शोधकर्ता

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए इनकी ध्वनियों को रिकॉर्ड और विश्लेषण कर रहे हैं।

- Global bat-call databases like **ChiroVox** and **Xeno-Canto** have very few contributions from Indian researchers.
  ChiroVox और **Xeno-Canto** जैसे वैश्विक डेटाबेस में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा बहुत कम रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं।

- Deshpande has been using bat detectors since **2008** and has seen their evolution globally.
  देशपांडे **2008** से बैट डिटेक्टर का उपयोग कर रही हैं और उन्होंने इन उपकरणों के वैश्विक विकास को देखा है।

- In Europe, detectors with software and reference libraries save researchers a lot of time.
  यूरोप में, सॉफ़्टवेयर और संदर्भ पुस्तकालयों से युक्त डिटेक्टर शोधकर्ताओं का **बहुत समय बचाते हैं**।

- Deshpande wanted a similar system for **insectivorous bats**, which are more common in India.
  देशपांडे ऐसा ही सिस्टम भारत में आम पाए जाने वाले **कीटभक्षी चमगादड़ों** के लिए बनाना चाहती थीं।

- After meeting Barje, the two experimented with various **designs**, **microprocessors**, **algorithms**, and **power solutions**.
  बरजे से मुलाकात के बाद, दोनों ने कई **डिज़ाइन**, **माइक्रोप्रोसेसर**, **एल्गोरिद्म**, और **ऊर्जा समाधानों** के साथ प्रयोग किया।

- This led to the current version of **BatEchoMon**.
  इसका परिणाम **BatEchoMon** के वर्तमान संस्करण के रूप में सामने आया।

- BatEchoMon's core system costs only **one-third** of other advanced detectors, though exact figures are undisclosed.
  BatEchoMon की मुख्य प्रणाली की लागत अन्य उन्नत डिटेक्टरों की तुलना में केवल **एक-तिहाई** है, हालांकि सटीक आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

The Main Challenge
मुख्य चुनौती

- In recent months, **BatEchoMon** successfully completed **pilot testing** at an IIHS site in **Nashik**.
  हाल ही में, **BatEchoMon** ने **नासिक** के IIHS स्थल पर **पायलट परीक्षण** सफलतापूर्वक पूरा किया।

- The team now plans to test it in **diverse conditions** and for **longer durations**, including **beta testing** with external users.
  अब टीम इसे **विविध परिस्थितियों** और **लंबी अवधि** के लिए परीक्षण करने की योजना बना रही है, जिसमें बाहरी उपयोगकर्ताओं के साथ **बीटा परीक्षण** शामिल है।

- A major limitation is the **lack of reference libraries** for Indian bat species.
  एक बड़ी सीमा यह है कि भारतीय चमगादड़ प्रजातियों के लिए **संदर्भ पुस्तकालयों की कमी** है।

- Currently, the device can identify only **six to seven** common Indian bat species.
  वर्तमान में, यह डिवाइस केवल **छह से सात** सामान्य भारतीय प्रजातियों की पहचान कर सकती है।

- The goal is to include **as many species as possible** in the future.
  भविष्य में उद्देश्य है कि **जितनी अधिक प्रजातियाँ** संभव हो सकें, उन्हें शामिल किया जाए।

- The team aims to identify species found in **urban**, **peri-urban**, and **human-modified forest** areas.
  टीम का लक्ष्य **शहरी**, **अर्ध-शहरी**, और **मानव-संशोधित वन क्षेत्रों** में पाई जाने वाली प्रजातियों की पहचान करना है।

- The major challenge is building **robust training datasets** to develop effective **detection models**.
  मुख्य चुनौती है कि **मजबूत प्रशिक्षण डेटा सेट** तैयार किए जाएं ताकि प्रभावी **डिटेक्शन मॉडल** विकसित किए जा सकें।

- Collaboration among Indian researchers is improving due to workshops like **'State of India's Bats'**.

PATRIOTIC IAS

भारतीय शोधकर्ताओं के बीच सहयोग **'स्टेट ऑफ इंडियाज़ बैट्स'** जैसे कार्यशालाओं के कारण बेहतर हो रहा है।

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

Saving traditional varieties of seeds

GS Paper III: Environment

Imagine an India where every farmer grows the same handful of crops – wheat, rice, and a few vegetables – while thousands of traditional seed varieties disappear. This is not a distant future; it is happening now.

For centuries, India's seeds of traditional varieties have been the backbone for food security and a key component of the country's rich cultural heritage. While new hybrid varieties have held the promise of high yields, they have come with a cost – greater dependence on chemical fertilisers, water-dependant farming, increased vulnerability to climate shocks, and altered food quality and nutrient content. The irony? At a time when extreme weather events are threatening food production, we are sidelining the very varieties that can withstand droughts, floods, and replenish depleted soils.

Structure of the food system

Even when we know their benefits, why are traditional varieties disappearing? The truth is: the problem is not just about seeds of traditional varieties; it is about how the entire food system is structured, creating issues that make it hard, if not impossible, for traditional seeds to survive. The first issue is of market demand and consumer preferences. Most Indian consumers unknowingly contribute to the loss of traditional seeds. Supermarkets, government food programmes, and households favour high-yielding rice and wheat, sidelining traditional, climate-resilient grains of millets, pulses and indigenous rice varieties. As there is no demand, farmers hesitate to grow these varieties.

The second issue is that unlike hybrid seeds that are mass-produced and sold commercially, traditional seeds rely on community exchange and local conservation. However, India lacks enough well-funded community seed banks to store and conserve these varieties.

Costanza Conti

Policy Research Lead at the M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF)

E.D. Israel Oliver King

Biodiversity Program Director, MSSRF

Rengalakshmi

Executive Director, Area Operations, MSSRF

At a time when extreme weather events are threatening food production, we are sidelining the very varieties that can withstand droughts, floods, and replenish depleted soils

Third, India's agricultural policies have historically promoted high-yielding varieties, in a well-meaning attempt to prioritise food production and boost food security. However, this has inadvertently caused a trade-off in terms of biodiversity and nutritional quality. While initiatives such as the Odisha Millet Mission have attempted to change this, most government subsidies and procurement programmes are slow to catch up. Even agricultural research and development has focused more on increasing productivity of a few crops, rather than focusing on conserving and improving genetic diversity and enhancing climate resilience.

Conservation efforts

While challenges persist, the fight to save India's traditional seed varieties is not lost. Many organisations have been leading the way in conserving and reviving indigenous varieties and neglected crops for over 30 years. For instance, MSSRF's Tribal Agrobiodiversity Centre in Jeypore, Odisha, recently held a national consultation, which brought together different stakeholders and fostered discussion on how to build climate resilient, sustainable, and inclusive seed systems. From this consultation, a road map started to emerge on the way forward.

No single solution will work to save India's seeds of traditional varieties and crops – recognising farmers' knowledge and rights, strengthening community seed bank networks, initiating alternative seed systems to support local crops and varieties, providing market incentives, and promoting policy changes are all actions that must go hand in hand.

For too long, India's research and development efforts have focused on improved/high-yield varieties that prioritise productivity over climate resilience. A shift is needed – one that funds participatory plant breeding programmes where farmers work alongside scientists to share knowledge and develop improved traditional seeds.

Well-funded and easily reachable seed banks are critical to prevent seed losses for farmers. Governments must support the establishment of a network of regional conservation centres to prevent India from losing its genetic heritage forever.

Farmers will not grow crops that they cannot sell. The government must create support systems for processing and marketing and provide financial incentives for traditional crop cultivation, recognising their climate-resilient, environmental and nutrition benefits. Expanding Minimum Support Prices and procurement programmes for including these crops into school meals, hospitals, and ration shops can drive large-scale change.

Ultimately, the battle for traditional crops and varieties will be won in kitchens. Awareness campaigns and branding initiatives should highlight the health and environmental benefits of traditional crops. When consumers demand these such produce, the markets will respond, creating a cycle of production and consumption.

Time for action

India stands at a turning point. Rising cost of farming inputs, climate change, depleting soil health, and unhealthy food consumption make it clear that we cannot afford to rely only on high-yield crop varieties and market preferred crops. The good news? We do not need to choose between food security and sustainability. By investing in seeds of traditional crops and varieties, India can create a sustainable food system that is not just productive but also resilient, nutritious, and aligned with its agricultural heritage. The time for piecemeal solutions is over. We need coordinated national efforts and alliances between diverse stakeholders to restore the balance in our food system.

Saving Traditional Varieties of Seeds

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण

Imagine an India where every farmer grows the same handful of crops like wheat, rice, and a few vegetables, while thousands of traditional seed varieties disappear.

कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर किसान वही कुछ बीज जैसे गेहूं, चावल, और कुछ सब्जियां उगाता है, जबकि हजारों पारंपरिक बीज किस्में गायब हो जाती हैं।

- This is happening now, not in the distant future.
  यह अब हो रहा है, न कि भविष्य में।

- For centuries, India's **traditional seed varieties** have been the backbone of **food security** and a key part of the country's rich **cultural heritage**.
  सदियों से, भारत की **पारंपरिक बीज किस्में खाद्य सुरक्षा** की रीढ़ रही हैं और देश की समृद्ध **संस्कृतिक धरोहर** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- New hybrid varieties promise **high yields**, but they come with costs: greater dependence on **chemical fertilisers**, **water-dependent farming**, increased vulnerability to **climate shocks**, and changes in food quality and **nutrient content**.
  नई हाइब्रिड किस्में **उच्च पैदावार** का वादा करती हैं, लेकिन इसके साथ लागतें जुड़ी हैं: **रासायनिक उर्वरकों** पर अधिक निर्भरता, **जल-निर्भर कृषि**, **जलवायु संकटों** के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता, और खाद्य गुणवत्ता तथा **पोषक तत्वों की सामग्री** में बदलाव।

- The irony is that at a time when extreme weather events threaten food production, we are sidelining the very varieties that can withstand **droughts**, **floods**, and **replenish depleted soils**.
  विडंबना यह है कि जब चरम मौसम घटनाएं खाद्य उत्पादन को खतरे में डाल रही हैं, हम उन्हीं किस्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो **सूखा**, **बाढ़**, और **खाली पड़े मिट्टी को पुनः भरने** की क्षमता रखती हैं।

Structure of the Food System
खाद्य प्रणाली की संरचना

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Even though we know the benefits of **traditional seed varieties**, they are disappearing due to the structure of the entire **food system**.
  हालांकि हम **पारंपरिक बीज किस्मों** के लाभ जानते हैं, वे **खाद्य प्रणाली** की संरचना के कारण गायब हो रही हैं।

- The first issue is **market demand** and **consumer preferences**.
  पहली समस्या **बाजार की मांग** और **उपभोक्ता की प्राथमिकताएं** हैं।

- Most Indian consumers unknowingly contribute to the loss of traditional seeds by favouring **high-yielding rice** and **wheat** in supermarkets, **government food programmes**, and households, sidelining **climate-resilient grains** like **millets**, **pulses**, and **indigenous rice varieties**.
  अधिकांश भारतीय उपभोक्ता **सुपरमार्केटों**, **सरकारी खाद्य कार्यक्रमों**, और घरों में **उच्च पैदावार वाले चावल** और **गेहूं** को प्राथमिकता देकर पारंपरिक बीजों के नुकसान में अनजाने में योगदान करते हैं, और **जलवायु-प्रतिरोधी अनाजों** जैसे **बाजरा**, **दालें**, और **देशी चावल की किस्मों** को नजरअंदाज करते हैं।

- Without demand, farmers hesitate to grow these **traditional varieties**.
  मांग न होने पर, किसान इन **पारंपरिक किस्मों** को उगाने में संकोच करते हैं।

- The second issue is that traditional seeds depend on **community exchange** and local conservation, whereas hybrid seeds are mass-produced and commercially sold.
  दूसरी समस्या यह है कि पारंपरिक बीज **समुदाय के आदान-प्रदान** और स्थानीय संरक्षण पर निर्भर करते हैं, जबकि हाइब्रिड बीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और वाणिज्यिक बिक्री होती है।

- India lacks **well-funded community seed banks** to store and conserve traditional seeds.
  भारत में पारंपरिक बीजों को संग्रहित और संरक्षित करने के लिए **अच्छी तरह से वित्त पोषित सामुदायिक बीज बैंक** की कमी है।

- Third, India's agricultural policies have historically promoted **high-yielding varieties**, focusing on food production and food security, which has inadvertently caused a **trade-off** in **biodiversity** and **nutritional quality**.
  तीसरी बात, भारत की कृषि नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से **उच्च पैदावार वाली किस्मों** को बढ़ावा दिया है, जो खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित हैं, जिसके कारण अनजाने में **जैव विविधता** और **पोषण गुणवत्ता** में **संतुलन** बन गया है।

PATRIOTIC IAS

- While initiatives like **Odisha Millet Mission** aim to address this issue, most government subsidies and procurement programmes have been slow to adapt.
  जबकि **ओडिशा बाजरा मिशन** जैसी पहलों का उद्देश्य इस समस्या को हल करना है, अधिकांश सरकारी सब्सिडी और खरीद कार्यक्रमों ने इसे अपनाने में धीमी गति दिखाई है।

- Agricultural research and development has focused more on increasing the **productivity of a few crops**, rather than conserving and improving **genetic diversity** and **climate resilience**.
  कृषि अनुसंधान और विकास ने कुछ फसलों की **उत्पादकता बढ़ाने** पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, बजाय इसके कि **जैविक विविधता** और **जलवायु लचीलापन** को संरक्षित और सुधारने पर।

Conservation Efforts
संरक्षण प्रयास

- Despite challenges, efforts to save India's **traditional seed varieties** are ongoing.
  चुनौतियों के बावजूद, भारत की **पारंपरिक बीज किस्मों** को बचाने के प्रयास जारी हैं।

- Several organizations have been working for over **30 years** to conserve and revive **indigenous varieties** and neglected crops.
  कई संगठन **30 वर्षों** से अधिक समय से **देशी किस्मों** और उपेक्षित फसलों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं।

- For example, **MSSRF's Tribal Agrobiodiversity Centre** in **Jeypore**, Odisha, recently held a national consultation to discuss building **climate-resilient**, sustainable, and inclusive seed systems.
  उदाहरण के लिए, **MSSRF का आदिवासी कृषि जैव विविधता केंद्र जेयपुर**, ओडिशा में हाल ही में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया, जिसमें **जलवायु-लचीले**, सतत और समावेशी बीज प्रणालियों पर चर्चा की गई।

- A **road map** emerged from this consultation for the way forward.
  इस परामर्श से आगे के रास्ते के लिए एक **राहनिर्देश** उभरा।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Saving India's traditional seeds will require **recognising farmers' knowledge and rights**, strengthening community seed bank networks, creating **alternative seed systems**, and providing **market incentives**.
  भारत के पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए **किसानों के ज्ञान और अधिकारों को पहचानना**, सामुदायिक बीज बैंक नेटवर्क को मजबूत करना, **वैकल्पिक बीज प्रणालियाँ** बनाना और **बाजार प्रोत्साहन** प्रदान करना आवश्यक होगा।

- The focus should shift to **participatory plant breeding programmes**, where farmers work alongside scientists to improve traditional seeds.
  ध्यान **भागीदार पौध प्रजनन कार्यक्रमों** पर होना चाहिए, जहां किसान वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पारंपरिक बीजों में सुधार करें।

- Well-funded and accessible **seed banks** are critical to prevent seed losses for farmers.
  अच्छी तरह से वित्त पोषित और सुलभ **बीज बैंक** किसानों के लिए बीजों के नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- Governments must support the establishment of a network of **regional conservation centres** to preserve India's **genetic heritage**.
  सरकारों को भारत की **जैविक धरोहर** को संरक्षित करने के लिए **क्षेत्रीय संरक्षण केंद्रों** के नेटवर्क की स्थापना का समर्थन करना चाहिए।

- Farmers will not grow crops they cannot sell, so the government must create **support systems for processing and marketing** and provide **financial incentives** for traditional crop cultivation.
  किसान उन फसलों को नहीं उगाएंगे जिन्हें वे बेच नहीं सकते, इसलिए सरकार को **प्रसंस्करण और विपणन के लिए समर्थन प्रणाली** बनानी चाहिए और पारंपरिक फसल उगाने के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करना चाहिए।

- Expanding **Minimum Support Prices** and procurement programmes for traditional crops can drive **large-scale change**.
  पारंपरिक फसलों के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य** और खरीद कार्यक्रमों का विस्तार **वृहद स्तर पर परिवर्तन** ला सकता है।

PATRIOTIC IAS

Time for Action
कार्रवाई का समय

- India faces rising costs of farming inputs, **climate change**, depleting **soil health**, and unhealthy food consumption, making it clear that relying only on **high-yield varieties** and market-preferred crops is unsustainable.
  भारत **कृषि इनपुट्स** की बढ़ती लागत, **जलवायु परिवर्तन**, घटती **मिट्टी की सेहत**, और अस्वस्थ खाद्य उपभोग का सामना कर रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि केवल **उच्च पैदावार वाली किस्मों** और बाजार-प्राथमिकता वाली फसलों पर निर्भर रहना अस्थिर है।

- The good news is that India does not have to choose between **food security** and **sustainability**.
  अच्छी खबर

PATRIOTIC IAS

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/patrioticIAS
YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/@PatrioticIAS
CONTACT: 9971932488

Will Trump's tariffs bring in a recession?

U.S. President Trump declared on April 2 that the U.S. would henceforth be charging a minimum of 10% tariff on all its imports. While the markets recoiled with horror at the scale of the tariff increases, China has vowed to 'fight till the end' in what may turn out to be a prolonged and bitter trade war

GS Paper III: External Sector

Jayan Jose Thomas

The U.S. has been the greatest champion of free trade and the chief architect of globalisation since the middle of the 20th century. However, in a stunning reversal of roles, U.S. President Donald Trump unleashed a carpet bombing of the global trading system on April 2, which he declared as "Liberation Day".

The U.S. tariff, or the tax America levies on imports from other countries, was 2 to 3% for two decades until 2024 (Chart 1). However, President Trump declared on April 2 that the U.S. would henceforth be charging a minimum of 10% tariff on all its imports. Imports from about 60 countries will have a significantly higher-level tariff – which is being described as "reciprocal" tariffs. These include tariffs of 20% on the European Union (EU), 27% on India, and 46% on Vietnam.

Tariffs of 25% were imposed in February itself on Mexico and Canada, the U.S.'s neighbours and two of its largest trading partners. But the biggest jolt has been the tariff imposed on China, which supplies one-sixth of all foreign goods the U.S. consumes. Imports from China to the U.S., as of April 11, will now face tariffs of 145% (Table 1).

The markets recoiled with horror at the scale of the tariff increases and their uncertainty. Stock markets nosedived. China has retaliated, returning each tariff blow with equal ferocity. It has imposed 125% tariffs on imports from the U.S. There is a distinct possibility that the U.S. and the world are heading towards a painful economic recession. On April 9, President Trump reversed some of his decisions, announcing a 90-day pause on "reciprocal" tariffs for most countries while insisting that the steep tariffs on China would take immediate effect.

A commodity with a price tag of $100 imported from (say, Vietnam) would have cost $103 in the U.S. market if tariffs were 3%. However, the same good must be purchased for $146 when the newly announced tariffs take effect. Tariffs protect domestic industries from foreign competition but may lead to price increases.

'Make America Great Again'

With its high per capita income and low tariffs, the U.S. has been the largest export market for goods from cars to computers, aiding the creation of manufacturing jobs in several countries. In 2022, China exported goods worth $576 billion to the U.S., but the U.S., in return, could sell only $154 billion worth of goods to China (Table 2). Overall, the U.S. had a trade deficit of $1,311 billion, or 5% of its gross domestic product (GDP), in 2022. America has managed to continue buying more from the world than what it sells because of the dollar's position as the dominant international currency. That is primarily thanks to China, which continues to back dollar-denominated assets, storing significant portions of its large export surpluses in U.S. treasury bonds. Such a mutually beneficial relationship between the two largest economic powers has been the key driver of the globalisation of trade and finance since the 2000s.

However, globalisation creates inequalities not only in the developing but also in the developed world. In the U.S., sectors such as steel and automobiles have been among the most hit by import competition.

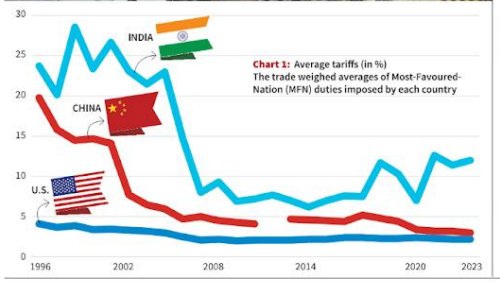

Chart 1: Average tariffs (in %)
The trade weighed averages of Most-Favoured-Nation (MFN) duties imposed by each country

Table 1: U.S. tariffs on selected countries and their export-GDP ratios

	U.S. tariffs (%), as of April 9, 2025	Exports as % of GDP
India	**27***	**21.8**
China	145	19.7
Canada	25	33.4
Mexico	25	36.0
Vietnam	46*	87.2
South Korea	26*	44.0

*Yet to take effect due to the 90-day pause

Table 2: U.S.'s trade with major trading partners in 2022 (in $ billion)

Partner Name	Export	Import	Trade Balance
All countries	2,062	3,373	-1,311
China	154	576	-422
Mexico	324	459	-135
Canada	355	447	-92
Japan	80	154	-74
Germany	73	150	-78
Vietnam	11	136	-124
South Korea	71	121	-49
India	**47**	**91**	**-44**
United Kingdom	77	65	13
Thailand	16	63	-47

Sources: World Integrated Trade Solution (WITS), The World Bank, World Trade Organization STATS, WTO, World Development Indicators, The New York Times.

Trade disruptions ahead: Gantry cranes stand as containers stack below at Brani Terminal, operated by the PSA (Port of Singapore Authority) International Pte, Singapore on April 12. GETTY IMAGES

The resentment of the workers in these sectors – many of whom are white, middle-aged men – has been one of the factors that helped propel Mr. Trump to the U.S. presidency in 2016 and again in 2024. President Trump has promised to revive U.S. manufacturing, protecting it from competitors who, in earlier years, were allowed to "rip off" America with their imports.

Without a doubt, President Trump is playing with fire. With the higher tariffs, prices of most goods, especially consumer goods, will move upward, inflicting pain on ordinary Americans. It is doubtful if American firms can lift their production capabilities to serve at least a part of the demand created for them by making imports costlier.

China's gamble

China has vowed to "fight till the end" in what may turn out to be a prolonged and bitter trade war. Such bravado is backed by the fact that China has been quietly preparing for such a showdown for over a decade, gradually reducing its dependence on the U.S. economy. The proportion of exports to GDP has declined steeply in China, from 35% in 2012 to 19.7% in 2023. As a proportion of its total exports, China's exports to the U.S. have fallen, too, from 21% in 2006 to 16.2% in 2022. China has invested hugely in science, technology, and innovation, particularly in artificial intelligence and electric cars. This has been done partly in response to the U.S.'s restrictions on technology transfer to China. China bypassed U.S. tariffs earlier by shifting production to its East Asian neighbours (especially Vietnam), with which it built deep economic networks.

India's options

President Trump calls India a 'tariff king', referring to the marked increase in India's tariffs since 2018 (Chart 1). The biggest chunk of India's exports is sold to the U.S. ($91 billion in 2022), and they are critical for meeting the country's large import bill. Therefore, any reduction in India's export earnings following tariff escalation will be keenly felt. At the same time, as exports form a relatively small share (21.8%) of its GDP, the impact of the tariff increases may be less in India than in many other countries (Table 1). Also, there has been no increase in tariffs on pharmaceuticals and services, two of India's major export items to the U.S.

The narrowness of its manufacturing capabilities is the biggest hurdle for India. Tariff protection and the Production Linked Incentive Scheme have not been sufficient to revive this sector. India needs a clear-cut industrial policy and a resurgence in investments to escape the unfolding global turmoil.

Jayan Jose Thomas is a Professor of Economics at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi.

THE GIST

- With its high per capita income and low tariffs, the U.S. has been the largest export market for goods from cars to computers, aiding the creation of manufacturing jobs in several countries.
- From now on, imports from about 60 countries will have a significantly higher level tariff — which is being described as "reciprocal" tariffs. These include tariffs of 20% on the European Union (EU), 27% on India, and 46% on Vietnam.
- President Trump calls India a 'tariff king', referring to the marked increase in India's tariffs since 2018.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

क्या ट्रंप के टैरिफ़ मंदी लाएंगे?

On April 2, U.S. President Trump declared a minimum of 10% tariff on all imports.

2 अप्रैल को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी आयातों पर न्यूनतम 10% टैरिफ़ लगाने की घोषणा की।

- Markets recoiled at the scale of tariff increases, and China vowed to "fight till the end" in a possible prolonged trade war.
  बाजार टैरिफ़ बढ़ोतरी के आकार से हैरान हो गए, और चीन ने "आखिर तक लडने" की कसम खाई, जो एक लंबा व्यापार युद्ध बन सकता है।

The U.S. and Its Role in Global Trade
अमेरिका और इसका वैश्विक व्यापार में योगदान

- The U.S. has been the greatest champion of free trade and the chief architect of globalization since the mid-20th century.
  अमेरिका 20वीं सदी के मध्य से मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा समर्थक और वैश्वीकरण का प्रमुख कर्ता रहा है।
- On April 2, President Trump declared a minimum of 10% tariff on all imports.
  2 अप्रैल को, राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी आयातों पर न्यूनतम 10% टैरिफ़ लगाने की घोषणा की।

The Tariff Increases and Their Impact
टैरिफ़ में वृद्धि और इसके प्रभाव

- The U.S. tariff on imports was 2-3% for two decades until 2024.
  2024 तक, अमेरिका का आयातों पर टैरिफ़ 2-3% था, जो दो दशकों तक स्थिर रहा।

- On April 2, President Trump announced a minimum 10% tariff on all imports.
  2 अप्रैल को, राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी आयातों पर न्यूनतम 10% टैरिफ़ लगाने की घोषणा की।

- Imports from 60 countries will have significantly higher tariffs, called "reciprocal tariffs."
  60 देशों से आयातों पर अधिक टैरिफ़ होंगे, जिन्हें "पारस्परिक टैरिफ़" कहा जाएगा।

PATRIOTIC IAS

- The tariffs will be 20% on the European Union, 27% on India, and 46% on Vietnam.
  यूरोपीय संघ पर 20%, भारत पर 27% और वियतनाम पर 46% टैरिफ़ होंगे।

Tariffs Imposed on Neighbors and China
पड़ोसियों और चीन पर टैरिफ़ लागू करना

- Tariffs of 25% were imposed on Mexico and Canada, the U.S.'s neighbors and two of its largest trading partners.
  मेक्सिको और कनाडा, अमेरिका के पड़ोसी और इसके दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर 25% टैरिफ़ लागू किया गया।

- The biggest jolt came with the tariffs on China, which supplies one-sixth of all foreign goods the U.S. consumes.
  चीन पर टैरिफ़ लगाने से सबसे बड़ा झटका लगा, जो अमेरिका द्वारा खपत किए जाने वाले सभी विदेशी सामानों का एक-छठा हिस्सा आपूर्ति करता है।

- Imports from China will face 145% tariffs, effective from April 11.
  चीन से आयातों पर 11 अप्रैल से प्रभावी 145% टैरिफ़ लागू होगा।

Market Reactions and China's Retaliation
बाजार की प्रतिक्रियाएँ और चीन की पलटवार

- Markets recoiled with horror at the scale of tariff increases, causing stock market crashes.
  बाजार टैरिफ़ वृद्धि के आकार से भयभीत हो गए, जिससे स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई।

- China retaliated by imposing 125% tariffs on imports from the U.S.
  चीन ने अमेरिका से आयातों पर 125% टैरिफ़ लगा कर पलटवार किया।

PATRIOTIC IAS

The Possibility of a Recession
मंदी की संभावना

- There is a distinct possibility that the U.S. and the world are heading towards a painful economic recession.
  यह एक स्पष्ट संभावना है कि अमेरिका और पूरी दुनिया एक दर्दनाक आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं।

- On April 9, President Trump reversed some decisions, announcing a 90-day pause on "reciprocal" tariffs for most countries, but keeping tariffs on China.
  9 अप्रैल को, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ फैसले पलटते हुए अधिकांश देशों के लिए "पारस्परिक" टैरिफ़ पर 90 दिन की स्थगन की घोषणा की, लेकिन चीन पर टैरिफ़ बनाए रखा।

Impact on U.S. Consumer Prices
अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों पर प्रभाव

- A commodity priced at $100 from Vietnam will now cost $146 after the new tariffs are imposed.
  वियतनाम से $100 मूल्य का सामान अब नए टैरिफ़ लागू होने के बाद $146 का हो जाएगा।

- Tariffs protect domestic industries but could lead to higher prices.
  टैरिफ़ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

The U.S. Trade Deficit and Globalization
अमेरिका का व्यापार घाटा और वैश्वीकरण

- In 2022, China exported goods worth $576 billion to the U.S., while the U.S. could only sell $154 billion worth of goods to China.
  2022 में, चीन ने अमेरिका को $576 बिलियन मूल्य का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका केवल $154 बिलियन मूल्य का सामान चीन को बेच सका।

- Overall, the U.S. had a trade deficit of $1,311 billion, or 5% of its GDP in 2022.
  कुल मिलाकर, अमेरिका का 2022 में $1,311 बिलियन का व्यापार घाटा था, जो इसके GDP का 5% था।

PATRIOTIC IAS

The Role of the Dollar and China
डॉलर और चीन की भूमिका

- The U.S. has been able to buy more from the world than it sells, due to the dollar's position as the dominant international currency.
  अमेरिका दुनिया से ज्यादा खरीदने में सक्षम रहा है, क्योंकि डॉलर का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रमुख स्थान है।

- China continues to back dollar-denominated assets, storing a significant portion of its large export surpluses in U.S. treasury bonds.
  चीन डॉलर-निर्धारित संपत्तियों का समर्थन करना जारी रखता है, और अपने बड़े निर्यात अधिशेष के महत्वपूर्ण हिस्से को अमेरिकी ट्रेजरी बॉड्स में जमा करता है।

The Impact of Globalization on the U.S.
वैश्वीकरण का अमेरिका पर प्रभाव

- Globalization has created inequalities in both developing and developed worlds.
  वैश्वीकरण ने न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में भी असमानताएँ उत्पन्न की हैं।

- In the U.S., sectors such as steel and automobiles have been most affected by import competition.
  अमेरिका में, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र आयात प्रतिस्पर्धा से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

Trump's Promise to Revive Manufacturing
ट्रंप का निर्माण को पुनर्जीवित करने का वादा

- Trump's election in 2016 and 2024 was partly propelled by the resentment of workers in sectors like steel and automobiles.
  2016 और 2024 में ट्रंप का चुनाव इन क्षेत्रों के श्रमिकों की नाराजगी से प्रेरित था, जैसे स्टील और ऑटोमोबाइल।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- President Trump promised to revive U.S. manufacturing and protect it from competition.
  राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और इसे प्रतिस्पर्धा से बचाने का वादा किया।

The Risks of Higher Tariffs
उच्च टैरिफ़ के जोखिम

- Higher tariffs will likely raise prices of most goods, especially consumer goods, causing pain for ordinary Americans.
  उच्च टैरिफ़ से अधिकांश सामानों, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो साधारण अमेरिकियों पर असर डालेगा।

- It is doubtful if American firms can increase production capabilities to meet the demand created by making imports costlier.
  यह संदेहास्पद है कि क्या अमेरिकी कंपनियां आयातों को महंगा बनाने से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं।

China's Gamble
चीन का जुआ

- China has vowed to "fight till the end" in what may turn out to be a prolonged and bitter trade war.
  चीन ने "आखिर तक लडने" का संकल्प लिया है, जो शायद एक लंबा और कड़वा व्यापार युद्ध साबित हो।

- China has been quietly preparing for this showdown for over a decade, gradually reducing its dependence on the U.S. economy.
  चीन इस संघर्ष के लिए एक दशक से धीरे-धीरे अपनी निर्भरता अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कम कर रहा है।

- The proportion of exports to GDP in China has declined steeply from **35%** in 2012 to **19.7%** in 2023.
  चीन में जीडीपी के मुकाबले निर्यातों का अनुपात 2012 में **35%** से घटकर 2023 में **19.7%** हो गया है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- As a proportion of its total exports, China's exports to the U.S. have fallen from **21%** in 2006 to **16.2%** in 2022.
  चीन के कुल निर्यातों के मुकाबले, 2006 में **21%** से घटकर 2022 में **16.2%** अमेरिकी निर्यातों का हिस्सा रह गया है।

- China has invested heavily in science, technology, and innovation, particularly in **artificial intelligence** and **electric cars**.
  चीन ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **इलेक्ट्रिक कारों** में भारी निवेश किया है।

- This investment has been partly in response to the U.S.'s restrictions on technology transfer to China.
  यह निवेश आंशिक रूप से अमेरिकी द्वारा चीन को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब है।

- China bypassed U.S. tariffs earlier by shifting production to its East Asian neighbors, especially **Vietnam**, with which it built deep economic networks.
  चीन ने पहले **वियतनाम** जैसे अपने पूर्व एशियाई पड़ोसियों में उत्पादन स्थानांतरित कर अमेरिकी टैरिफ़ को पार किया, और उनके साथ गहरे आर्थिक नेटवर्क बनाए।

India's Options
भारत के विकल्प

- President Trump calls India a 'tariff king', referring to the marked increase in India's tariffs since 2018.
  राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ़ किंग' कहा, जो 2018 से भारत के टैरिफ़ में हुई स्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है।

- The biggest chunk of India's exports is sold to the U.S. ($**91 billion** in 2022), critical for meeting the country's large import bill.
  भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को बेचा जाता है (**2022 में $91 बिलियन**), जो देश के बड़े आयात बिल को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- Any reduction in India's export earnings following tariff escalation will be keenly felt.
  टैरिफ़ वृद्धि के बाद भारत की निर्यात आय में कोई भी कमी गहरे प्रभाव डालने वाली होगी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

- Exports form a relatively small share (21.8%) of India's GDP, so the impact of tariff increases may be less than in many other countries.
  भारत की जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा **21.8%** है, इसलिए टैरिफ़ वृद्धि का प्रभाव कई अन्य देशों के मुकाबले कम हो सकता है।

- There has been no increase in tariffs on pharmaceuticals and services, two of India's major export items to the U.S.
  फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं, जो भारत के प्रमुख निर्यात हैं, पर टैरिफ़ में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

- The narrowness of India's manufacturing capabilities is the biggest hurdle for India in this scenario.
  भारत की विनिर्माण क्षमताओं की संकीर्णता इस परिदृश्य में भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

- Tariff protection and the Production Linked Incentive Scheme have not been sufficient to revive this sector.
  टैरिफ़ सुरक्षा और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं रही हैं।

India needs a clear-cut industrial policy and a resurgence in investments to escape the unfolding global turmoil.
भारत को एक स्पष्ट औद्योगिक नीति और निवेशों में पुनरुत्थान की आवश्यकता है, ताकि वह विकासशील वैश्विक उथल-पुथल से बच सके।

PATRIOTIC IAS